राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 5 अंक 29

मूल्य ₹8.00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 9 जुलाई, 2021

www.jagran.com

पृष्ठ 14



भारत में रहने और काम करने वालों को मानने होंगे देश के नियम : अश्विनी

>>3

जागरण विशेष

इस जैविक खाद का दोहरा लाभ, बचे पानी व बढ़े पैदावार



रायपुर : रायपुर के समीप के गांव धमधा के युवा कृषि उद्यमी योगेश कुमार सोनकर ने ऐसी जैविक खाद तैयार की है, जिससे पैदावार 20 फीसद तक बढ़ेगी और 50 फीसद तक पानी की बचत होगी। (पेज-10)

तीसरी लहर से निपटने को 23 हजार करोड़ का पैकेज

तैयारी ▸ बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के साथ ही आक्सीजन व जरूरी दवाओं का होगा भंडारण

स्वास्थ्य के डिजिटल ढांचे को मजबूत कर बेहतर प्रबंधन का किया जाएगा इंतजाम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना की दूसरी लहर की चुनौतियों से सीख लेते हुए सरकार तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए कैबिनेट ने 23 हजार करोड़ रुपये के नए पैकेज को मंजूरी है। इनमें से 15 हजार करोड़ रुपये केंद्र और 8,123 करोड़ रुपये राज्य सरकारें मुहैया कराएंगी। नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को बताया कि इस पैकेज को अगले नौ महीने के भीतर यानी अगले मार्च तक अमली जामा पहना दिया जाएगा। इसके पहले पिछले साल मार्च में 15 हजार करोड़ रुपये का पैकेज दिया गया था।

मंडाविया ने पैकेज की जानकारी देते हुए कहा कि इसके तहत जिला स्तर पर आक्सीजन व जरूरी दवाइयों की आपूर्ति और स्टोरेज से लेकर पर्याप्त संख्या में बिस्तरों की संख्या की बढ़ाने का प्रविधान किया गया है। यही नहीं, तीसरी लहर में बच्चों के अधिक संख्या में प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए सभी जिलों में बच्चों के विशेष वार्ड के निर्माण के साथ ही ऐसे हाईब्रिड आइसीयू बेड का निर्माण भी किया जाएगा, जिनका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर बच्चे और बड़े दोनों कर सकेंगे।

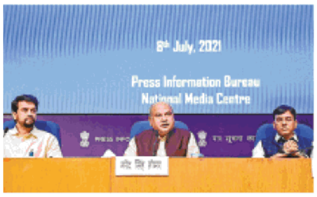
नए पैकेज में बड़े पैमाने पर जिनोम सिक्वेंसिंग प्रणाली तैयार करने के साथ-साथ सभी 736 जिला अस्पतालों को डिजिटल प्लेटफार्म से जोड़ने का भी प्रविधान है। इसके अलावा ई-संजीवनी को मजबूत कर कोरोना काल में लोगों को टेलीमेडिसिन की मदद से भी इलाज उपलब्ध कराने का विकल्प तैयार किया जाएगा। देश में कोरोना के हालात की मानिटरिंग और जरूरत के मुताबिक तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कंट्रोल रूम के साथ-साथ कोविड-19 व कोविन प्लेटफार्म और कोरोना हेल्पलाइन नंबर को मजबूत किया जाएगा।

नौ महीने के भीतर यानी अगले मार्च तक पहना दिया जाएगा अमली जामा

8,800 नई एंबुलेंस खरीदी जाएंगी।

सभी जिला अस्पतालों में बच्चों के वार्ड बनाए जाएंगे।

6,688 कोरोना बेड तैयार होंगे केंद्र सरकार के अस्पतालों में



नई दिल्ली में गुरुवार को कैबिनेट के फैसलों की प्रेस कांफ्रेंस में जानकारी देते केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, अनुराग ठाकुर और मनसुख मांडविया। प्रेट्र

नए पैकेज के तहत देश के सभी जिलों में पीडियाट्रिक केयर यूनिट से लेकर आइसीयू बेड, आक्सीजन स्टोरेज, एंबुलेंस और दवाओं जैसे जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

पैकेज के अहम बिंदु

- सभी 736 जिला अस्पतालों में ई-हास्पिटल या ई-सुश्रुत साफ्टवेयर का इस्तेमाल कर हास्पिटल मैनेजमेंट इंफोरमेशन सिस्टम लगाए जाएंगे। अभी 310 अस्पतालों में ही लगाए गए हैं।
- 2.4 लाख सामान्य मेडिकल बेड और 20 हजार आइसीयू बेड तैयार किए जाएंगे। इनमें 20 फीसद बच्चों के लिए होंगे।
- नेशनल सेंटर फार डिजीज कंट्रोल को जिनोम सिक्वेंसिंग मशीनें दी जाएंगी। साइंटिफिक कंट्रोल रूम व एपेडेमिक इंटेलीजेंस सर्विस का ढांचा बनाया जाएगा।
- ई-संजीवनी प्लेटफार्म को मजबूत कर रोजाना पांच लाख लोगों को टेली कंसल्टेंसी मुहैया कराई जाएगी। अभी 50 हजार लोगों को दी जाती है।
- देशभर में लिक्विड मेडिकल आक्सीजन के 1,050 स्टोरेज बनाए जाएंगे, उन्हें पाइपलाइन से अस्पतालों से जोड़ा जाएगा। हर जिले में एक स्टोरेज जरूर होगा।
- कोरोना के प्रभावी प्रबंधन में अंडर ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंटर्न, अंतिम वर्ष के एमबीबीएस छात्र और बीएससी व जीएनएम के नर्सिंग छात्रों की सेवाएं ली जाएंगी।

एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मजबूत की जा सकेंगी कृषि उपज मंडियां

कैबिनेट का फैसला

▸ कृषि मंत्री तोमर बोले, आंदोलन छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं प्रदर्शनकारी किसान, सरकार है तैयार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कृषि उपज मंडियों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने एक अहम फैसला किया है। इसके तहत देश की कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) के ढांचे को मजबूत बनाने के काम में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का उपयोग किया जा सकेगा। इसकी घोषणा करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि कृषि सुधार कानूनों को लेकर आंदोलनकारी संगठनों की आशंकाएं निराधार साबित हुई हैं। सरकार लगातार मंडियों को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य करती रही। नए कृषि कानून लागू होने के बाद भी ये मंडियां खत्म नहीं होंगी।

कृषि और किसानों के हित में सरकार ने 15 मई, 2020 को एक लाख करोड़ रुपये के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्टर फंड की घोषणा की थी। एक फरवरी, 2021 को सरकार ने इस फंड के उपयोग करने वालों की सूची में एपीएमसी (मंडी) को भी जोड़ दिया। इसे लागू करने के लिए गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। इसके नियमों में कुछ संशोधन भी किए गए हैं ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास में किया जा सके।

कैबिनेट के फैसले की जानकारी देने आए तोमर ने कृषि कानून विरोधी आंदोलन पर पूछे गए सवालों पर कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों को कानून समाप्त करने की जिद छोड़कर वार्ता के लिए आना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरकार उनके हर मसले पर वार्ता को तैयार है। प्रदर्शनकारी किसानों को नए कानूनों की महत्ता को समझना चाहिए, जिसे सारा देश समझ रहा है। तोमर ने कहा कि आंदोलन के बावजूद कृषि उपज की रिकार्डतोड़ खरीद हुई है। आंदोलन में जहां के लोग (पंजाब) ज्यादा शामिल हैं, वहां के किसानों को हजारों करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

न्यूज गैलरी

राष्ट्रीय राजधानी ▸ पृष्ठ 2

अनाज वर्बादी मामले में दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली : पिछले वर्ष लाकडाउन के दौरान गरीबों में बांटने के लिए खरीदे गए अनाज की बर्बादी के मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। दिल्ली सरकार को 23 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति की पीठ ने कहा कि गरीबों के राशन की बर्बादी कम से कम और वितरण ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए।

राष्ट्रीय फलक ▸ पृष्ठ 5

जमीन घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में खडसे से पूछताछ

मुंबई : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधान परिषद सदस्य एकनाथ खडसे ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होने से पहले पत्रकारों से कहा कि उनके परिवार को राजनीतिक कारणों से फंसाया जा रहा है। वह ईडी की जांच में पूरा सहयोग करेंगे। ईडी इससे पहले पुणे के भूखंड घोटाले में उनके दामाद गिरीश चौधरी को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी जमीन घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले की जांच कर रही है।

कोरोना से जंग ▸ पृष्ठ 6

राज्यों और निजी अस्पतालों के पास 1.83 करोड़ से अधिक डोज

नई दिल्ली : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि राज्यों और निजी अस्पतालों में 1.83 करोड़ से अधिक शेष और अप्रयुक्त कोरोना रोधी टीके अभी भी उपलब्ध हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 37.93 करोड़ (37,93,56,790) वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। जल्द ही 23,80,000 और डोज उपलब्ध कराई जाएंगी। देश में टीकाकरण का नया चरण 21 जून से शुरू हुआ है।

राष्ट्रीय फलक ▸ पृष्ठ 10

हिंसा पीड़ितों को शिकायत नहीं कराने की धमकी दे रही पुलिस

कोलकाता : बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच कर रही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम के एक सदस्य ने गुरुवार को कहा, पुलिस पीड़ितों को मामले में शिकायत दर्ज नहीं कराने की धमकी दे रही है। इस दावे के बाद हिंसा की जांच ने एक नया मोड़ ले लिया है। ज्ञात हो, कलकत्ता हाई कोर्ट ने एनएचआरसी की रिपोर्ट के आधार पर दो जुलाई को राज्य पुलिस को सभी हिंसा पीड़ितों की शिकायतों को दर्ज करने का निर्देश दिया था।

पीएम ने सैलानियों को किया आगाह, अभी खत्म नहीं हुआ है कोरोना

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना का प्रकोप कम होते ही मनाली समेत दूसरे पर्यटक स्थलों और बाजारों में उमड़ रही भीड़ ने पीएम नरेंद्र मोदी की चिंता बढ़ा दी है। विस्तार के बाद गुरुवार को मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में उन्होंने इसका जिक्र करते हुए सभी को आगाह किया कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सावधानी जरूरी है और लापरवाही व आत्मसंतोष की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा, सभी मंत्री लोगों को जागरूक करते रहें। साथ ही महाराष्ट्र और केरल में संक्रमण की बड़ी संख्या पर चिंता जताई।

सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट बैठक के बाद करीब दो घंटे चली मंत्रिपरिषद की बैठक में यूं तो गवर्नमेंट फार ग्रोथ पर ही बातें हुईं। लेकिन इसी बीच पीएम ने कोरोना की तीसरी लहर के प्रति भी आगाह किया। उन्होंने कहा, 'कुछ दिनों से हम लोग ऐसे वीडियो और पिक्चर देख रहे हैं जिसमें लोग बिना मास्क और शारीरिक दूरी के भीड़ में घूम रहे हैं। यह अच्छा नहीं है। हमें याद रखना चाहिए कि एक भूल के भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं।' मोदी ने कहा, कोरोना से जंग पूरी ताकत से जारी है। लोगों का लगातार टीकाकरण किया जा रहा है, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। किसी भी चूक के लिए स्थान नहीं है। बहुत से ऐसे देश हैं जहां कोरोना ने फिर से दस्तक देना शुरू कर दिया है। भारत को हर हाल में ऐसी स्थिति से बचना चाहिए।

उन्होंने मंत्रियों से कहा, लोगों में डर पैदा करना मकसद नहीं होना चाहिए, लेकिन वे लोगों से सभी एहतियात बरतने का अनुरोध करें। ध्यान रहे कि कुछ ऐसा ही हाल पहली लहर के थोड़ा कम होने पर हुआ था, जब पूरे देश में सैलानियों की भीड़ इकट्ठी हुई थी। उसी दौरान म्यूटेशन भी हुआ था और डेल्टा वैरिएंट ने कहर बरपाया था।

विस्तार के बाद मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में पर्यटक स्थलों और बाजारों में उमड़ रही भीड़ पर जताई गहरी चिंता



नई दिल्ली में गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एएनआइ

समय पर दफ्तर पहुंचने और बेवजह बयानबाजी से बचने की दी नसीहत

प्रेट्र के मुताबिक, बैठक में पीएम ने नए बने मंत्रियों को सही सोच और लगन के साथ समयबद्ध तरीके से योजनाओं को परवान चढ़ाने की सीख दी। सभी से समय पर कार्यालय पहुंचने, बेवजह बयानबाजी से बचने और पूरी ऊर्जा मंत्री पद के दायित्वों को पूरा करने में लगाने को कहा। मोदी ने कहा, सिर्फ काम ही मायने रखता है। मंत्रियों को मीडिया की चकाचौंध में नहीं फंसना चाहिए। नवनियुक्त मंत्री पूर्ववर्ती मंत्रियों से मुलाकात करें। जो अब सरकार का हिस्सा नहीं है, उन्होंने अपना योगदान दिया है, नए मंत्री उनसे सीख सकते हैं।

टीम मोदी के नए मंत्रियों ने संभाली कमान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के अगले ही दिन टीम मोदी के नए मंत्रियों ने कामकाज संभाल सरकार के एजेंडे को नई गति व तेवर से आगे बढ़ाने के इरादे साफ कर दिए।

सूचना प्रौद्योगिकी, संचार व इलेक्ट्रानिक्स और रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार सुबह ही तीनों मंत्रालयों में जाकर कामकाज संभाल लिया। वैष्णव ने कहा, तीनों मंत्रालयों में काफी एकरूपता है। मोदी सरकार के दूरदर्शी लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में वे अपनी ऊर्जा लगाएंगे। सूचना प्रसारण मंत्री के साथ युवा और खेल मंत्रालय का जिम्मा संभालते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा, वे देश को बड़ी खेल शक्ति के रूप में स्थापित करने की जिम्मेदारी निभाएंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का प्रभार संभालने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, पीएम के आशीर्वाद से वे अपने पिता के सपनों को साकार करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम सभी छात्रों व युवाओं को एक समान शिक्षा देने को प्रतिबद्ध हैं।

भूपेंद्र यादव ने वन व पर्यावरण और श्रम मंत्री का पद संभालते हुए कहा, पीएम के विकास लक्ष्य को हासिल करना ही प्राथमिकता होगी। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, इस जिम्मेदारी में चुनौतियां हैं तो मौके भी हैं। इनके अलावा पुरुषोत्तम रुपाला ने पशुपालन व डेयरी, जी किशन रेड्डी ने पर्यटन व संस्कृति मंत्रालय संग पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय में कामकाज शुरू कर दिया।

...तो उप्र में दो संतान वाले ही पाएंगे सरकारी सुविधाएं

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- जनसंख्या नियंत्रण को लेकर योगी सरकार को राज्य विधि आयोग की सिफारिशों का इंतजार
- आयोग इसी माह संस्तुति रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर सरकार को सौंपेगा
- मुख्यमंत्री बोले, विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी



योगी आदित्यनाथ। फाइल

यह है आयोग के ड्राफ्ट में : दो बच्चे तक ही होने पर सरकारी कर्मियों को इन्क्रीमेंट और प्रमोशन का भी लाभ मिलेगा।

जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक ओर जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के जरिये लोगों को दो ही बच्चे पैदा करने के लिए जागरूक करने की व्यापक तैयारी की है, वहीं उसे राज्य विधि आयोग की इस संबंध में सिफारिशों का इंतजार है। आयोग, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा तैयार कर रहा है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आयोग इसी माह अपनी संस्तुति रिपोर्ट को अंतिम रूप देते हुए सरकार को सौंप देगा। आयोग ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है, उससे साफ है कि अगर सरकार ने उसकी सिफारिशें मानीं तो दो बच्चे वालों को ही तमाम तरह के सरकारी लाभ व सहूलियतें मिलेंगी। वैसे प्रस्तावित कानून को हरी झंडी मिलने से एक वर्ष बाद ही प्रभावी होगा। दो बच्चे तक ही होने पर सरकारी कर्मियों को इन्क्रीमेंट और प्रमोशन का भी लाभ मिलेगा।

गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि प्रदेश के विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि की दर को नियंत्रित करना जरूरी है। सभी नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से जनसंख्या को नियंत्रित करना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 का प्रस्तुतिकरण देखने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंख्या को नियंत्रित करके बेहतर कल की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नीति में जनसंख्या वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जनसामान्य को जागरूक किये जाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए सतत कार्यक्रम चलाए जाएं।

जनसंख्या का स्थिरीकरण बेहद जरूरी : उन्होंने कहा कि स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए जनसंख्या का स्थिरीकरण बेहद जरूरी है। ऐसा करके बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है।

'दिल्ली विस कर सकती है दंगों की जांच, पर अभियोजक एजेंसी की तरह नहीं'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसीडेंट और एमडी अजीत मोहन की याचिका खारिज की

▸ अजीत मोहन ने दिल्ली विस की शांति और सौहार्द समिति के नोटिस को दी थी चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली विधानसभा को 2020 के दिल्ली दंगों की जांच करने के लिए कमेटी गठित करने का अधिकार है, लेकिन साथ ही साफ किया कि कमेटी अभियोजक एजेंसी की भूमिका नहीं निभा सकती। कमेटी को कानून-व्यवस्था और पुलिस के क्षेत्र में आने वाले किसी भी पहलू का अतिक्रमण करने की इजाजत नहीं है। ऐसे में फेसबुक प्रतिनिधि को इन विषयों से संबंधित सवालों का उत्तर नहीं देने का अधिकार है। इसके साथ ही कोर्ट ने फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसीडेंट और एमडी अजीत मोहन की याचिका खारिज कर दी। अजीत मोहन ने दिल्ली दंगों की जांच कर रही दिल्ली विधानसभा की शांति और सौहार्द कमेटी के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कमेटी ने गवाह के तौर पर पेश नहीं होने पर अजीत मोहन को नोटिस भेजा था।

इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान समय में इंटरनेट मीडिया के महत्व, भूमिका व प्रभाव को आदेश में दर्ज किया और कहा कि फेसबुक इस मुद्दे से हाथ नहीं झाड़ सकता। इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उनकी कोई भूमिका नहीं है। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के तल्ख रिश्तों पर भी कहा कि अच्छी तरह काम करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर चलना चाहिए।

अजीत मोहन की याचिका प्री-मैच्योर है : कोर्ट पेज>>5

पुलवामा और कुलगाम में चार आतंकी ढेर

श्रीनगर : सुरक्षाबल के जवानों ने दक्षिण कश्मीर में गुरुवार तड़के पुलवामा और कुलगाम में हुई दो मुठभेड़ों में लश्कर-ए-तैयबा के चार आतंकियों को मार गिराया। कुलगाम में मारे गए दोनों आतंकी जवानों पर आत्मघाती हमले की साजिश को अंजाम देने वाले थे। जवानों ने हंदवाड़ा में बुधवार को भी हिजबुल के दुर्दांत आतंकी मेहराजुदीन हलवाई को मार गिराया था। (पेज 5)

गूगल पर 36 अमेरिकी राज्यों ने किया मुकदमा

वाशिंगटन : इंटरनेट सर्च इंजन गूगल के खिलाफ अमेरिका के 36 राज्यों और जिले कोलंबिया ने संघीय अदालत में मुकदमा दर्ज किया है। गूगल पर आरोप है कि उसने अपने मोबाइल एप स्टोर का दुरुपयोग करते हुए अपने बाजार की शक्ति को बढ़ाया है। साफ्टवेयर डेवलपर्स कड़े नियम-शर्तों के तहत गूगल की मनमानियों के कारण कानूनी चुनौतियों का शिकार हो रहे हैं। (पेज 11)

ग्लोबल वार्मिंग

जलवायु परिवर्तन से पड़ रही ज्यादा गर्मी व सर्दी, जर्नल लैंसेट में प्रकाशित अध्ययन में किया गया दावा

असामान्य तापमान से देश में सालाना 7 .4 लाख मौतें

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारत में असामान्य सर्दी और गर्मी के चलते हर साल लगभग 7,40,000 लोगों की मौत हो जाती है। लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया में अत्यधिक सर्दी और गर्मी पड़ रही है।

आस्ट्रेलिया स्थित मोनाश यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया कि असामान्य तापमान के चलते दुनियाभर में हर साल 50 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है। बुधवार को प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि वर्ष 2000 से 2019 के बीच दुनिया के सभी क्षेत्रों में गर्मी के चलते होने वाली मौत की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। इससे यह संकेत भी मिलता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली ग्लोबल वार्मिंग से भविष्य में मौत की संख्या और बढ़ेगी।

शोधकर्ताओं का कहना है कि भारत में हर साल असामान्य सर्दी से 6,55,400 लोगों की मौत होती है, जबकि अत्यधिक गर्मी की वजह से 83,700 लोगों को जान गंवानी पड़ती है।

- असामान्य तापमान से दुनियाभर में हो रहीं 50 लाख से ज्यादा मौतें
- हर दशक में वैश्विक तापमान में 0.26 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतर्री



उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भीषण गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए गमछा ओढ़कर जाते युवक। जागरण

पूर्वी यूरोप व अफ्रीका में सर्वाधिक मौत : आंकड़ों के मुताबिक, मृत्यु दर पर असामान्य तापमान का भौगोलिक अंतर भी दिखाई देता है। पूर्वी यूरोप और अफ्रीका के उप-सहारा रेगिस्तान में अत्यधिक सर्दी और गर्मी के चलते सर्वाधिक मौतें होती हैं।

शोधकर्ताओं की टीम ने वर्ष 2000 से लेकर 2019 के बीच दुनियाभर में मौत और तापमान के आंकड़ों का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला है। इस अवधि के दौरान हर दशक में वैश्विक तापमान में 0.26 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

गर्मी के चलते होने वाली मौतों में बढ़ोतरी होगी: अध्ययन के अनुसार, वैश्विक मौत के 9.43 प्रतिशत हिस्से के लिए असामान्य सर्दी और गर्मी जिम्मेदार है। शोधकर्ताओं का कहना है कि प्रति 1,00,000 लोगों में 74 लोगों की मौत अत्यधिक सर्दी के चलते होती है। मोनाश यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर यूमिंग गुओ ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते मुख्यतः ठंड से होने वाली मृत्यु दर में कमी आ सकती है। हालांकि, लंबे समय तक जलवायु परिवर्तन जारी रहने से गर्मी के चलते होने वाली मौतों में बढ़ोतरी होगी।

फ्रांसीसी कोर्ट ने केयर्न को दी पेरिस में भारतीय संपत्तियां जब्त करने की इजाजत

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारत के साथ कर विवाद में फ्रांस के कोर्ट ने ब्रिटेन की केयर्न एनर्जी पीएलसी के पक्ष में फैसला दिया है। उसने केयर्न को पेरिस स्थित भारत सरकार की करीब 20 संपत्तियां जब्त करने की इजाजत दी है। मध्यस्थता अदालत ने केयर्न को 1.7 अरब अमेरिकी डालर (करीब 12,600 करोड़ रुपये) का हर्जाना वसूलने का अधिकार दिया था। इसी आदेश के तहत फ्रांसीसी अदालत ने उक्त इजाजत दी है।

फ्रांसीसी अदालत ने 11 जून को केयर्न एनर्जी को भारत सरकार की संपत्तियों के अधिग्रहण का आदेश दिया था, जिनमें ज्यादातर फ्लैट शामिल हैं। भारत सरकार इन फ्लैट का इस्तेमाल फ्रांस में अपने अधिकारियों के लिए करती है। भारतीय अधिकारियों से इन फ्लैट को खाली करवाने की संभावना भी नहीं है। भारत सरकार इन फ्लैट को बेच नहीं सकेगी।

1.7 अरब डालर हर्जाना वसूलने का आदेश दिया था केयर्न को मध्यस्थता अदालत ने

- भारत सरकार के फैसला स्वीकार नहीं करने पर केयर्न संपत्ति की वसूली के लिए गई थी कोर्ट

नहीं मिला कोई नोटिस : भारत सरकार का कहना है कि उसे इस बारे में फ्रांस की किसी भी अदालत से कोई नोटिस या आर्डर नहीं मिला है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार इस बारे में तथ्यों की जांच कर रही है। अगर इस तरह का कोई नोटिस मिलता है तो उस पर वकीलों से राय मशविरा करके भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित कानूनी कदम उठाया जाएगा।

न्यायाधिकरण ने दिसंबर में दिया था आदेश

तीन सदस्यीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने पिछले साल दिसंबर में सर्वसम्मति से केयर्न पर पिछली तारीख से लगाए गए करों को रद कर दिया था। इस न्यायाधिकरण में एक भारत द्वारा नियुक्त जज भी थे। न्यायाधिकरण ने करों की वसूली के लिए बिक्री किए गए शेयरों, जब्त किए गए लाभांश और रोके गए टैक्स रिफंड का भुगतान करने का आदेश दिया था। भारत सरकार ने इस आदेश को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद केयर्न एनर्जी ने भारत सरकार की संपत्तियों को जब्त करके देय राशि की वसूली के लिए विदेश में कई न्यायालयों में अपील की थी। पांच देशों की अदालतों ने केयर्न के पक्ष में आए ट्रिब्यूनल (पर्मानेंट कोर्ट आफ आर्बिट्रेशन) के फैसले पर मुहर लगा दी थी। इनमें अमेरिका और इंग्लैंड का अदालतें भी शामिल थीं।

1,799 अनधिकृत कालोनियां हैं दिल्ली में। जल बोर्ड के अनुसार 1,631 कालोनियों में पानी की पाइपलाइन पहुंच चुकी है, लेकिन जलापूर्ति 1,573 कालोनियों में ही हो रही है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 9 जुलाई, 2021

न्यूज गैलरी

स्वानंद किरकिरे बने दिल्ली हिंदी अकादमी के उपाध्यक्ष

नई दिल्ली : दिल्ली के उपमुख्यमंत्री एवं दिल्ली हिंदी अकादमी के अध्यक्ष मनीष सिसोदिया ने बृहस्पतिवार को अकादमी की पहली गवर्निंग बाडी बैठक में मशहूर लेखक और गीतकार स्वानंद किरकिरे को दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया।



स्वानंद किरकिरे। सौ.दिल्ली सरकार

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि स्वानंद किरकिरे के अनुभवों से अकादमी को भाषा और संस्कृति का प्रसार करने में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना की चुनौतियों ने हमें अकादमी के कामकाज पर नए सिरे से सोचने का अवसर दिया है। अब यह भी आवश्यक है कि अकादमी को अपने कार्यक्रमों के स्वरूप को उसके अनुसार बदलना होगा। (राब्यू)

सीबीआइ मुख्यालय के बेसमेंट में लगी आग

नई दिल्ली : लोधी कालोनी के सीजीओ कांप्लेक्स स्थित सीबीआइ मुख्यालय की बिल्डिंग में बृहस्पतिवार सुबह आग लग गई इससे पूरी बिल्डिंग में धुआं फैल गया। दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल गर्ग ने बताया कि आग बिल्डिंग के सेकेंड बेसमेंट में स्थित एसी प्लांट रूम के इलेक्ट्रिक केबल व ट्रांसफार्मर में शार्ट सर्किट के कारण लगी थी। दमकल विभाग की सात गाड़ियां मौके पर भेजी गई थीं, जिन्होंने थोड़ी देर में आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। (जासं)

नजफगढ़-ढांसा बस स्टैंड तक मेट्रो परिचालन के लिए तैयार

नई दिल्ली : ग्रे लाइन पर नजफगढ़ से ढांसा बस स्टैंड तक नवनिर्मित कारिडोर मेट्रो परिचालन के लिए तैयार है। बुधवार को मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) ने कारिडोर के सुरक्षा मानकों का निरीक्षण किया। इस दौरान मेट्रो के ट्रैक, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल रूम व प्लेटफार्म की तकनीकी जांच में कोई खामी नहीं पाई गई। इसके बाद सीएमआरएस से मेट्रो परिचालन के लिए डीएमआरसी को हरी झंडी मिल गई है। सिर्फ परिचालन की तारीख की घोषणा होने का इंतजार है। (राब्यू)

डीयू अगस्त माह में जारी करेगा ओबीई का परिणाम

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष के छात्रों की ओपन बुक परीक्षा जून महीने में संपन्न हुई है। डीयू 15 अगस्त तक सभी छात्रों का परीक्षा परिणाम जारी करने की कवायद में जुट गया है। यह संभव होगा डीयू द्वारा शिक्षकों के प्रोत्साहन की बदौलत। डीयू के अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि परीक्षा के साथ ही मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। (जासं)

अनाज बर्बादी मामले में दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट का नोटिस

आरोप ▶ लाभार्थियों को भोजन के अधिकार से रखा गया वंचित

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

पिछले वर्ष लाकडाउन के दौरान गरीबों में बांटने के लिए खरीदे गए अनाज की बर्बादी के मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। दिल्ली सरकार को 23 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति की पीठ ने कहा कि गरीबों के राशन की बर्बादी कम से कम और वितरण ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए।

गैर सरकारी संगठन संपूर्णा ने जनहित याचिका दायर कर राशन वितरण में गंभीर गड़बड़ियों के आरोप लगाए हैं और अदालत से इस संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश तैयार कराने की मांग की है। अधिवक्ता प्रशांत रावत के माध्यम से दायर याचिका में एनजीओ ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर सकी। याचिका के अनुसार, अप्रैल 2020 में दिल्ली सरकार ने गैर राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न और सूखा राशन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना शुरू की थी। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में राशन खरीदा गया, लेकिन दिल्ली सरकार बड़े पैमाने पर लाभार्थियों को राशन किट और खाद्यान्न के वितरण में बुरी तरह विफल रही। इसके कारण बाजार मूल्य पर खरीदा गया अनाज गरीबों को वितरित नहीं होने के कारण पड़े-पड़े बर्बाद हो गया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अनाज की बर्बादी के कारण न सिर्फ लाभार्थियों को भोजन के मौलिक अधिकार से वंचित रखा गया, बल्कि बिना किसी गलती के जनता पर भारी वित्तीय बोझ भी डाल दिया गया।



▶ एनजीओ संपूर्णा ने जनहित याचिका दायर कर लगाया है राशन वितरण में गंभीर लापरवाही का आरोप

▶ अदालत ने कहा, गरीबों के राशन की बर्बादी कम से कम और वितरण ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए

यह है मामला

दैनिक जागरण ने अनाज की बर्बादी मामले को 29 मई, 2021 को उजागर किया था। इसमें कई स्कूलों में सड़ा हुआ अनाज मिला था। राशन बर्बादी के लगातार समाने आ रहे हैरान करने वाले मामलों को देखते हुए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बीते माह यानी नौ जून को मामले की जांच के आदेश भी दिए थे। जांच के आदेश के बाद सरकार ने स्कूलों से अनाज को हटा दिया था।

'क्या किसी की प्रतिष्ठा खराब करने को कोई कुछ भी लिख सकता है'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी व उनकी पत्नी को लेकर किए गए अपमानजनक ट्वीट पर हाई कोर्ट ने लगाई फटकार

▶ लक्ष्मी एम पुरी ने साकेत गोखले के खिलाफ दायर किया है पांच करोड़ का मानहानि मुकदमा

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी व संयुक्त राष्ट्र में पूर्व सहायक महासचिव उनकी पत्नी लक्ष्मी एम पुरी की तरफ से दाखिल पांच करोड़ के मानहानि मुकदमे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टिविस्ट साकेत गोखले को फटकार लगाई है। गुरुवार को न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि क्या किसी की प्रतिष्ठा खराब करने के लिए कोई कुछ भी लिख सकता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीठ ने फैसला मंगलवार तक सुरक्षित रख लिया।

सुनवाई के दौरान लक्ष्मी पुरी के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने दलील दी कि संयुक्त राष्ट्र का वेतन कर मुक्त है और यह उनके मुवक्किल का पारिवारिक मामला है। गोखले के ट्वीट पर लोगों की प्रतिक्रिया पूरी तरह से मानहानि है। अगर गोखले इसे सार्वजनिक करना चाहते थे तो ट्वीट करने से पहले उनसे पूछना चाहिए था। उन्होंने नए आइटी नियमों का हवाला देते हुए कहा कि अपमानजनक ट्वीट को हटाया जाए।

गोखले की ओर से पेश अधिवक्ता सरीम नवेद ने कहा कि बतौर नागरिक उन्हें सार्वजनिक पदाधिकारियों की संपत्ति के बारे में जानने का अधिकार है। इस पर पीठ ने पूछा कि क्या इस संबंध में उनके पास कोई तथ्य हैं या इसे किसी प्राधिकरण से सत्यापित किया है। नवेद का जवाब था कि कानूनन इसकी जरूरत नहीं है और उन्होंने ट्वीट में वित्त मंत्री को टैग किया था। पीठ ने नवेद से पूछा क्या उनके मुवक्किल उक्त ट्वीट को हटाएंगे तो नवेद ने ना में जवाब दिया।

यह है मामला

साकेत गोखले ने 13 और 26 जून को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी लक्ष्मी एम पुरी को लेकर ट्वीट में कहा था 'लक्ष्मी पुरी ने स्विटजरलैंड में 25 लाख डालर का एक घर खरीदा था। जिस पर खर्च रकम का पर्याप्त वैध स्रोत नहीं था। लक्ष्मी ने उक्त घर 2006 में खरीदा था।'

डीपीसीसी ने 12 ट्रीटमेंट प्लांटों पर ठोका 12 करोड़ का जुर्माना

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने अपशिष्ट जल के निपटान मानकों का लगातार उल्लंघन करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे 12 कामन इफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांटों (सीईटीपी) पर 12 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है।

मालूम हो कि दिल्ली में 24 औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिनमें से 17 इलाके 12 सीईटीपी से जुड़े हैं जो औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को पुनः इस्तेमाल करने या उसे यमुना में बहाने से पहले उसका शोधन करते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार बिना शोधन वाला अपशिष्ट जल और सीईटीपी से निकलने वाले गंदे पानी की खराब गुणवत्ता तथा सीवेज जल शोधन संयंत्र दिल्ली में यमुना नदी में प्रदूषण की मुख्य वजह है। ये 12 सीईटीपी झिलमिल, बादली, मायापुरी, मंगोलपुरी, नांगलोई, ओखला, नरेला, बवाना, नारायणा, जीटीके रोड, केशव पुरम में औद्योगिक इलाकों में हैं। डीपीसीसी ने इन सीईटीपी को कई नोटिस जारी कर उनसे अपशिष्ट जल के निपटान के मानकों पर खरा उतरने के लिए सुधारात्मक उपाय उठाने के लिए कहा था, लेकिन हालात में सुधार नहीं हुआ।

एनडीएमसी को 293 करोड़ रुपये जारी करे दिल्ली सरकार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

नगर निगम कर्मचारियों को वेतन और पेंशन नहीं मिलने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि निगम के कर्मचारियों की उठ रही चीखें बहरे कानों में पड़ रही हैं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह ग्रांट्स-इन-एड (जीआइए) और बेसिक टैक्स असाइनमेंट (बीटीए) की दूसरी और तीसरी तिमाही के 293 करोड़ रुपये दस दिन के अंदर उत्तरी दिल्ली नगर निगम को जारी करे, ताकि वेतन-पेंशन के भुगतान के अंतर को पाटने में निगम सक्षम हो सके।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने गुरुवार को कहा कि कर्मचारियों के वेतन-पेंशन का भुगतान करने के साथ ही शहर को विश्वस्तरीय बनाना नगर पालिका का काम है। ऐसे में पूरी स्थिति और अधिकारियों की बेरुखी से कोर्ट स्तब्ध है। पीठ ने उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी नगर निगम को आय के स्रोत बढ़ाने के संबंध में कदम उठाने और इस संबंध में हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि निगम अपनी आय बढ़ाकर न सिर्फ वेतन व पेंशन का भुगतान करने में सक्षम होंगे, बल्कि दिल्ली को एक सभ्य शहर भी बनाया जा सकेगा।

अस्पतालों को स्थानांतरित करने के मामले में मांगी रिपोर्ट

पीठ ने कहा, चाहें या न चाहें उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के छह अस्पतालों को केंद्र या दिल्ली सरकार को स्थानांतरित करने का फैसला एनडीएमसी को लेना होगा। यह निर्णय वित्तीय विवेक पर आधारित होना चाहिए। साथ ही छह अस्पतालों को केंद्र या दिल्ली को स्थानांतरित करने पर फैसला लेने सहित अन्य तथ्यों पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान एनडीएमसी की तरफ से पेश हुए स्टैंडिंग काउंसल दिव्या प्रकाश पांडे ने कहा कि एनडीएमसी का मासिक वेतन बिल 293 करोड़ रुपये है और उस पर वेतन-पेंशन के रूप में 600 करोड़ से अधिक का बकाया है। जीआइए और बीटीए के तहत दूसरी और तीसरी तिमाही की राशि सितंबर-अक्टूबर में दी जाती है। ऐसे में अगर इसमें से कुछ जल्द भुगतान कर दें तो एरियर भुगतान में निगम को सहूलियत होगी। दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसल अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि एनडीएमसी अनुदान के लिए बार-बार अदालत नहीं आ सकता और उन्हें भी अपनी आय के स्रोत बढ़ाने चाहिए।

वर्षा जल संचयन के लिए जलाशयों को रखें अवैध कब्जों से मुक्त : बैजल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : उपराज्यपाल अनिल बैजल ने वर्षा जल संचयन के लिए जलाशयों को अवैध कब्जे से मुक्त रखने पर जोर दिया है। बैजल ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार के जल संचयन अभियान को दिल्ली में लागू करने के मद्देनजर आयोजित बैठक की अध्यक्षता भी की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संचयन विषय पर गंभीरता जताई है। साथ ही इस अभियान में वर्षा जल संचयन के साथ-साथ भूजल संचयन पर भी जोर दिया है। इसके लिए नए जल संचयन स्थल तैयार करने के निर्देश दिए। उपराज्यपाल ने राजधानी में वर्षा जल संचयन व भूजल संचयन को लेकर विभिन्न एजेंसियों द्वारा अब तक किए गए प्रयासों की सराहना की है। साथ ही कहा कि अभी तक कितना जल संग्रह संभव हो पाया है, इससे जल स्तर में कितना सुधार हुआ है। यह जानकारी भी साझा की जानी चाहिए। जलाशयों की साफ-सफाई, जियो टैगिंग का काम भी जल्द पूरा किया जाए। उपराज्यपाल ने दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को जल वितरण में हो रही लीकेज को कम करने के लिए नई तकनीक का प्रयोग करने को कहा, ताकि जल संचयन हो सके। बैठक में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (पर्यावरण), डीडीए उपाध्यक्ष, मंडलायुक्त व जल बोर्ड के सीईओ ने भी हिस्सा लिया।

आइएलबीएस में होगी नए वैरिएंट की जांच

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले स्वायत्तशासी अस्पताल यकृत व पित्त विज्ञान संस्थान (आइएलबीएस) में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए अत्याधुनिक लैब का शुभारंभ किया। इस लैब में नेक्स्टसेक व एमआइसेक नाम की दो मशीनें हैं। इससे हर सप्ताह 400 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग हो सकेगी। इसके एक दिन पहले ही लोकनायक अस्पताल में भी एक लैब की शुरुआत की गई थी। इसलिए दिल्ली सरकार के दो अस्पतालों में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा हो गई है।

आइएलबीएस में लैब का शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि जीन सीक्वेंसिंग के जरिये कोरोना के किसी भी नए वैरिएंट की पहचान और उसकी गंभीरता का पता लगाया जा सकेगा। इससे अगली लहर में कोरोना से बचाव के लिए रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग की पहली रिपोर्ट अगले तीन-चार दिनों में आ जाएगी। लोकनायक अस्पताल की तुलना में आइएलबीएस की लैब अधिक अत्याधुनिक है। इससे दिल्ली के लोगों को काफी फायदा होगा। अभी तक सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए केंद्र सरकार के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) में भेजने पड़ते थे। आइएलबीएस के निदेशक डा. एसके सरीन ने कहा कि लैब में पहले सैंपल की आरटी-पीसीआर जांच की जाती है। रिपोर्ट पाजिटिव आने पर वायरस के आरएनए की सीक्वेंसिंग की जाती है। कोरोना का हर वैरिएंट खतरनाक नहीं है, लेकिन यह निगरानी रखना जरूरी है कि जो नए मामले आए रहे हैं, उनमें किसी नए वैरिएंट का संक्रमण तो नहीं। कोरोना वायरस में 30 हजार मालिक्यूल होते हैं। लैब में उन सबकी जीनोम सीक्वेंसिंग हो सकेगी। इससे वायरस के स्पाइक प्रोटीन सहित सभी हिस्सों में होने वाले म्यूटेशन का पता चल सकता है। आइएलबीएस अस्पताल के अनुसार नोवासेक नाम की नई मशीन भी खरीदी जाएगी। इस मशीन के जरिये हर सप्ताह तीन हजार सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग हो सकेगी।



आइएलबीएस में जीन सीक्वेंसिंग लैब के शुभारंभ पर चिकित्सकों से बात करते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (बाएं) व साथ में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (बाएं से दूसरे)। सौ.दिल्ली सरकार

एक लाख 20 हजार सैंपल ही चुकी है आरटी-पीसीआर जांच

इस अस्पताल में माइक्रोबायोलाजी की लैब में अब तक एक लाख 20 हजार सैंपल की आरटी-पीसीआर जांच की गई है। इसमें से 13 फीसद सैंपल पाजिटिव पाए गए हैं। लैब में ये सैंपल सुरक्षित रखे गए हैं। डा. एसके सरीन ने कहा कि आदेश मिलने पर उन सभी सैंपल की भी सीक्वेंसिंग की जाएगी।

सभी को आवास देने के लिए बदलेगा दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

अनधिकृत कालोनियों में विकास और लैंड पूलिंग पालिसी का विस्तार जल्द ही रफ्तार पकड़ेगा। दरअसल, दिल्ली में सभी को आवास उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957 में बदलाव करने का निर्णय लिया है। इसका प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए केंद्रीय शहरी विकास विकास मंत्रालय को भी भेज दिया गया है। केंद्र सरकार इसे मानसून सत्र में ही पास भी कर सकती है।

दिल्ली की 1731 अनधिकृत कालोनियों में मालिकाना हक देने की शुरुआत तो डीडीए करीब डेढ़ साल पहले ही कर चुका है, लेकिन इन कालोनियों में विकास कार्यों की शुरुआत अभी भी अटकी हुई हैं। इसकी वजह भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू होने के बाद सरकारी एजेंसियों के लिए भूमि अधिग्रहण में आ रही कानूनी अड़चनें हैं। ऐसी ही समस्या लैंड पूलिंग पालिसी को लेकर है। 2018 में अधिसूचित इस पालिसी में 95 गांवों को शामिल किया गया है, जहां 17 लाख आवास बनाए जाने हैं। लेकिन, यहां भी पालिसी को क्रियान्वित करने के लिए न्यूनतम जमीन भी अब तक अधिगृहीत नहीं कर सके हैं।

दिल्ली की पुनर्संरचना और पुनर्विकास को गति देने के लिए दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट में बदलाव जरूरी हो गया है। कुछ कानूनी अड़चनों का निदान एक्ट में बदलाव से ही संभव है। इन बदलावों के बाद दिल्ली में तेजी से विकास कार्य हो सकेंगे।

-मनीष गुप्ता, सदस्य (प्रशासन एवं भूमि प्रबंधन), डीडीए

लैंड पूलिंग पालिसी के तहत अभी तक करीब 6900 हेक्टेयर जमीन पंजीकृत हो चुकी है, लेकिन पांच जोनों में क्रियान्वित होने वाली इस पालिसी के लिए कम से कम 70 फीसद जमीन पूल होनी चाहिए जबकि एक भी जोन में अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है।

नए नियम के तहत हालमार्किंग सेंटरों पर चलने लगा चाबुक

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली : ज्वेलरी पर हालमार्किंग की अनिवार्यता का नियम लागू होने के बाद पहली बार राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) का चाबुक चला है। बीआइएस के अधिकारियों ने चांदनी चौक के दरीबा कलां स्थित एक हालमार्किंग सेंटर पर छापेमारी कर गड़बड़झाला को पकड़ा है। मौके से तकरीबन 350 ग्राम सोने की ज्वेलरी जब्त की गई है। हालमार्किंग किए कुछ ज्वेलरी को जांच के लिए बीआइएस प्रयोगशाला भेजा गया है।

बीआरएस के मुताबिक उन्हें इस सेंटर में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। यहां ज्वेलरी की मार्किंग पुराने तौर-तरीके से ही की जा रही थी, जिसमें ज्वेलरी की शुद्धता मामले में धांधली की संभावना रहती है। इसी को रोकने के लिए नए नियम में हर ज्वेलरी के लिए विशेष एचयूआइडी नंबर की कंयूटरीकृत व्यवस्था की गई है, जिसका पालन इस सेंटर पर नहीं हो रहा था।

226 कालोनियों में पाइपलाइन से जलापूर्ति नहीं

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में इन दिनों पेयजल किल्लत बनी हुई है। दिल्ली सरकार एक तरफ हर परिवार को प्रति माह 20 हजार लीटर पानी निःशुल्क उपलब्ध कराने का दावा करती है, जबकि स्थिति यह है कि 226 अनधिकृत कालोनियों में पाइपलाइन से पानी आपूर्ति नहीं होती। इस वजह से इन कालोनियों के लोग पेयजल के लिए टैंकर पर निर्भर हैं। इसके अलावा हैरत की बात यह है कि 58 कालोनियों में पाइपलाइन बिछाए जाने के बाद भी पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है।

दल्ली में प्रतिदिन 1,140 एमजीडी पानी की जरूरत होती है, जबकि जल बोर्ड 935 एमजीडी पानी की आपूर्ति करता है। पिछले करीब दो वर्ष से यही स्थिति है। इस वजह से करीब 205 एमजीडी पानी की कमी बनी हुई है। पेयजल की परेशानी अनधिकृत कालोनियों में ही ज्यादा है। दिल्ली में 1,799 अनधिकृत कालोनियां हैं। जल बोर्ड के अनुसार 1,631 कालोनियों में पानी की पाइपलाइन पहुंच चुकी है, लेकिन पानी की कमी के कारण अभी 1,573 कालोनियों में ही पाइप लाइन से पेयजल आपूर्ति हो रही है। इनमें से भी कई कालोनियों में एक दिन छोड़कर पानी आपूर्ति होती है। कुछ कालोनियों में डेढ़ से दो घंटे ही पानी आता है। 168 कालोनियों में अब तक पानी की पाइपलाइन डाली जा सकी है। जल बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 115 कालोनियां वन विभाग व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जमीन पर हैं। इन कालोनियों को छोड़कर बाकी अन्य कालोनियों में चरणबद्ध तरीके से अगले दो साल में पाइपलाइन से हर घर में पानी आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी।

नहीं बढ़ पाई पेयजल आपूर्ति : समर एक्शन प्लान के तहत जल बोर्ड ने अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक 53.7 एमजीडी पानी आपूर्ति बढ़ाने की योजना तैयार की है, लेकिन अब तक पेयजल आपूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकी है। जल बोर्ड वर्ष 2019 में भी करीब 935 एमजीडी पानी की आपूर्ति करता था। अब भी इतना ही पानी आपूर्ति कर पा रहा है। 2019 में पेयजल आपूर्ति के लिए 1,034 टैंकर थे। अब यह संख्या बढ़कर 1,095 हो गई है, जिसमें से 248 टैंकर विभाग के हैं।



दूतावासों के बीच चाणक्यपुरी विवेकानंद कैंप में पानी का टैंकर आते ही पेयजल के लिए इस तरह संघर्ष करते हैं निवासी। ध्रुव कुमार

एसआरएस के निदेशकों के ठिकानों पर सीबीआइ ने ली तलाशी

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद : रियल एस्टेट, ज्वेलरी, सिनेमा व फाइनेंस के कारोबार से जुड़ी एसआरएस ग्रुप आफ कंपनीज के कारपोरेट कार्यालय और निदेशकों के ठिकानों पर बृहस्पतिवार को सीबीआइ की टीम ने तलाशी ली। इस ग्रुप की एसआरएस फाइनेंस लिमिटेड कंपनी पर कारपोरेशन बैंक, बैंक आफ बड़ौदा और कर्नाटक बैंक के साथ करीब 125 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। बैंकों की शिकायत पर सीबीआइ ने दो साल पहले मुकदमे दर्ज किए थे। सीबीआइ इन मामलों की जांच में जुटी है।

इसी के तहत बृहस्पतिवार को सीबीआइ की चार टीमें फरीदाबाद पहुंची थीं। सेक्टर-31 में एसआरएस के कारपोरेट कार्यालय, सेक्टर-11, सेक्टर-नौ और सेक्टर-14 में ग्रुप के निदेशकों के घरों पर सीबीआइ के अधिकारी पहुंचे। उन्होंने घर में मौजूद लोगों से पूछताछ की और धोखाधड़ी से संबंधित दस्तावेज जुटाने की कोशिश की। सीबीआइ पहले भी कई बार आरोपितों के ठिकानों पर तलाशी ले चुकी है।

मौसम

निम्न हवा का दबाव क्षेत्र हिमालय की तराई में हुआ शिफ्ट, जमीन से पांच-छह किमी की ऊंचाई तक बना हुआ है राजस्थान और पाकिस्तान से आ रही हवाओं का असर

दिनभर की उमस से बेचैन दिल्ली को रात की बारिश से राहत

जागरण संवाददाता नई दिल्ली

दिनभर उमस से बेचैन रहे दिल्ली के लोगों को गुरुवार देर रात की बारिश से राहत मिली। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में बादलों की गर्जन के साथ बारिश हुई। हालांकि, पश्चिमी दिल्ली और बाहरी दिल्ली के इलाकों में बारिश नहीं हुई। राजधानी में कई दिनों से लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने गुरुवार की दोपहर में ही हल्की बारिश का अनुमान जताया था।

हालांकि, दोपहर में तो बारिश नहीं हुई, लेकिन देर रात में अचानक मौसम ने करवट ली। इसके बाद रात में करीब 11:30 बजे दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। इससे दिल्ली की तमाम सड़कें भी जलमग्न हो गईं। पुरानी दिल्ली के सदर बाजार कश्मीरी गेट मटिया महल तुर्कमान गेट पहाड़गंज समेत अन्य इलाकों के साथ ही यमुना पार के गीता कालोनी, करावल नगर, गांधी नगर पुश्ता रोड, वजीराबाद रोड पर पानी भर गया। दोपहिया वाहन चालक बारिश से बचने के लिए फ्लाईओवर के नीचे खड़े हो गए, इससे लोगों को जाम का सामना भी करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री ज्यादा 41.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान तीन डिग्री ज्यादा 30.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। 44.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ नजफगढ़ दिल्ली का सबसे गर्म इलाका रहा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने का भी अनुमान है। इससे तापमान भी कुछ नीचे आएगा और 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।



नई दिल्ली में गर्मी से राहत पाने को नहाते बच्चे। एएनआइ

मानसून और बारिश के अनुकूल परिस्थितियां बननी शुरू हो गई हैं। बारिश का दौर भी शुरू होने को है। अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश होने के संकेत मिल रहे हैं। मानसून की दस्तक भी सप्ताहांत के आसपास संभावित है।

-महेश पलावत, उपाध्यक्ष, स्काईमेट वेदर

जुलाई के पहले सप्ताह में लू रही हावी

जुलाई के पहले सप्ताह में सात में से पांच दिन अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहा है। तीन दिन से लू चल रही है। आमतौर पर जुलाई में पश्चिमी हवाएं नहीं चलती। लू की स्थिति भी नहीं ही रहती, लेकिन मौसम विज्ञानियों के अनुसार इस बार मानसून की निम्न दबाव की रेखा जून के तीसरे सप्ताह में दक्षिण से उत्तर में शिफ्ट हो गई। यानी हिमालय के तराई क्षेत्र में पहुंच गई। इससे गर्म पश्चिमी हवाओं ने जोर पकड़ लिया। पिछले 15 दिन से भी अधिक समय से जमीन से पांच-छह किमी की ऊंचाई अथवा वायुमंडल के निचले हिस्से में इन हवाओं ने डेरा जमाया हुआ है। इसी कारण बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से चलने वाली दक्षिणी पश्चिमी हवाएं बेअसर हो रही हैं, लेकिन अब इस स्थिति में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं।

पुलिस पर हमले के आरोपित बूटा सिंह को मिली जमानत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

लाल किला उपद्रव मामला

▶ पांच माह से फरार चल रहे बूटा सिंह पर था 50 हजार का इनाम

▶ 30 जून को दिल्ली पुलिस ने पंजाब के तरनतारन से किया था गिरफ्तार

26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले में हुई तोड़फोड़, हिंसा व पुलिसकर्मी पर हमले के आरोपित बूटा सिंह को गुरुवार को जमानत मिल गई। तीस हजारी कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाउ की अदालत ने बूटा सिंह को जमानत दी। 17 फरवरी को गिरफ्तार मोनिंदर सिंह मोनी को भी अदालत ने जमानत दे दी है। वहीं, एक अन्य आरोपित जजबीर सिंह को पुलिस जांच में शामिल होने का निर्देश दिया। हालांकि सुनवाई की अगली तारीख तक उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

बता दें कि आरोपित बूटा सिंह पांच माह से फरार चल रहा था। दिल्ली पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। गत 30 जून को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने उसे तरनतारन जिले से गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक, बूटा सिंह लाल किले पर हुई हिंसा में शामिल था। उसने सार्वजनिक संपत्ति को लूटा तथा तोड़फोड़ भी की थी। पुलिसकर्मी पर हमला भी किया था। पुलिस ने अदालत से मामले में और पूछताछ व साजिश में पैसों के स्रोत का पता लगाने के लिए उसकी पांच दिन की हिरासत मांगी थी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (डीएसजीएमसी) की कानूनी टीम के वकीलों ने मामले में आरोपित की पैरवी की।

हर किसी को मानने होंगे नियम-कायदे : वैष्णव

दोटूक ▶ सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कामकाज संभालते ही वैष्णव ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर को दिया संदेश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : पूर्व आइटी मंत्री रविशंकर प्रसाद के मंत्री पद छोड़ने के बाद ट्विटर को भारतीय आइटी नियमों के पालन में राहत मिलने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन नए आइटी व इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पर विराम लगा दिया है। गुरुवार को मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद वैष्णव ने कहा कि देश का कानून सर्वोपरि है और ट्विटर को उस कानून को मानना ही होगा। उन्होंने कहा कि जो कोई भी भारत में रहेगा और काम करेगा, उसे देश के नियमों का पालन करना होगा।



नई दिल्ली के रेल भवन स्थित अपने कार्यालय में गुरुवार को पदभार ग्रहण करने के बाद नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव • प्रेट्र

बता दें, ट्विटर भारत के नए आइटी नियमों के पालन में लगातार आनाकानी कर रहा है और इस वजह से ट्विटर ने अपना इंटरमीडिएरी का दर्जा भी खो दिया है। इस साल फरवरी में सोशल मीडिया प्लेटफार्म के लिए नए आइटी नियम लाए गए थे। 25 मई तक इन नियमों को लागू करना था। सरकार के बार-बार कहने के बावजूद ट्विटर ने अब तक नियमों का पालन नहीं किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इंटरनेट मीडिया के नए नियम पालन में ट्विटर की अनदेखी के बाद सरकार को उसके खिलाफ कार्रवाई की छूट दी। नियमों के पालन को लेकर पूर्व मंत्री प्रसाद की तरफ से सख्ती के बीच ट्विटर ने कुछ घंटों के लिए उनके एकाउंट को भी बंद कर दिया। किसान आंदोलन के दौरान लाल किले पर हुए उपद्रव में ट्विटर के प्लेटफार्म से कई भड़काऊ ट्वीट किए गए और उस दौरान भी प्रसाद की तरफ से उन एकाउंट को डिलीट करने के लिए कहा गया। लेकिन ट्विटर ने कार्रवाई करने में काफी समय लिया। इन सब वजहों से ट्विटर और आइटी मंत्रालय के बीच तल्खी बढ़ती जा रही थी। ट्विटर से पहले वाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर भी प्रसाद के कार्यकाल में आइटी मंत्रालय ने अपनी सख्ती दिखाई थी। अब नए मंत्री की तरफ से कानून पालन को लेकर दिए गए संदेश से साफ है कि ट्विटर को कोई रियायत नहीं मिलने जा रही है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि प्रसाद को ट्विटर की वजह से मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक प्रसाद के कार्यकाल में घरेलू स्तर पर मोबाइल फोन निर्माण करने वाली कंपनियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई और मोबाइल फोन का भारत प्रमुख निर्यातक बन गया। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के भारत में निर्माण की शुरुआत के साथ मेक इन इंडिया तकनीक से 5जी सेवा लाने की तैयारी चल रही थी। संचार क्षेत्र में चीन की दखल लगातार कम हो रही थी और ग्रामीण इलाके में सस्ते इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराने की भी कवायद चल रही थी। इसी दौरान लगभग चार लाख गांवों में सीएससी तैनात हुए।

रेलवे में सेफ्टी के साथ रफ्तार की दरकार

सुरेंद्र प्रसाद सिंह • नई दिल्ली

▶ आधुनिकीकरण से संबंधित परियोजनाओं पर देना होगा जोर

यात्रियों को बेहतरीन सुविधाएं देने व माल ढुलाई का लक्ष्य बढ़ाने की जरूरत भारतीय रेलवे की हमेशा से बड़ी चुनौती रही है, जिसे पूरा करने में नवनियुक्त रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को मशक्कत करनी होगी। रेलवे में सेफ्टी के साथ ट्रेनों को रफ्तार देने का काम चालू है, जिसके लिए ढांचागत परियोजनाओं के साथ आधुनिकीकरण का काम सबसे अहम है। रेल मंत्री वैष्णव की संचार क्षेत्र में विशेषज्ञता सिग्नलिंग व बेहतर कोच वाली ट्रेनें चलाने में काम आ सकती है। लेकिन, उनके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती 'जीरो बेस्ड टाइम टेबल' लागू करना है। हालांकि, उनके पास दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के साथ इलेक्ट्रानिक्स मंत्रालय का दायित्व भी है, जो उन्हें इसे लागू करने में सहायक साबित हो सकता है।

वैष्णव ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि रेलवे के लिए प्रधानमंत्री का विजन लोगों के जीवन में बदलाव लाना है, ताकि आम आदमी, किसान और गरीबों को रेलवे का लाभ मिल सके। कोरोना की वजह से पिछले दो साल रेलवे के लिए परेशानियों भरे रहे। यद्यपि ज्यादातर यात्री ट्रेनें पटरी पर दौड़ने लगी हैं, लेकिन यात्रियों को ट्रेनों तक लाना बड़ी चुनौती है। सस्ती हवाई यात्राएं रेलवे को कड़ी चुनौती देने लगी हैं। इसके लिए कम समय में यात्रा पूरी करना और ट्रेनों में मिलने वाली सुविधाएं बढ़ानी ही होंगी। इस बाबत रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में चल रहे कार्यों को तेज करना होगा। रेलवे में सुधार की दिशा में कई अहम कार्य करने हैं, जिसे पूरा करने के लिए नए मंत्री वैष्णव को दृढ़ता दिखानी होगी। भारतीय रेलवे की आठ सेवाओं के बीच समन्वय बनाने के लिए यूनिफिकेशन की प्रक्रिया तेज करनी होगी, ताकि काम गति पकड़ सके। हालांकि, केंद्रीय कैबिनेट ने इस संबंध में बहुत पहले ही रास्ता साफ कर रखा है। रेलवे का आधुनिकीकरण एक बड़ा मामला रहा है, लेकिन यह माना जाता है कि इस क्षेत्र में जिस तरह से काम होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। वैष्णव से पहले पीयूष गोयल ने मंत्री के रूप में इस दिशा में काम तेज किया था।

जोधपुर में जन्मे 51 वर्षीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को यात्रियों की सुख सुविधाओं के साथ माल ढुलाई की दिशा में विशेष प्रयास करने होंगे, ताकि रेलवे की माली हालत में सुधार हो सके। इसके लिए ईस्ट और वेस्ट फ्रेट कारिडोर अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएंगे, जिन पर मालगाड़ियां तीव्र गति से दौड़ सकेंगी। लेकिन, ढुलाई के लिए माल की जरूरत होगी, जिसके लिए रेलवे को अपनी नीतियों में संशोधन करने की जरूरत होगी। रेल पटरियों पर निजी ट्रेनों को दौड़ाने की लंबित परियोजनाएं तेजी पकड़ सकती हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप माडल से रेलवे की आमदनी बढ़ाने की योजना पर आगे बढ़ना होगा। वैष्णव को इसमें विशेष रुचि के लिए जाना जाता है। मोदी सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री शामिल होकर वे भले ही लोगों को चौंका गए, लेकिन रेलवे की बड़ी चुनौतियां देख खुद भी चौंक गए होंगे।

संवाद के नए चेहरे की कसौटी पर अनुराग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : मोदी सरकार में हुए अब तक के सबसे बड़े बदलावों में इस बार सरकार के संवाद का चेहरा भी बदल गया है। भाजपा के युवा चेहरे अनुराग ठाकुर सूचना प्रसारण मंत्री के तौर पर सरकार का नया चेहरा बन गए हैं। उनके सामने एक ओर सरकार के कामकाज की उपलब्धियों के साथ उसकी रीति-नीति को जनता तक पहुंचाने की बड़ी चुनौती है, वहीं डिजिटल मीडिया को आइटी कानून के तहत नियंत्रित करने की पहल का विरोध व प्रस्तावित नए सिनेमेटोग्राफ संशोधन बिल पर उठाए जा रहे एतराज से लेकर टेलीविजन रेटिंग की नई व्यवस्था शुरू करने से जुड़े संवेदनशील मसलों का समाधान निकालने की चुनौती कम नहीं है।

कोरोना की दूसरी लहर व पेट्रोल-डीजल से लेकर खाद्य पदार्थों की महंगाई को लेकर उठाए जा रहे सवालों के मद्देनजर सरकार के दृष्टिकोण को तार्किक साबित करते हुए उसके फैसलों को सही ठहराने का कठिन लक्ष्य भी नए सूचना प्रसारण मंत्री के सामने है। वैसे वित्त मंत्रालय में बतौर राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत पैकेज व तमाम दूसरे वित्तीय पैकेज के बारे में सरकार के नजरिये को जिस तरह स्पष्टता से रखा, उसे चौतरफा नोटिस किया गया। माना तो यह भी जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री के तौर पर प्रमोशन में उनके इस बेहतर संवाद संप्रेषण की भी अहम भूमिका रही है। सूचना प्रसारण मंत्री को सरकार का प्रवक्ता माना जाता है। इस जवाबदेही को निभाने में संयम और वाकपटुता को



सिनेमेटोग्राफ संशोधन बिल है सूचना प्रसारण मंत्री की चुनौती, डिजिटल मीडिया को आइटी एक्ट में लाने का हल निकालना होगा

अपरिहार्य माना जाता है। अनुराग इस कसौटी पर फिट बैठते हैं व हिंदी के साथ अंग्रेजी में संवाद की दक्षता ताकत है।

सरकार की छवि को दुरुस्त करने के अलावा अनुराग के समक्ष ताजा बड़ा मसला सिनेमेटोग्राफ कानून में प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ फिल्म उद्योग का लामबंद होना है। इस संशोधन के जरिये सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म को प्रमाणपत्र देने के बाद भी सरकार को इसकी समीक्षा का अधिकार देने का प्रस्ताव है। फिल्म जगत इसे सिनेमा के नैरेटिव पर सरकारी नियंत्रण के प्रयास के रूप में देख रहा। डिजिटल मीडिया को आइटी कानून के सख्ती के दायरे में लाने के खिलाफ भी बड़े मीडिया संस्थानों के एतराजों का समाधान निकालना सूचना प्रसारण मंत्रालय की चुनौती है। चैनलों की बार्क रेटिंग के बड़े विवाद को देखते हुए चैनलों की रेटिंग की नई प्रणाली शुरू करना भी आसान नहीं है। चैनलों की टीआरपी रेटिंग की नई व्यवस्था के लिए गठित मंत्रालय की समिति ने बीते जनवरी में ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। कोरोना काल में वैश्विक मीडिया में हुईं आलोचनाओं के मद्देनजर दूरदर्शन के प्रस्तावित ग्लोबल न्यूज चैनल की स्थापना भी नए मंत्री के लिए बेहद अहम होगी।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ही होगी धर्मेंद्र प्रधान की परीक्षा



नई दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान (मध्य में) ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। पीआइबी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

तैयारी

▶ शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बैठक में ही प्रधान ने नीति को लेकर तेजी से आगे बढ़ने के संकेत

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिये भले ही देश को फिर से विश्व गुरु बनाने का सपना देखा गया है, लेकिन असल चुनौती इसके पूरी तरह से अमल हो लेकर है। ऐसे में शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने वाले नए मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के सामने इसके तय समय में अमल की एक बड़ी चुनौती होगी।

कोरोना संकट के चलते वैसे भी इसके अमल में कुछ सुस्ती आई है, लेकिन शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बैठक में ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीति को लेकर तेजी से आगे बढ़ने के संकेत दिए हैं। साथ ही कहा कि देश ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिये भविष्य के भारत को गढ़ने की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है। हम तेजी से बढ़ते भारत में सभी छात्रों और युवाओं को एक समान ज्ञान वाले समाज की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

फिलहाल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की राह में जो बड़ी चुनौती है, उनमें इसे तय समय पर लागू करने के साथ राज्यों के साथ तालमेल के साथ आगे बढ़ने की भी है। यह इसलिए भी है, क्योंकि शिक्षा जैसा विषय समवर्ती सूची में है जिसमें राज्यों की भूमिका ज्यादा है। ऐसे में राज्यों को भी साथ लेकर चलना जरूरी होगा। वैसे भी देश के कई राज्यों में जिस तरह से अलग-अलग राजनीतिक दलों की सरकारें है, उनमें यह चुनौती और भी अहम हो जाती है। फिलहाल नीति के अमल को लेकर जो लक्ष्य तय किया है, उसमें 2024 तक नीति को पूरी तरह से लागू करना है। इनमें भी अगले दो सालों में इसके 70 फीसद लक्ष्यों को पूरा करना है। नीति के इस अमल में स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में बड़े बदलाव होने हैं। नीति के अमल के अलावा जो अन्य तात्कालिक चुनौती है, उनमें सीबीएसई के दसवीं और बारहवीं के रिजल्ट को समय पर घोषित करने और जेईई मेंस- नीट जैसी परीक्षाओं सहित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए प्रस्तावित संयुक्त प्रवेश परीक्षा को कराने की है।

इस पर देश के लाखों छात्र टकटकी लगाए हैं। इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी गतिविधियों पर खुद प्रधानमंत्री की गहरी रुचि है। वह स्कूली छात्रों से साथ हर साल परीक्षा पर चर्चा करते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल को लेकर भी वह लगातार शिक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रमुखों से संपर्क में हैं। माना जा रहा है कि पीएम ने प्रधान को यह जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय के सामने आने वाली चुनौतियों को देखते हुए ही सौंपा है।

विदेश मंत्रालय में जयशंकर की सहायता के लिए अब तीन मंत्री



वी मुरलीधरन | राजकुमार रंजन सिंह | मीनाक्षी लेखी (फाइल)

बढ़ा दायरा

▶ विस्तार के बाद दो राज्य मंत्री विदेश मंत्रालय में हुए शामिल

▶ मीनाक्षी लेखी और राजकुमार रंजन ने संभाला कामकाज

नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुए व्यापक फेरबदल व विस्तार के एक दिन बाद मीनाक्षी लेखी और राजकुमार रंजन सिंह ने गुरुवार को विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया। लेखी और राजकुमार रंजन सिंह के शामिल होने के बाद से विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्रियों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है। इससे पहले केरल से सांसद वी मुरलीधरन मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कैबिनेट मंत्री एस जयशंकर का सहयोग कर रहे थे।

विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने लेखी और राजकुमार रंजन सिंह का मंत्रालय के मुख्यालय में स्वागत किया।

तीन दिनों की रूस यात्रा पर गए जयशंकर ने भी ट्वीट कर दोनों मंत्रियों का स्वागत किया। जयशंकर ने ट्वीट किया, मीनाक्षी लेखी और राजकुमार रंजन सिंह का विदेश मंत्रालय में स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। मुझे विश्वास है कि एक साथ मिलकर हम विदेश में भारत के हित को प्रभावशाली ढंग से बढ़ावा दे सकेंगे। लेखी जहां दिल्ली से सांसद हैं वहीं राजकुमार रंजन सिंह मणिपुर से संसद सदस्य हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया, नए राज्य मंत्रियों का विदेश मंत्रालय में स्वागत है।



गृहमंत्री से की मुलाकात

नई दिल्ली में गुरुवार को निशीथ प्रमाणिक (बाएं) और अजय कुमार (बाएं से दूसरे) ने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। एएनआइ

हर हिस्से को उड्डयन से जोड़ना ज्योतिरादित्य का सपना

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सवा साल पहले कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया देश के नए नागरिक उड्डयन मंत्री नियुक्त किए गए हैं। तकरीबन सात वर्ष बाद केंद्रीय सत्ता में शामिल हुए सिंधिया के कंधे पर दो बड़ी जिम्मेदारियां होंगी। एक तो कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित देश के नागरिक उड्डयन सेक्टर को फिर से पटरी पर लाना और दूसरा देश के हर हिस्से को उड्डयन के मानचित्र पर लाना। यह कभी उनके पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया का सपना था जो संयोग से इस सरकार का भी ख्वाब है। माधवराव ने राव सरकार के कार्यकाल में वर्ष 1991-1993 के बीच केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के तौर पर कई सुधारवादी कदम उठाए थे। पदभार संभालने के बाद गुरुवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा भी है कि वह पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपने पूज्य पिताजी के सपने को साकार करने की हरसंभव कोशिश करेंगे।



ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में पदभार संभालने से पहले भाजपा मुख्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। एएनआइ

उम्मीद है कि वह अपने पिता की तरफ से स्थापित उच्च नैतिक मानदंड पर भी खरे उतरेंगे। वर्ष 2018 में टीडीपी की एनडीए से विदाई के बाद इस महत्वपूर्ण मंत्रालय को खास तौर पर संभालने वाले सिंधिया पहले मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी दो वर्षों से इस मंत्रालय के साथ शहरी विकास मंत्रालय भी संभाल रहे थे। वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का भी पदभार संभाला हुआ था। ऐसे में इस मंत्रालय को जो तवज्जो मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिल सकी। कभी देश में आर्थिक सुधार का चमकदार उदाहरण समझा जाने वाला नागरिक उड्डयन मंत्रालय कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है। कोरोना ने इस सेक्टर से जुड़ी हर कंपनी को रसातल में पहुंचा दिया है। तरह-तरह के प्रतिबंधों व लाकडाउन की वजह से घरेलू व अंतरराष्ट्रीय उड़ानों वाली एविएशन कंपनियों का संचालन प्रभावित हुआ है। ऐसे में सिंधिया के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यही है कि एविएशन सेक्टर में उड़ानों का संचालन सुचारू तौर पर हो और लोगों में हवाई उड़ानों के प्रति भरोसा बढ़े। मोदी सरकार ने देश के कोने-कोने को वाणिज्यिक उड़ानों से जोड़ने की जो योजना शुरू की थी उसे परवान चढ़ाया जा सकेगा। एयर डक्कन, एयर ओडिशा, स्पाइस जेट जैसी कंपनियों ने कम फायदे वाले क्षेत्रीय रूट पर खास सेवाएं शुरू की थीं जो ठप हो गई हैं। इन्हें चालू करने के साथ ही पीएम ने 100 नए एयरपोर्ट शुरू करने की बात कही थी जिसको लेकर कदम नहीं उठाए जा सके हैं। देश के कुछ बड़े एयरपोर्ट के निजीकरण का काम सुचारू तौर पर चल रहा था, लेकिन कोरोना से वहां भी काम ठंडा पड़ गया। इन चुनौतियों के साथ ही सिंधिया को सरकारी उड्डयन कंपनी एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया को भी ना सिर्फ आगे बढ़ाना, बल्कि उसे पूरा भी करना है।

रेल मंत्री के कार्यालय में नौ-नौ घंटे की दो शिफ्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : नौकरशाह से नेता बने अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को देश के नए रेल मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण के साथ अपने कार्यालय के अधिकारियों को नौ-नौ घंटे की दो पालियों में काम पर आने का निर्देश दिया है।

इस आशय का एक आदेश रेल मंत्रालय के अलावा संचार, इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के दफ्तर से भी जारी किया गया था। आदेश में कहा गया कि माननीय रेल मंत्री ने निर्देश दिया है कि रेल मंत्री सेल के सभी अधिकारी और कर्मचारी तत्काल प्रभाव से दो पालियों यानी सुबह सात बजे से शाम चार बजे और दोपहर बाद तीन बजे रात 12 बजे तक काम करेंगे।1994 बैच के आइएएस अधिकारी रहे वैष्णव ने 15 वर्षों से अधिक समय तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभाला है। वे विशेष रूप से बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक-निजी भागीदारी ढांचे में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं।

असाधारण

हिम्मत, धैर्य और परिश्रम की मिसाल हैं त्रिपुरा वाली 'दीदी'

प्रतिमा भौमिक त्रिपुरा मूल की पहली एवं पूरे पूर्वोत्तर की दूसरी महिला हैं, जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिला

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

बुधवार की शाम मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के समय एक साधारण सी दिखनेवाली महिला शपथ लेती दिखाई दे रही थीं। प्रतिमा भौमिक त्रिपुरा मूल की पहली एवं पूरे पूर्वोत्तर की दूसरी महिला हैं, जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिला।

प्रतिमा का रहनसहन और पहनावा भले साधारण दिखता हो, लेकिन उनके गुण असाधारण हैं। 1990 के आसपास जब त्रिपुरा में भाजपा का अता-पता भी न रहा हो, उस दौर में प्रतिमा ने भाजपा के युवा संगठन भारतीय जनता युवा मोर्चा का दामन थामा। त्रिपुरा में कितने भी उतार-चढ़ाव आए हों, उन्होंने भाजपा का साथ नहीं छोड़ा। वह पूरे धैर्य के साथ न सिर्फ संगठन में बनी रहीं, बल्कि बार-बार दिल्ली आकर केंद्रीय नेताओं से मिलकर त्रिपुरा में सार्थक बदलाव की सिफारिश भी करती रहीं। यह सिफारिश रंग लाई।

भाजपा ने राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे सुनील देवधर को त्रिपुरा का प्रभारी बनाकर भेजा। बिप्लव देव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। प्रतिमा को प्रदेश महासचिव बनाया गया। इस तिकड़ी ने केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में ऐसा कमाल दिखाया कि माकपा की वर्षों पुरानी माणिक सरकार की सरकार को 2018 में उखाड़ फेंका। सुनील देवधर प्रतिमा की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वह काम में डूबी रहनेवाली हिम्मती महिला हैं।



नई दिल्ली में गुरुवार को प्रतिमा भौमिक ने केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। पीआइबी

▶ 52 वर्षीय विज्ञान स्नातक प्रतिमा खेतिहर परिवार से आती हैं, पिता स्कूल मास्टर थे

▶ वह 1991 से भाजपा से जुड़ीं हैं और उनके गांव की 80 फीसद आबादी मुस्लिम है

▶ लोगों के प्रति के समर्पण के चलते हिंदू हो या मुसलमान सभी के बीच उनका बहुत सम्मान है

त्रिपुरा के वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल सत्तार बताते हैं कि 52 वर्षीय विज्ञान स्नातक प्रतिमा खेतिहर परिवार से आती हैं। पिता देबेंद्र कुमार भौमिक स्कूल मास्टर थे। उनका गांव बरनारायण त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले में उसी धनपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार 20 साल से अधिक समय से जीत दर्ज करते रहे। प्रतिमा विधानसभा चुनाव में दो बार माणिक सरकार का मुकाबला कर चुकी हैं। पहली बार 1998 में, दूसरी बार 2018 में। वह चुनाव हारीं, हिम्मत नहीं। 1991 से भाजपा से जुड़ीं प्रतिमा के गांव की 80 फीसद आबादी मुस्लिम है। उनके घर से भारत-बांग्लादेश सीमा सिर्फ 300 मीटर दूर है।

सीमा पर लगी कंटीली बाड़ के उस पार नो मेंस लैंड में भी भारतीय किसानों के खेत हैं। उन्हें अपना पहचानपत्र दिखाकर ही खेतों में जाने की अनुमति मिलती है। पहचानपत्र बनवाने में प्रतिमा अपने गांव ही नहीं, पूरे इलाके के गरीब किसानों की मदद करती रही हैं। स्थानीय लोगों के प्रति उनका यही समर्पण क्या हिंदू, क्या मुसलमान, उन्हें सबके बीच सम्मान दिलाता है। पूरे इलाके में सब उन्हें दीदी कहकर संबोधित करते हैं।

वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल सत्तार के अनुसार जब लोगों को पता चला कि प्रतिमा भौमिक यानी दीदी केंद्र सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं, तो पूरे इलाके के लोग उनके गांव में इकट्ठा हो गए और प्रतिमा के शपथ लेते ही पूरा माहौल जश्न में बदल गया। हर कोई खुश नजर आ रहा था।

कह के रहेंगे माधव जोशी



2022 में पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होंगे। पांचों राज्यों में कुल लगभग 17.84 करोड़ मतदाता हैं।

मदद करेंगे ये चेहरे

मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान न केवल विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वालों को तरजीह दी गई है, बल्कि राज्यों के समीकरणों का भी ध्यान रखा गया है। वैसे कुल मिलाकर मोदी सरकार की प्राथमिकता विकास और जनकल्याण को तेज करना नजर आ रही है। इनमें राज्य मंत्रियों की भूमिका भी अहम है। मंत्रिमंडल में कई ऐसे चेहरे शामिल किए गए हैं जो प्रभावी काम करने की क्षमता रखते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ राज्य मंत्रियों के बारे में...

ए नारायणस्वामी — उम्र : 64
शिक्षा : स्नातक
पद : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री



कर्नाटक की चित्रदुर्ग लोस सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहली बार संसद पहुंचे हैं। कर्नाटक विधानसभा में चार बार विधायक रह चुके हैं। कर्नाटक की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। उनसे जुड़ी सितंबर 2019 की एक घटना चर्चा में रही जब एक दौरे पर तुमकुर के पावागड़ा तालुक के लोगों ने उन्हें अछूत कह दिया, इस पर उन्होंने गोला गांव में प्रवेश से इन्कार कर दिया था।

पंकज चौधरी — उम्र : 56
शिक्षा : स्नातक
पद : वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री



उत्तर प्रदेश की महाराजगंज लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। छठवीं बार संसद पहुंचे हैं। कुर्मी बिरादरी में अच्छी पकड़ है। 1991 से 2004 तक लगातार सांसद रहे हैं। सिर्फ 2009 का चुनाव हारे। उनका राजनीतिक सफर गोरखपुर के नगर निगम से शुरू हुआ। वह पहली बार 1989-91 में पार्षद चुने गए थे। इसके बाद 1990-91 तक गोरखपुर नगर निगम में ही उप-महापौर रहे।

भानुप्रताप सिंह वर्मा — उम्र : 63
शिक्षा : एमए, एलएलबी
पद : एमएसएमई राज्यमंत्री



उत्तर प्रदेश की जालौन लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। पांचवी बार संसद पहुंचे हैं। कोरी समाज से ताल्लुक रखते हैं और इनकी अपने समाज में अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है, जो उन्हें राजनीतिक रूप से मजबूत बनाती है। 1991 में कोंच विधानसभा सीट से बतौर विधायक अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। 1996 के लोकसभा चुनाव में वह पहली बार सांसद बने।

एसपी सिंह बघेल — उम्र : 61
शिक्षा : पीएचडी, एमए, एमएससी
पद : कानून मंत्रालय में राज्यमंत्री



उत्तर प्रदेश की आगरा लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। पांचवी बार संसद पहुंचे हैं। यूपी पुलिस में रहते हुए उन्हें मुलायम सिंह यादव की सुरक्षा का मौका मिला। मुलायम ने ही उन्हें जलेसर सीट से 1998 में पहली बार उतारा और वह जीते। उसके बाद दो बार सांसद चुने गए। 2010 में बसपा ने उन्हें राज्यसभा भेजा। विधानसभा चुनाव 2017 में टूंडला से जीतने के बाद कैबिनेट मंत्री बने।

कौशल किशोर — उम्र : 61
शिक्षा : स्नातक (विज्ञान)
पद : आवास एवं शहरी मामलों के राज्यमंत्री



उत्तर प्रदेश की मोहनलाल गंज लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी बार संसद पहुंचे हैं। सामंतवाद और गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले कौशल ने 1986 से क्षेत्रीय राजनीति में कदम रखा और निर्दल चुनाव लड़े। वर्ष 2002 में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने के बाद सपा सरकार में श्रम राज्य मंत्री भी रहे। उनकी पासी समाज में अच्छी पकड़ है।

अजय कुमार मिश्रा — उम्र : 60
शिक्षा : बीएससी, एलएलबी
पद : गृह राज्यमंत्री



उत्तर प्रदेश की खीरी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी बार संसद पहुंचे हैं। एक बार विधायक रहने के साथ ही खीरी जिला परिषद के सदस्य भी रहे हैं। साफ-सुथरी छवि के व्यक्ति हैं। लंबे समय से संघ परिवार से जुड़े हैं। उनका चयन 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण मतदाताओं को रिझाने के प्रयास से जोड़कर देखा जा रहा है। उनकी तराई के क्षेत्र में अच्छी पकड़ है।

बीएल वर्मा — उम्र : 59
शिक्षा : परास्नातक
पद : पूर्वोत्तर और सहकारिता राज्यमंत्री



उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हैं। पहली बार संसद पहुंचे हैं। मंत्रिमंडल में शामिल करके पार्टी ने रूहेलखंड के साथ आगरा मंडल में लोधी वोट बैंक को सहेजने की कोशिश की है। 1980 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड कार्यवाह से सामाजिक जीवन के सफर की शुरुआत की। 1984 में वह भाजयुमो के जिला महामंत्री बने। 2003 से 2007 तक वह भाजपा के प्रदेश मंत्री रहे।

राजीव चंद्रशेखर — उम्र : 57
शिक्षा : एमटेक
पद : आइटी एवं कौशल विकास और उद्यमिता विकास राज्यमंत्री



कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य। तीसरी बार संसद पहुंचे हैं। जाने-माने उद्योगपति हैं। 1991 में बीपीएल मोबाइल की नींव रखी। 12 सालों तक टेलीकॉम सेक्टर में एक अग्रदूत की तरह काम करते हुए इस क्षेत्र में निवेश और निर्माण से सेलुलर नेटवर्क को मजबूती प्रदान की। उन्होंने नई दूर संचार नीति एनटीपी 99 को लागू कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

अजय भट्ट — उम्र : 60
शिक्षा : एलएलबी
पद : रक्षा एवं पर्यटन राज्यमंत्री



उत्तराखंड की नैनीताल लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहली बार संसद पहुंचे हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से तीन बार विधायक रह चुके हैं। उत्तराखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। इनका शुरुआती जीवन काफी कठिनाइयों से भरा रहा। मेलों में दुकानें लगा पढ़ाई का खर्चा निकाला। द्वाराहाट में सब्जी की दुकान चलाई। 1985 में वह भाजयुमो से जुड़े।

शांतनु ठाकुर — उम्र : 38
शिक्षा : स्नातक
पद : जहाजरानी राज्यमंत्री



बंगाल की बोनगांव लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहली बार संसद पहुंचे हैं। वे तृणमूल कांग्रेस के पूर्व मंत्री मंजुल कृष्ण ठाकुर के बड़े बेटे हैं। मतुआ समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। यह समुदाय एक साथ वोट करने के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भाषण से प्रेरित शांतनु ने राजनीति में शामिल होने का फैसला किया और जल्द ही छाप छोड़ी।

निशीथ प्रमाणिक — उम्र : 35
शिक्षा : बीसीए
पद : गृह एवं खेल राज्यमंत्री



बंगाल की कूचबिहार लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहली बार संसद पहुंचे हैं। उन्होंने दिनहाटा से विधानसभा चुनाव में जीत भी हासिल की थी, लेकिन पार्टी के निर्देश पर विधायक के तौर पर शपथ नहीं ली। शपथ लेते ही प्रमाणिक विवादों में घिर गए हैं। कूचबिहार के एक तृणमूल नेता ने इंटरनेट मीडिया पर उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर सवाल उठाया है।

जॉन बारला — उम्र : 45
शिक्षा : नौवीं पास
पद : अल्पसंख्यक राज्यमंत्री



बंगाल की अलीपुरद्वार लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहली बार संसद पहुंचे हैं। आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखने वाले बारला का क्षेत्र के चाय बागान श्रमिकों के बीच मजबूत आधार है। उनके संगठनात्मक कौशल ने सबसे पहले माकपा के स्थानीय नेतृत्व का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि वह किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े लेकिन कई मौकों पर वाम मोर्चा को समर्थन दिया।

डॉ. एल मुरुगन — उम्र : 44
शिक्षा : एलएलबी, पीएचडी
पद : मत्स्य और पशुपालन राज्यमंत्री



तमिलनाडु में संघ से राजनीतिक सफर शुरू करने वाले एल मुरुगन अभी संसद में नहीं हैं। मुरुगन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं। उन्होंने वर्ष 2011 में राशिपुरम से विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन असफल रहे थे। उन्हें कुल पड़े मतों के मात्र 1.03 फीसद मत प्राप्त हुए थे। वह अभी भी मद्रास हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। वह अंग्रेजी और तमिल के साथ धाराप्रवाह तेलुगु बोलते हैं।

डॉ. सुभाष सरकार — उम्र : 67
शिक्षा : एमबीबीएस
पद : शिक्षा राज्यमंत्री



बंगाल की बांकुरा लोस सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहली बार संसद पहुंचे हैं। वह एम्स कल्याणी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल होने के साथ ही प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। उन्हें संगठन का आदमी माना जाता है और उनका जंगलमहल इलाके में काफी प्रभाव है। हाल के विधानसभा चुनाव में भी उनके इलाके में बीजेपी का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। पांच दशकों से सरकार रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए हैं।

डॉ. भागवत कराड़ — उम्र : 64
शिक्षा : एमबीबीएस, एमएस
पद : वित्त राज्यमंत्री



भाजपा के टिकट से राज्यसभा से पहली बार सांसद बने हैं। महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं। औरंगाबाद के मेयर रहने के साथ ही मराठवाड़ा लीगल डेवलपमेंट कोआपरेशन के चेयरमैन भी रहे हैं। पेशे से डॉक्टर हैं और औरंगाबाद में स्वयं का मल्टीस्पेशियलिटी हास्पिटल है। संगठन में भी उनकी खासी पकड़ है। स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे ही उन्हें राजनीति में लेकर आए थे। पहले मुंडे की बेटी को मंत्री बनाने की चर्चा थी।

हटाए गए मंत्रियों के पीछे कुछ खराब प्रदर्शन तो कुछ भविष्य की रणनीति

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : नरेंद्र मोदी कैबिनेट के विस्तार से पहले छह हाइप्रोफाइल केंद्रीय मंत्रियों (कुल 12) से इस्तीफा लिए जाने के पीछे केवल प्रदर्शन आधार था या भविष्य की रणनीति, यह सवाल जोर पकड़ने लगा है। माना जा रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा, केंद्रीय सूचना प्रसारण, पर्यावरण व भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावडेकर, केंद्रीय कानून, आइटी व टेलीकाम मंत्री रविशंकर व केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत के इस्तीफे के पीछे दोनों कारण थे।

सदानंद गौड़ा

यह बात किसी से छिपी नहीं है कि गौड़ा



अपने गृहराज्य कर्नाटक में भी जातीय राजनीति के कारण बरकरार हैं। प्रदर्शन के मानक पर वे हमेशा से पीछे रहे हैं। प्रदेश में उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया गया था लेकिन कुछ महीनों में ही हटा दिया गया। किस्मत ने कुछ ऐसा खेल खेला कि केंद्र में उनके रसायन मंत्री रहते ही कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाया और दवाओं की कमी से हाहाकार मच गया। आक्सीजन की कमी तो कुछ दिनों में खत्म हो गई लेकिन गौड़ा दवाओं की कमी दूर नहीं कर पाए। गौड़ा की इस अक्षमता ने सरकार की बहुत किरकिरी कराई। आखिरकार सरकार ने उनके राज्यमंत्री मनसुख मांडविया को आगे बढ़ा दिया। माना जा रहा है कि उन्हें 2023 के कर्नाटक चुनाव में उपयोग किया जाएगा।

रविशंकर प्रसाद

रविशंकर के जाने के पीछे प्रदर्शन का आधार कम है। पूरे देश में आप्टिकल फाइबर बिछाने



के लिए भारत नेट के क्रियान्वयन में जरूर थोड़ी देर हुई लेकिन अभी दो सप्ताह पहले ही कैबिनेट ने 16 राज्यों के 3.60 लाख गांवों में पीपीपी माडल से फाइबर बिछाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। प्रधानमंत्री ने पिछले 15 अगस्त को 1000 दिन का वक्त तय किया था। बताया जा रहा है कि कोरोना के कारण हुई थोड़ी देरी को पाटा जा सकता था। बहरहाल उनका आक्रामक तेवर जरूर सवालों में था। ट्विटर के साथ छिड़ी जंग और अंतरराष्ट्रीय लाबी को एक कारण माना जा रहा है लेकिन यह ध्यान रखने की बात है कि नए आइटी मंत्री ने भी वही सुर दोहराया है। वैसे भी ट्विटर को छोड़कर फेसबुक, गूगल, वाट्सअप जैसे मीडिया प्लेटफार्म ने कानून पर अमल शुरू कर दिया था। टेलीकाम सेक्टर जरूर संकट में पड़ा और रविशंकर उसे सुधारने में असमर्थ दिखे। 5जी के रोलआउट में भी भारत पीछे दिखा। वैसे रविशंकर को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की पूरी संभावना है।

रमेश पोखरियाल निशंक

उत्तराखंड चुनाव सिर पर है और निशंक



की वहां उपयोगिता से इन्कार नहीं किया जा सकता है। लेकिन केंद्र में शिक्षा जैसे अहम मंत्रालय में निशंक वह धमक व क्षमता नहीं दिखा पाए जिसकी अपेक्षा थी। कई कारणों से कभी वे तो कभी उनका स्टाफ, कभी उनकी तैयारी की कमी विवादों में बनी रही। फैसला लेने में अक्सर देरी भी दिखी। दर्जनभर से ज्यादा विश्वविद्यालयों में वीसी के पद खाली हैं। उन्होंने जो लिस्ट बनाकर भेजी उसे पीएमओ ने रद कर दिया। दिल्ली विवि के कुलपति ने तो उन्हें खुली चुनौती तक दे दी थी। मंत्रालय के कामकाज पर पकड़ कितनी कमजोर थी इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है एक साहित्यिक पत्रिका जिसे हिंदी संस्थान की ओर से फंड मिल जा रहा था में केंद्र सरकार को तुगलक बताया जा रहा था। यह भी किसी से छिपा नहीं है कि उनके एक निजी स्टाफ के कमरे में कुछ दिन के लिए ताला लगा दिया गया था। मामला शायद कुछ अनियमितताओं से जुड़ा था।

प्रकाश जावडेकर

70 साल के हो चुके जावडेकर की शिथिलता को एक बड़ा कारण माना जा रहा है।



पर्यावरण में जरूर उन्होंने अपनी क्षमता दिखाई लेकिन कोरोना काल में सूचना प्रसारण सुस्त पड़ा रहा। देश के अंदर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब कुछ वर्गों की ओर से केंद्र सरकार को कठघरे मे खड़ा किया जा रहा था तो जावडेकर से सक्रिय होने की आशा थी। बदलते वैश्विक परिदृश्य में सरकार को नए सक्रिय चेहरे की जरूरत थी। माना जा रहा है कि जावडेकर के लिए सक्रिय राजनीति से परे की भूमिका देखी जा रही है।

हर्षवर्धन

यह सभी को याद होगा कि साफ छवि के



हर्षवर्धन को अपेक्षा अनुकूल प्रदर्शन न दे पाने के कारण पिछली सरकार में भी स्वास्थ्य मंत्रालय से हाथ धोना पड़ा था। इस बार कोरोना की लहर में वे लगभग गायब ही हो गए। वे न तो नेतृत्व देते दिखे और न ही सरकार की आवाज बन पाए। स्वास्थ्य यूं तो राज्य का विषय है लेकिन चाहे अनचाहे उनकी शिथिलता के कारण ही कोरोना का पूरा ठीकरा केंद्र से सिर फूटा।

थावरचंद गहलोत

73 वर्ष के हो चुके थावरचंद को यूं तो राज्यपाल बनाया जा चुका है। उन्हें हटाकर जहां मध्यप्रदेश से नए मंत्री को शामिल करने की जगह बनाई गई वहीं यह संदेश भी साफ है कि 75 की आयु का फार्मूला थोड़ा पहले भी लागू हो सकता है। जावडेकर अब इसी खेमे में खड़े दिखाई दे रहे हैं।



अब हरियाणा मंत्रिमंडल में भी फेरबदल की संभावना

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़

- कई मंत्रियों की विदाई हो सकती है, कुछ के विभाग बदलेंगे तो कई नए चेहर भी होंगे शामिल

केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने के साथ ही अब हरियाणा कैबिनेट में बदलाव और विस्तार की पटकथा तैयार हो गई है। लंबे समय से कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में बदलाव होने के साथ ही इसका विस्तार होना है। नए कृषि कानून विरोधी आंदोलन और कोरोना की दूसरी लहर की वजह से राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार और बदलाव नहीं सका था। अब मोदी कैबिनेट में बदलाव और विस्तार के साथ ही हरियाणा में भी इसकी संभावना बढ़ गई है। हरियाणा में भाजपा-जजपा गठबंधन की सरकार है। 90 सदस्यीय विधानसभा के हिसाब से प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत 14 मंत्री होने चाहिए, लेकिन इस समय 12 मंत्री हैं। एक मंत्री दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जननायक जनता पार्टी के कोटे से बनेगा, जबकि एक मंत्री भाजपा के कोटे से बनना है।

हरियाणा में सितंबर-अक्टूबर में पंचायत और शहरी निकाय चुनाव हैं। भाजपा के कुछ रणनीतिकार इन चुनाव के बाद कैबिनेट विस्तार का सुझाव दे रहे हैं, जबकि अधिकतर एक महीने के भीतर ही कैबिनेट के नए स्वरूप को सामने लाने के पक्षधर हैं। मनोहर लाल अपनी कैबिनेट के कुछ मंत्रियों के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं, जबकि कुछ मंत्रियों की दलील है कि उनके पास करने को कुछ है ही नहीं। ऐसे में मोदी कैबिनेट की तरह मनोहर कैबिनेट में भी ऊर्जावान, कार्यशील, भरोसेमंद और साफ-सुथरी छवि के साथ युवा विधायकों को महत्व दिया जा सकता है।

हरियाणा कैबिनेट में तीन मंत्रियों और चार राज्य मंत्रियों के कामकाज से पार्टी हाईकमान संतुष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री भी इनमें से कुछ मंत्रियों के कामकाज पर असंतोष जता चुके हैं। जजपा कोटे के राज्य मंत्री की परफारमेंस कुछ खास नहीं है, लेकिन दुष्यंत चौटाला के कोटे से होने की वजह से उनका बदलाव संभव नहीं है। जजपा कोटे से ऊर्जावान चेहरे देवेंद्र बबली को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। हालांकि लाइन में रामकुमार गौतम और ईश्वर चंद भी शामिल हैं, लेकिन समय-समय पर दुष्यंत की घेराबंदी करने का उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है।

ममता बनर्जी को ध्रुवीकरण के चलते संयोगवश मिला फायदा : अधीर

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का मानना है कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) अध्यक्ष ममता बनर्जी को बंगाल विधानसभा चुनाव में ध्रुवीकरण के चलते संयोगवश फायदा मिला। उन्होंने कहा कि वह इकलौती 'मोदी विरोधी चेहरा' नहीं हैं, जो अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा का मुकाबला कर सकें। अगले लोकसभा चुनावों से पहले एक व्यापक भाजपा विरोधी गठबंधन की संभावनाओं पर चौधरी ने कहा कि कोई भी विपक्षी मोर्चा कांग्रेस की मदद के बिना सफल नहीं हो सकता।

लोकसभा में कांग्रेस के नेता चौधरी ने समाचार एजेंसी प्रेट्र को दिए गए साक्षात्कार में कहा कि चुनाव के दौरान कूचबिहार में केंद्रीय बलों की गोली लगने से चार मुसलमानों की मौत के बाद अल्पसंख्यक मतों का ध्रुवीकरण हो गया। राज्य की जो जनता भाजपा को नहीं चाहती थी, उसने एक साथ तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया। सांप्रदायिक बयानबाजी और भाजपा के नेताओं की डराने-धमकाने वाली राजनीति से ममता बनर्जी को मदद ही मिली। उन्होंने कहा कि मैं कहूंगा कि वह इन चुनावों में संयोगवश फायदा पाने वाली नेता हैं।

चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी भाजपा को हराने वाली इकलौती क्षेत्रीय नेता नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव, एमके स्टालिन, पिनराई विजयन ने भी ऐसा कर दिखाया है। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी ने अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं की इस बात को खारिज कर दिया कि वह ममता बनर्जी के भाजपा से भी बड़े आलोचक हैं। वह अक्सर उनके खिलाफ बयान देते हैं।

'ताश का जोकर नहीं, रिंग मास्टर बनें मुस्लिम'

जासं, बहराइच : हमें किसी पार्टी के ताश का जोकर नहीं बनना है, बल्कि पार्टी हित में संघर्ष कर रिंग मास्टर बनकर दूसरे लोगों को सबक सिखाना है। ये बातें आल इंडिया मजलिस-ए इत्तिहादुल मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच में कहीं। वह गुरुवार को पार्टी के प्रदेश स्तरीय कैंप कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे।

ओवैसी ने कहा कि नौजवान डिग्री लेकर दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। दिन-प्रतिदिन डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि केंद्र व राज्य में शासन करने वाले लोग देश को किधर ले जाना चाहते हैं। चुनाव का समय जब नजदीक आता है तो तमाम पार्टियां मुस्लिमों की हितैषी बनकर सामने आती हैं। रमजान के दिनों में इफ्तार में उनका शामिल होना मुस्लिमों के लिए कोई मायने नहीं रखता है।

कल्याण सिंह के लिए पीएम मोदी भी चिंतित : नड्डा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अपनी धारदार राजनीति से उत्तर प्रदेश में भाजपा के कल्याण के द्वार खोलने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को लेकर पूरी पार्टी फिक्रमंद है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी गुरुवार को राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष के साथ गुरुवार देर शाम लखनऊ पहुंचे। एसजीपीजीआइ में भर्ती वयोवृद्ध नेता का हालचाल जाना और बोले कि कल्याण सिंह के स्वास्थ्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिंतित हैं।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह कुछ दिन से अस्वस्थ होने के कारण लखनऊ स्थित एसजीपीजीआइ में भर्ती हैं। लगातार पार्टी के वरिष्ठ नेता उनके देखने के लिए पहुंच रहे हैं। दो बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जा चुके हैं। इसी क्रम में जेपी नड्डा भी राजकीय विमान से बीएल संतोष के साथ लखनऊ पहुंचे।



भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को लखनऊ में एसजीपीजीआइ में उपचाराधीन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से मिलने पहुंचे और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ थे। सौ. सूचना विभाग

हवाई अड्डे पर योगी, भाजपा प्रदेश प्रभारी राधामोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उपमुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा ने अमौसी हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली से ही उनके साथ आए थे। यहां से सभी वरिष्ठ नेता एसजीपीजीआइ पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य का हालचाल लिया। उनके पौत्र राज्यमंत्री संदीप सिंह से भी इस संबंध में बातचीत की। इसके बाद संस्थान के निदेशक डा. आरके धीमन से स्वास्थ्य की स्थिति, इलाज प्रक्रिया आदि की विस्तृत जानकारी ली। नड्डा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमारे वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह का इलाज यहां एसजीपीजीआइ में चल रहा है। उन्हें देखने का सौभाग्य मिला। उनके स्वास्थ्य के प्रति प्रधानमंत्री भी चिंतित हैं। यहां जानकारी मिली है कि पूर्व सीएम की स्थिति अब स्थिर है। स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। नड्डा ने कहा कि हम ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि हमारे वरिष्ठ नेता जल्द स्वस्थ हों और हमें मार्गदर्शन देते रहें।

उल्लेखनीय है कि अचानक तबीयत बिगड़ने पर तीन जुलाई की रात में कल्याण सिंह को पहले राममनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान और फिर स्थिति में सुधार न होने पर अगले दिन एसजीपीजीआइ रेफर कर दिया गया।

ममता ने सौरव को घर जाकर दी जन्मतिथि की शुभकामना, कयासों का दौर शुरू

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

- बंगाल की सीएम को बीसीसीआइ अध्यक्ष ने भेंट की साड़ी
- दोनों की मुलाकात को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान व बीसीसीआइ के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली को गुरुवार को उनकी जन्मतिथि पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके घर जाकर शुभकामना दी। यह पहला मौका है, जब मुख्यमंत्री उनके बेहला स्थित घर गईं। इसके बाद कयासों का दौर शुरू हो गया। पूर्व क्रिकेटर 49 साल के हो गए हैं।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सौरव ने ममता को एक साड़ी भेंट की। यह साड़ी उनकी पत्नी डोना गांगुली ने ममता के लिए खरीदी थी। जन्मतिथि पर डोना ने सौरव को उपहार में एक मोबाइल फोन दिया है। ममता के सौरव के घर जाकर उन्हें शुभकामना देने को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है। इस मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। गौरतलब है कि बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सौरव को ममता के खिलाफ उतारने की जुगत में थी, पर सौरव ने साफ तौर पर कह दिया था कि उनकी राजनीति में कदम रखने की कोई इच्छा नहीं है। ममता और सौरव गांगुली के काफी अच्छे संबंध हैं। सौरव को बंगाल क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बनाने में ममता की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। बाद में बीसीसीआइ अध्यक्ष बनने के बाद सौरव ने यह पद छोड़ दिया था। इस साल जनवरी माह में सौरव जब दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे तो ममता उन्हें देखने अस्पताल गई थीं।



कोलकाता में गुरुवार को बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली को जन्मतिथि पर बधाई देने उनके आवास पहुंचीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। प्रेट्र

सिंधिया का फेसबुक अकाउंट किया हैक

नईदुनिया, ग्वालियर : ज्योतिरादित्य सिंधिया के केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने के कुछ ही घंटे बाद उनका अधिकृत फेसबुक अकाउंट (पेज) हैक हो गया। हैकर ने मोदी को कोसने वाले सिंधिया के पुराने वीडियो पेज पर अपलोड कर दिए। सात और आठ जुलाई की दरम्यानी रात 12:24 बजे अज्ञात व्यक्ति द्वारा अकाउंट हैक किए जाने के मामले को लेकर पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल द्वारा क्राइम ब्रांच में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई है।

हैकर ने सिंधिया के पेज पर उनके कांग्रेस में रहने के दौरान दिए भाषणों के पुराने वीडियो अपलोड कर दिए थे। इन वीडियो में सिंधिया भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर कोस रहे थे। हालांकि, पेज हैक होने के कुछ समय बाद ही सिंधिया की टीम सक्रिय हो गई और सभी वीडियो समेत अन्य पोस्ट को डिलीट कर फेसबुक अकाउंट रिकवर कर लिया गया। सिंधिया समर्थकों ने कांग्रेस पर हैकिंग कराने का आरोप लगाया है।

पंजाब में मुफ्त बिजली देने को लेकर असमंजस

इंद्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़

पंजाब में बिजली सब्सिडी आगामी विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनती दिख रही है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली माडल को लेकर रक्षात्मक रवैया अपना रही कैप्टन सरकार जल्द ही आक्रामक रुख अख्तियार कर सकती है। हालांकि सरकार अभी 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने या न देने को लेकर किसी निर्णय पर नहीं पहुंची है। इस पर फैसले के लिए मुख्यमंत्री जल्द ही कैबिनेट की बैठक बुला सकते हैं।

मालूम हो कि दस दिन पहले पंजाब के हर घर को दो सौ यूनिट निश्शुल्क देने के कांग्रेस हाई कमान के फैसले को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पावरकाम के अधिकारियों से डाटा मांगा था। इसमें यह बात सामने आई कि मुफ्त बिजली और सब्सिडी देने में पंजाब दिल्ली से आगे है। राज्य में 40 लाख उपभोक्ताओं को यह सुविधा मिल रही है।

सूत्रों के अनुसार सरकार में चर्चा हो रही है कि अब और ज्यादा सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। बिजली विभाग ने इस पर तीन से चार हजार करोड़ रुपये का बजट बताया है, जो सरकार की मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए संभव नहीं है। कारण यह कि राज्य सरकार पहले ही 10434 करोड़ रुपये बिजली सब्सिडी पर खर्च कर रही है।

दिल्ली से सस्ती है पंजाब में बिजली

- दिल्ली और पंजाब की तुलनात्मक रिपोर्ट में पावरकाम के अधिकारियों ने दावा किया है कि दिल्ली में कामर्शियल बिजली पंजाब की तुलना में साढ़े तीन रुपये प्रति यूनिट महंगी है। पंजाब में इसकी दर 7.97 रुपये प्रति यूनिट है तो दिल्ली में 11.34 रुपये प्रति यूनिट है।
- पंजाब में सालाना 467130 लाख यूनिट बिजली बेचकर 29903 करोड़ रुपये का राजस्व मिलता है। इसके मुकाबले दिल्ली में 274360 लाख यूनिट बेचकर 20556 करोड़ रुपये राजस्व मिलता है। यानी पंजाब को प्रति यूनिट औसत 6.40 रुपये जबकि दिल्ली को प्रति यूनिट 7.49 रुपये मिलते हैं।
- पंजाब सरकार बिजली पर 10458 करोड़ रुपये तो दिल्ली सरकार 2820 करोड़ रुपये की सब्सिडी देती है। यानी पंजाब सरकार सब्सिडी पर 2.24 रुपये जबकि दिल्ली सरकार 1.03 रुपये प्रति यूनिट खर्च कर रही है। सब्सिडी निकालकर पंजाब को 19445 करोड़ रुपये तो दिल्ली को 17336 करोड़ रुपये राजस्व मिलता है।

बिजली कट से परेशान किसान ने दी जान

: जासं, श्री मुक्तसर साहिब : जिले के लंबी में बिजली संकट के कारण धान की फसल सूखने से परेशान होकर गांव माहूआना के 35 वर्षीय किसान बलजीत सिंह ने खेत में ही टाहली के पेड़ से फंदा लगा लिया। साले जगमीत सिंह ने बताया कि बलजीत के पास करीब चार एकड़ जमीन है। वह करीब 20 एकड़ जमीन को ठेके पर लेकर खेती करता था।

आखिर ट्विटर ने दिया भरोसा, लागू करेगा नई आइटी नीति

दो सप्ताह के अंदर अमेरिका में नोटिफाई हलफनामे को दायर करने दिया निर्देश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

केंद्र सरकार के लगातार बढ़ते दबाव और दिल्ली हाई कोर्ट के सख्त रुख से ट्विटर के तेवर ढीले पड़ गए हैं। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ के समक्ष ट्विटर ने कहा कि वह नए आइटी नियमों का पूरी तरह से अनुपालन करेगा। पीठ को सूचित किया कि छह जुलाई को एक अंतरिम मुख्य शिकायत अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई और अन्य स्थानीय शिकायत अधिकारी की नियुक्त 11 जुलाई तक कर दी जाएगी।

ट्विटर की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पुवैया ने एक हस्ताक्षरित ज्ञापन दाखिल किया। इसे रिकार्ड पर लेते हुए पीठ ने ट्विटर को निर्देश दिया कि अमेरिका में नोटिफाई किए हलफनामे को दो सप्ताह के अंदर दाखिल करें और इसकी स्कैन प्रति 13 जुलाई तक दाखिल करें। साथ ही, आइटी नियमों के तहत नियुक्त अधिकारियों की ताजा अनुपालन रिपोर्ट भी पेश की जाए।

केंद्र कार्रवाई को स्वतंत्र: अमित आचार्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत ट्विटर को आइटी नियमों पर कोई सुरक्षा नहीं देगी और आइटी नियमों का उल्लंघन होने पर केंद्र सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है।

▸ कहा, आइटी नियमों का उल्लंघन करने पर केंद्र सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र

'अंतरिम' पर उठा सवाल : सुनवाई के दौरान पीठ ने पूछा कि अंतरिम मुख्य शिकायत अधिकारी से क्या मतलब है। इस पर पुवैया ने कहा कि 'अंतरिम' शब्द के प्रयोग से नए आइटी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का अधिकारियों का उत्तरदायित्व कम नहीं होगा। पीठ के यह कहने पर कि आप भविष्य में अंतरिम शब्द का फायदा उठा सकते हैं, पुवैया ने कहा कि ट्विटर का भारत में स्थायी कार्यालय नहीं है और इस कारण स्थायी कर्मचारी की नियुक्ति ट्विटर नहीं कर सका है। उन्होंने बताया कि ट्विटर एक संपर्क कार्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया में है। उन्होंने कहा कि अभी ट्विटर का कार्यालय बैंगलुरु में है। उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया के लिए आठ सप्ताह का समय देने की मांग की, जिसे पीठ ने खारिज कर दिया।

हलफनामा दायर नहीं करने पर जताई आपत्ति : केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल सालिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने हलफनामा नहीं दायर होने पर आपत्ति दर्ज कराई। उम्मीद जताई कि नियमों के पालन में ट्विटर सद्भावना से प्रयास करेगा और किसी तीसरे पक्ष की नियुक्ति का मतलब नहीं है। जवाब में पुवैया ने कहा कि प्रयास शब्द का इस्तेमाल गैर-अनुपालन के मामले में अदालत की अवमानना से बचने के लिए किया गया था। इस पर अदालत ने कहा कि आप (ट्विटर) पहले से ही अवमानना में हैं।

उप्र पुलिस के नोटिस को रद करवाना चाहते हैं ट्विटर इंडिया एमडी

बेंगलुरु, प्रेट्र : ट्विटर इंडिया के प्रबंधन निदेशक (एमडी) मनीष माहेश्वरी ने गुरुवार को कर्नाटक हाई कोर्ट से उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जारी नोटिस को रद करने की मांग की। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील एक वीडियो के प्रसार के मामले में माहेश्वरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है।

माहेश्वरी ने पहले इशारा किया था कि वह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जांच में सहयोग करना चाहते हैं। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। हाई कोर्ट के जस्टिस जी. नरेंद्र की एकल पीठ के समक्ष वकील सीवी नागेश ने माहेश्वरी की तरफ से कहा कि 17 जून को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस जारी किया गया। नागेश ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 160 उस पर लागू होती है।

बुजुर्ग की पिटाई के मामले में कांग्रेसी नेता के बयान दर्ज

संवाद सहयोगी, लोनी : बुजुर्ग अब्दुल समद की पिटाई व दाढ़ी काटने का वीडियो ट्वीट करने के मामले में बृहस्पतिवार को आरोपित कांग्रेस नेता डॉ.मसकूर अहमद उस्मानी ने लोनी बार्डर थाने पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराए। कांग्रेस नेता से करीब दो घंटे तक पूछताछ हुई। लोनी में बुजुर्ग की पिटाई के बाद उसकी दाढ़ी काटी गई थी। इसका वीडियो सपा के पूर्व प्रदेश सचिव उम्मेद पहलवान ने इंटरनेट मीडिया पर वायरल की थी।

एप पर लगाई जा रही थी मुस्लिम महिलाओं की बोली, केस दर्ज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : मुस्लिम महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने के मामले में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने गुरुवार को एक एप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बीते दिनों इस एप पर मुस्लिम महिलाओं के फोटो व उनके ट्विटर हैंडल की जानकारी देकर उनकी बोली लगाई जा रही थी। आपत्ति आने पर एप को बंद तो कर दिया गया था, लेकिन इसे लेकर विभिन्न संगठनों ने शिकायतें दी थीं। साइबर सेल ने वेबसाइट गिटहब को नोटिस भेजकर एप बनाने वालों और इस्तेमाल करने वालों की जानकारी मांगी है।

पुलिस के मुताबिक, गत रविवार और सोमवार को सुल्ली डील नाम से ओपन सोर्स एप बनाया गया था। एप पर मुस्लिम महिलाओं के ट्विटर हैंडल से जानकारियां और तस्वीरें निकाल कर अपलोड कर दी गई थीं। उक्त तस्वीरों के जरिये महिलाओं की बोली लगाई जा रही थी। एप खोलने पर महिलाओं की तस्वीरें व उनकी निजी जानकारी सार्वजनिक हो जाती थी। हैरानी की बात है कि महिलाओं की तस्वीर के साथ कीमत भी लिखी होती थी।

अजीत मोहन की याचिका प्री-मेच्योर है : कोर्ट

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे


तीखा रुख : सुप्रीम कोर्ट। फाइल फोटो

जस्टिस संजय किशन कौल, दिनेश महेश्वरी और ऋषिकेश राय की पीठ ने अजीत मोहन, फेसबुक इंडिया आनलाइन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और फेसबुक इंक की याचिका खारिज करते हुए कहा कि अजीत मोहन की याचिका प्री-मेच्योर है क्योंकि विधानसभा कमेटी के समक्ष उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। याचिका में कहा गया था कि कमेटी को पेश नहीं होने पर विशेषाधिकार हनन पर समन भेजने का अधिकार नहीं है।

कोर्ट ने अपने आदेश में माना कि दिल्ली विधानसभा को 2020 के दिल्ली दंगों की जांच के लिए कमेटी गठित करने का अधिकार है। हालांकि कोर्ट ने कमेटी के अध्यक्ष के प्रेस में दिए गए बयान को ठीक नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि कमेटी को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि वह एक तरह से अभियोजक एजेंसी है जिसे लोगों को दोषी ठहराने और और उनके खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल करने का निर्देश देने का अधिकार है। अगर कमेटी अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करती है और कानून-व्यवस्था व पुलिस जो उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है, के प्रतिबंधित क्षेत्र में जाती है तो याचिकाकर्ता फेसबुक प्रतिनिधि कमेटी के सवाल का जवाब देने से मना कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि वह इस बारे में सीमित संरक्षण ही दे रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रतिनिधि किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे और कमेटी की कार्यवाही को ही निष्फल कर देंगे। कोर्ट ने कहा, हमें भरोसा है कि ऐसा नहीं होगा।

कोर्ट ने कहा, इस बात में कोई विवाद नहीं है कि विधानसभा और उसकी कमेटी को विशेषाधिकार हनन पर कार्रवाई का अधिकार है। लेकिन इस मामले में विशेषाधिकार का मुद्दा प्रीमेच्योर है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली विधानसभा को कानून व्यवस्था और पुलिस के बारे में कानून बनाने का अधिकार नहीं है, संविधान में ये चीजें उसके क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। इसके अलाव इंटरमीडिएरीज के नियमन का विषय भी आइटी कानून के तहत आता है।

न्यूज गैलरी

छह बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का निधन

शिमला : पांच बार लोकसभा सदस्य, छह बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, तीन बार केंद्रीय मंत्री व नौ बार विधायक रहे वीरभद्र सिंह नहीं रहे। राजपरिवार से संबंध रखने वाले वीरभद्र सिंह हिमाचल की राजनीति के छह दशक तक सरताज रहे। उन्होंने गुरुवार सुबह 3.40 बजे शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज अस्पताल में अंतिम सांस ली। कोरोना से दो बार जंग जीतने के बाद वह कई दिन से अस्पताल में उपचाराधीन थे। निमोनिया सहित अन्य बीमारियों के कारण उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया। अंतिम संस्कार शनिवार को रामपुर में सतलुज नदी के किनारे किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रदेश सरकार ने तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। (जासं)


स्मृतियों में रहेंगे वीरभद्र सिंह। फाइल

बीएसएफ जवान निकला हथियार तस्कर, पकड़ा गया

पटना : दो रायफल, एक पिस्तौल व 460 गोलियों के साथ बिहार में अरवल के जहानाबाद मोड़ से दो हथियार तस्करों को एसटीएफ की टीम ने गुरुवार को दबोच लिया। तस्करों में से एक जय पुकार राय खुद को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का जवान बताया है। (राब्यू)

मधुवनी में छह जगह टूटा कोसी नहर का तटबंध

मुजफ्फरपुर : लगातार बारिश से उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। मधुबनी का बेनीपट्टी अनुमंडल बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है। गुरुवार को बेनीपट्टी प्रखंड में कोसी नहर का तटबंध पांच जगहों पर और हरलाखी प्रखंड में एक जगह टूट गया। (जासं)

एक कैनाइन दांत टूटने से आदमखोर हो गया था तेंदुआ

उदयपुर : भोजन के लिए आवश्यक कैनाइन दांतों में से एक भी टूट जाए तो तेंदुए के आदमखोर होने की आशंका बनी रहती है। आदमखोर तेंदुए के बारे में अधिकारियों एवं मेडिकल टीम ने यही दावा किया है। (संसू)

पुलवामा व कुलगाम में चार आतंकी ढेर, हमले की थी साजिश

कार्रवाई ▸ सेना ने सरेंडर का दिया पूरा मौका, नहीं माने तो किया ढेर

बुधवार को भी हिजबुल के शीर्ष आतंकी को किया था ढेर

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

कश्मीर में आतंकवाद पर प्रहार लगातार जारी है। सुरक्षाबल के जवानों ने दक्षिण कश्मीर में गुरुवार तड़के पुलवामा और कुलगाम में हुई दो मुठभेड़ों में लश्कर-ए-तैयबा के चार आतंकियों को मार गिराया। कुलगाम में मारे गए दोनों आतंकी राष्ट्रीय राजमार्ग पर जवानों पर आत्मघाती हमले की साजिश को अंजाम देने वाले थे। जवानों ने हंदवाड़ा में बुधवार को भी हिजबुल के दुर्दांत आतंकी मेहराजुदीन हलवाई को मार गिराया था।

कुलगाम से मिली सूचनाओं में बताया गया है कि तड़के तीन बजे जाडूर में सुरक्षाबलों ने नाका लगाया था। नाका पार्टी ने एक कार को देखा। चालक ने जैसे ही नाका देखा उसने कार समेत वहां से निकल भागने का प्रयास किया। जवानों ने रुकने का संकेत करते हुए चेतावनी दी। कार चालक व उसके साथी ने कार से बाहर निकल पास ही जंगल की तरफ भागना शुरू कर दिया। नाका पार्टी ने तुरंत आसपास चौकियों को सूचित करते हुए आतंकियों की घेराबंदी शुरू कर दी। खुद को फंसते देख आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई कर दोनों आतंकियों को मार गिराया। उनके पास से एक एके-47 राइफल व दो मैगजीन, एक पिस्तौल और दो मैगजीन मिले हैं।


जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में गुरुवार को आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान मोर्चा संभाले जवान। एएनआइ

सेना ने कई बार दिया सरेंडर का मौका : इससे पूर्व पुलवामा जिले के पुच्छल में पुलिस ने सेना और सीआरपीएफ के जवानों के साथ मिलकर आतंकियों की धरपकड़ के लिए तलाश अभियान चलाया। यह अभियान बुधवार मध्य रात्रि शुरू हुआ। जवानों को अपने ठिकाने की तरफ आते देख आतंकियों ने उन पर फायरिंग की। जवानों ने खुद को बचाते हुए जवाबी फायर कर उन्हें मुठभेड़ में उलझा लिया। जवानों ने इस दौरान उन्हें कई बार सरेंडर का मौका देते हुए अपनी तरफ से फायरिंग भी रोकी रखी। आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग जारी रखी। आतंकियों को न मानते देख, जवानों ने भी जवाबी प्रहार तेज किया और दोनों आतंकियों को मार गिराया। सूत्रों ने बताया कि मुठभेड़ आधी रात के बाद करीब एक बजे शुरू हुई थी। बावजूद जवानों ने सुबह पांच बजे तक पूरी नरमी बरती ताकि किसी तरह आतंकी सरेंडर करें। पहला आतंकी सुबह सवा पांच बजे मारा गया और दूसरा अगले पांच मिनट बाद।

खतरनाक थे इरादे : आइजीपी

पुलिस महानिरीक्षक (आइजीपी, कश्मीर) विजय कुमार ने पुलवामा और कुलगाम में चार आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि यह सभी स्थानीय ही थे। लश्कर से जुड़े हुए थे। दोनों आतंकी राष्ट्रीय राजमार्ग पर अगले चंद दिनों में आत्मघाती हमले की तैयारी में थे।

सुंदरबनी में जंगल में छिपे दो विदेशी आतंकी ढेर, सेना के दो जवान शहीद

जागरण संवाददाता, राजौरी


मारुप्रोलु जसवंत रेड्डी। फाइल


सूबेदार श्रीजीत एम। फाइल

जम्मू-कश्मीर में राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर के दादल क्षेत्र में 10 दिन से तलाश में जुटे सेना के जवानों ने आतंकियों को ढूंढ निकाला। ये आतंकी एलओसी पार कर भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे। वीरवार को दादल के जंगल में छिपे आतंकियों ने जवानों को देख गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें सेना के नायब सूबेदार सहित दो जवान शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में दो विदेशी आतंकी मारे गए। सेना का बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। इसमें पैरा कमांडो भी उतारे गए हैं। सेना के आपरेशन में पुलिस के विशेष अभियान दल के जवान व अधिकारी भी शामिल हैं। आशंका है कि जंगल में और भी आतंकी छिपे हो सकते हैं।

29 जून को नियंत्रण रेखा (एलओसी) से सटे गांव दादल के कुछ लोगों ने हथियारों से लैस संदिग्धों को देख सेना के जवानों को सूचित किया। जवानों ने पूरे क्षेत्र को घेर कर तलाशी अभियान शुरू किया। चप्पे-चप्पे को खंगाला जाने लगा। 29 को क्षेत्र में गोलाबारी में सेना का जवान घायल हो गया था। उसके बाद से क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी था। गुरुवार सुबह 11 बजे आतंकवादियों व सेना के जवानों के बीच गोलाबारी शुरू हुई और फिर से बंद हो गई। आतंकी घने जंगल में छिपकर बैठे थे। दोपहर बाद फिर से आतंकियों ने गोलाबारी शुरू कर दी। सेना के जवानों ने कार्रवाई कर दो विदेशी आतंकवादियों को ढेर कर दिया। ये आतंकी हाल ही में एलओसी पार करके भारतीय क्षेत्र में घुसे थे।

बड़े पैमाने पर हमले की साजिश रच रहे थे आतंकी

गगन कोहली, नौशहरा (राजौरी) : राजौरी के नौशहरा सेक्टर के कलाल क्षेत्र में सेना ने बुधवार को आतंकियों की घुसपैठ की बड़ी कोशिश को तो नाकाम कर दिया, लेकिन इसके पीछे सरहद पार पाकिस्तान और आतंकी संगठनों के मंसूबे खतरनाक थे। मारा आतंकी पाकिस्तानी था। अगर सभी छह आतंकी घुसपैठ कर भारतीय क्षेत्र में पहुंच जाते तो बड़े पैमाने पर हमले करते। बताया जाता है कि ये आतंकी आत्मघाती हमलों में भी निपुण थे। मारे गए आतंकी ने गुलाम कश्मीर में लश्कर के शिविर में प्रशिक्षण लिया था।

जवान चौकस: सेना के 25 डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल राजीव पुरी ने कहा कि सीमा पर हमारे चौकस जवानों ने घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। यह आपरेशन अभी भी जारी है। घुसपैठ के प्रयास को विफल करने में जवान पूरी तरह से सक्षम है। मारे गए पाक आतंकी से 300 रुपये पाक करंसी, ठंडे के बोतलें और खाने का सामान भी मिला है।

जम्मू-कश्मीर में सचिवालय और राजभवन नो फ्लाई जोन घोषित

राज्य ब्यूरो, जम्मू

जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले से उपजे हालात के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर में सचिवालय और राजभवन के ऊपर एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। उपराज्यपाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने वीरवार को आदेश जारी किया। प्रदेश की दोनों राजधानियों में उपराज्यपाल के कार्यक्रम स्थलों के ऊपर से कार्यक्रम संपन्न होने तक विमान उड़ान नहीं भर पाएंगे। इसके साथ ड्रोन व मानवरहित टोही विमानों के उड़ानों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा। यह आदेश उपराज्यपाल की सुरक्षा की नए सिरे से समीक्षा करने के बाद जारी किया। अधिकांश जिलों में पहले ही ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया है।

जम्मू में ड्रोन हमले के बाद उपराज्यपाल की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा हो गया है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के बाद भी जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में ड्रोन देखे गए। ऐसे हालात में उपराज्यपाल की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स ने निर्देश जारी किए कि देशविरोधी तत्वों से उपराज्यपाल को बड़ा खतरा है।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके में सुरक्षा बल के कैंपों पर फिर मंडराया ड्रोन

सुकमा (नईदुनिया न्यूज): छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के धुर नक्सल प्रभावित इलाकों में स्थापित सुरक्षा बल के कैंपों के ऊपर फिर ड्रोन मंडराता दिखा है। सुरक्षा बलों का मानना है कि ये ड्रोन नक्सलियों के हो सकते हैं। बीते महीने छह जून को मिनपा कैंप के ऊपर ड्रोन देखा गया था। जवान कोई कार्रवाई करते इससे पहले ही गायब हो गया। इसी तरह एक साल पहले किस्टारम और पालोडी कैंपों के ऊपर ड्रोन देखा गया था। ड्रोन देखे जाने की घटना के बाद कैंपों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है।

बड़गाम में रेलवे ट्रैक पर विस्फोटक की साजिश विफल

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर: पुलिस ने गुरुवार को बड़गाम में लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी को रेलवे क्रासिंग के पास करीब सवा किलो विस्फोटक और दो डेटोनेटर के साथ गिरफ्तार किया है। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, आतंकी श्रीनगर-बारामुला रेललाइन पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में था।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस को अपने तंत्र से पता चला था कि आतंकियों द्वारा अरछनदरहामा, मागाम में किसी वारदात को अंजाम देने की साजिश रची जा रही है। इसके आधार पर पुलिस ने रेलवे क्रासिंग के पास नाका लगाया और वहां से गुजरने वाले संदिग्ध तत्वों की निगरानी शुरू कर दी। इसी दौरान नाका पार्टी ने एक व्यक्ति को थैला लेकर वहां से गुजरते देखा। उसने अचानक अपनी चाल तेज कर दी। नाका पार्टी को उस पर कुछ संदेह हुआ और उसने उसे रुकने का संकेत किया।

कफील, इमरान व नासिर के साथ एनआइए पहुंची पटना, पेशी आज

राज्य ब्यूरो, पटना

▸ दरभंगा पार्सल विस्फोट के तीनों आरोपितों की रिमांड आज हो रही है पूरी, सलीम को ले सकती है रिमांड पर

दरभंगा पार्सल विस्फोट के आरोपित कफील, इमरान व नासिर को दिल्ली से लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की टीम गुरुवार को पटना आ गई। कड़ी सुरक्षा के बीच एनआइए तीनों को लेकर एटीएस मुख्यालय पहुंची। रात भर इन्हें एटीएस मुख्यालय में ही रखा जा सकता है। शुक्रवार को तीनों को एनआइए कोर्ट में पेश किया जाएगा। तीनों आरोपितों की रिमांड शुक्रवार को ही खत्म हो रही है।

दरभंगा रेलवे जंक्शन पर 17 जून को हुए विस्फोट की जांच कर रही एनआइए की टीम ने मामले में चार आरोपितों को पकड़ा है। हैदराबाद से पकड़े गए भाई इमरान और नसीर को एक जुलाई को पटना लाकर कोर्ट में पेश किया गया था जिसके बाद सात दिनों की रिमांड मिली थी। वहीं उत्तर प्रदेश के कैराना से गिरफ्तार दो अन्य आरोपित सलीम और कफील को दो जुलाई को पटना लाकर कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने कफील को छह दिनों की हिरासत में सौंपा, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने से सलीम को रिमांड पर नहीं सौंपा।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, बेउर जेल में बंद आरोपित सलीम की सेहत में सुधार दिख रहा है। ऐसे में एनआइए की टीम शुक्रवार को कोर्ट में सलीम को रिमांड पर लेने की अर्जी भी दे सकती है। एनआइए वापस दिल्ली ले जाकर पूछताछ करेगी।

चारों से एक साथ पूछताछ की तैयारी : एनआइए के साथ एटीएस के अफसरों ने भी दरभंगा विस्फोट मामले के आरोपितों से पूछताछ की है। एनआइए की टीम विस्फोट के मास्टरमाइंड बताए जा रहे सलीम के सामने कफील, इमरान व नासिर से पूछताछ करना चाह रही है। पिछली बार यह मुमकिन नहीं हो पाया था। सलीम को हिरासत में नहीं सौंपे जाने पर अन्य तीन आरोपितों की रिमांड बढ़ाने जाने की अर्जी कोर्ट में दी जा सकती है।

सोपोर में हिजबुल के ठिकाने से आरपीजी लांचर बरामद, ओजीडब्ल्यू गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर: सुरक्षाबल के जवानों ने गुरुवार को उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिले के सोपोर में हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने से कंधे से एंटी टैंक ग्रेनेड और राकेट दागने में सक्षम एक आरपीजी (राकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड) लांचर और 16 यूबीजी (अंडर बैरेल ग्रेनेड) बरामद किए हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में एक ओवरग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) को भी गिरफ्तार किया है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि दोपहर बाद करीब साढ़े तीन बजे सोपोर के गनई मोहल्ला दोआबगाह में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके आधार पर पुलिस ने सेना की 22 आरआर और सीआरपीएफ की 179वीं वाहिनी के साथ मिलकर गनई मोहल्ला में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने वहां छिपे हिजबुल मुजाहिदीन के एक ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस एक मकान में बने हिजबुल मुजाहिदीन के भूमिगत ठिकाने की तलाशी ली।

रघुवर दास, अनुराग गुप्ता व अजय कुमार पर लगा पीसी एक्ट

राज्य ब्यूरो, रांची

▸ हार्स ट्रेडिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बनाए गए थे अप्राथमिकी आरोपित

▸ जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर की जगह एएसपी हटिया को सौंपी गई

राज्यसभा चुनाव-2016 में हार्स ट्रेडिंग के मामले में रांची के जगन्नाथपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी में प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट (पीसी एक्ट) की धाराएं लगा दी गई हैं। रांची पुलिस ने कांड के प्राथमिकी आरोपित एडीजी अनुराग गुप्ता व पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के सलाहकार अजय कुमार के अलावा अप्राथमिकी आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराएं जोड़ने के बाद इसकी लिखित जानकारी न्यायालय को दी है। धारा जोड़ने के साथ ही इस कांड की जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर से हटाकर हटिया के एएसपी विनीत कुमार को सौंपी गई है। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के आलोक में रांची पुलिस ने कानूनी सलाह लेने के बाद राज्य सरकार की अनुमति पर यह कार्रवाई की है।

17 माह से निलंबित हैं एडीजी अनुराग गुप्ता : एडीजी अनुराग गुप्ता लगभग 17 माह से निलंबित चल रहे हैं। गत वर्ष 14 फरवरी 2020 को हेमंत सरकार ने एडीजी अनुराग गुप्ता को निलंबित कर दिया था। तब वह सीआइडी के एडीजी थे। उनके खिलाफ राज्यसभा चुनाव 2016 में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने के लिए बड़कागांव की तत्कालीन विधायक निर्मला देवी को प्रलोभन देने और उनके पति पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को धमकाने का आरोप है।

भारत निर्वाचन आयोग ने दिया था पीसी एक्ट जोड़ने का आदेश : इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) जोड़ने का आदेश भारत निर्वाचन आयोग ने ही दिया था।धारा 171बी व 171सी के अलावा पीसी एक्ट लगाने का आदेश दिया था।

जमीन घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में खडसे से पूछताछ

राज्य ब्यूरो, मुंबई


ईडी के सामने पेश होने से पहले राकांपा नेता ने जांच को राजनीति से प्रेरित बताया

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधान परिषद सदस्य एकनाथ खडसे ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होने से पहले पत्रकारों से कहा कि उनके परिवार को राजनीतिक कारणों से फंसाया जा रहा है। वह ईडी की जांच में पूरा सहयोग करेंगे। ईडी इससे पहले पुणे के भूखंड घोटाले में उनके दामाद गिरीश चौधरी को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी जमीन घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले की जांच कर रही है।

गिरीश की गिरफ्तारी के बाद बुधवार को ईडी ने एकनाथ खडसे को भी पूछताछ के लिए समन भेजा था। गुरुवार को ईडी कार्यालय पहुंचे खडसे ने बाहर खड़े पत्रकारों से संक्षिप्त बात करते हुए कहा कि मेरे खिलाफ मामला राजनीति प्रेरित है। मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को बदनाम करने के लिए राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि मैं जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रहा हूं। खडसे के अनुसार जो कुछ हो रहा है, उसे पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। इस मामले की पहले ही पांच बार जांच हो चुकी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने हमें क्लीनचिट दे दी है। फिर भी जांच की जा रही है। जबकि ईडी का आरोप है कि पुणे के भोसरी स्थित एमआइडीसी का एक भूखंड खडसे परिवार ने सिर्फ 3.75 करोड़ रुपये में खरीदा, जबकि बाजार भाव पर उसकी कीमत 31 करोड़ रुपये से अधिक थी। एजेंसी को शक है कि भाजपा सरकार में राजस्व मंत्री रहते खडसे ने अपने पद का दुरुपयोग कर इस सौदे को अंजाम दिलवाया। साथ ही इस सौदे में दिए गए धन का स्रोत भी वास्तविक नहीं था। इसका पैसा कागजी कंपनियों के जरिये दिलवाया गया। ईडी इसी मामले में खडसे से पूछताछ कर रही है। एक बार उनसे जनवरी में भी पूछताछ हो चुकी है। इस बार उन्हें उनके दामाद के सामने बैठाकर पूछताछ होनी है। इस मामले में खडसे की पत्नी भी आरोपित हैं। बता दें कि इसी मामले में गंभीर आरोप लगने के बाद खडसे को देवेंद्र फड़नवीस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना पड़ा था। वरिष्ठ नेता होने के बावजूद उन्हें हाशिये पर जाना पड़ा था।

देशमुख मामले में एनआइए कोर्ट ने दी वाझे से पूछताछ की इजाजत

▸ महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री व राकांपा नेता के दो सहयोगियों को गिरफ्तार कर चुकी है ईडी

मुंबई, प्रेट्र : एनआइए की विशेष अदालत ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ दर्ज मनी लांड्रिंग मामले में मुंबई पुलिस के बर्खास्त अधिकारी सचिन वाझे से पूछताछ की इजाजत दे दी।

वाझे को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर (अंटीलिया) के पास एक विस्फोटक लदी कार खड़ी किए जाने व ठाणे के कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या मामले में मार्च में गिरफ्तार किया था। बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि नवी मुंबई स्थित तलोजा जेल में बंद वाझे से पूछताछ के लिए ईडी को तीन दिनों का समय मिला है।

ईडी इस मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे व निजी सहायक कुंदन शिंदे को गिरफ्तार कर चुकी है। केंद्रीय एजेंसी का दावा है कि दोनों आरोपितों ने स्वीकार किया है कि वाझे ने मुंबई के आर्केस्ट्रा बार मालिकों से 4.70 करोड़ रुपये वसूले और दो किस्तों में शिंदे को सौंपा। वाझे से पूछताछ की इजाजत की मांग करते हुए ईडी ने कहा था कि वह मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के पूर्व सहायक निरीक्षक तथा पलांडे व शिंदे से एक साथ पूछताछ करना चाहती है।

उल्लेखनीय है कि वाझे की गिरफ्तारी व मुंबई पुलिस आयुक्त पद से हटाए जाने के बाद परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृहमंत्री देशमुख ने सचिन को बार व रेस्तरां से 100 करोड़ रुपये प्रतिमाह वसूली का लक्ष्य दिया था। हालांकि, देशमुख ने आरोपों से इन्कार किया था।

राज्यों व निजी अस्पतालों के पास 1.83 करोड़ डोज

टीकाकरण में तेजी ▶ राज्यों को जल्द ही 23.8 लाख टीके और मुहैया कराए जाएंगे

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि राज्यों और निजी अस्पतालों में 1.83 करोड़ से अधिक शेष और अप्रयुक्त कोरोना के टीके अभी भी उपलब्ध हैं।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 37.93 करोड़ (37,93,56,790) डोज दी जा चुकी हैं। जल्द ही 23,80,000 और डोज उपलब्ध कराई जाएंगी। मंत्रालय ने कहा कि इसमें से अपव्यय सहित कुल खपत 36,09,69,128 खुराक (गुरुवार को सुबह 8 बजे उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) है। इसमें कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन की 1.83 करोड़ (1,83,87,662) से अधिक अप्रयुक्त डोज राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास उपलब्ध हैं।

देश में टीकाकरण का नया चरण 21 जून से शुरू हुआ है। नए चरण में, केंद्र सरकार देश में निर्माताओं द्वारा उत्पादित 75 प्रतिशत टीकों की खरीद और आपूर्ति (मुफ्त में) करेगा। इससे टीकाकरण अभियान में तेजी आएगी।

देश में कोरोना की स्थिति	
भारत	
24 घंटे में नए मामले	45,892
कुल सक्रिय मामले	4,60,704
24 घंटे में टीकाकरण	36.90 लाख
कुल टीकाकरण	36.48 करोड़
गुरुवार सुबह आठ बजे तक कोरोना की स्थिति	
नए मामले	45,892
कुल मामले	3,07,09,557
मौतें	817
कुल मौतें	4,05,028
कुल सक्रिय मामले	4,60,704
ठीक होने की दर	97.18 फीसद
पाजिटिविटी दर	2.42 फीसद
मृत्यु दर	1.32 फीसद
जांचें (बुधवार)	18,93,800
कुल जांचें	42,52,25,897



कोरोना रोधी टीका लगवाने के लिए लोगों में होड़ है। गुरुवार को बंगाल के नदिया जिले में टीकाकरण केंद्र पर लोगों की कतार नजर आई। इस दौरान लोग बारिश से बचाव के लिए छाता लिए हुए थे। प्रेट्र

टीके की उपलब्धता आयात के जरिये बढ़ाने पर जोर : सरकार

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह आयात के जरिये कोरोनारोधी टीके की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में 'सक्रियता' से काम कर रही है। अभी उसका ध्यान घरेलू स्तर पर तैयार टीकों का उपयोग देश में चल रहे टीकाकरण कार्यक्रम के लिए करने पर है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने वर्चुअल प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि हमें उम्मीद है कि अन्य देश भारत निर्मित टीके को मान्यता देंगे। अभी हमारा (सरकार) ध्यान घरेलू टीका उत्पादन का अपने टीकाकरण अभियान के लिए उपयोग करने पर है। हम अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए आयात पर भी जोर देंगे।

टीकाकरण में यूपी पहले पायदान पर पहुंचा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : कोरोना वायरस से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में यूपी अब पहले नंबर पर आ गया है। गुरुवार को महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर यूपी पहले पायदान पर पहुंच गया। यूपी में कुल 3.59 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी है। यहां 3.04 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली और 55.22 लाख लोगों को दूसरी डोज लगाई गई है। देश में सर्वाधिक तीन करोड़ से ज्यादा लोगों को टीके की पहली डोज भी यूपी में ही लगाई गई है। महाराष्ट्र में कुल 3.57 करोड़ टीके लगाए गए हैं। यहां 2.82 करोड़ लोगों को टीके की पहली और 75.17 लाख लोगों को दूसरी डोज लगाई गई है।

3.59 करोड़ वैक्सीन लगाकर महाराष्ट्र को पिछाड़ा

सनोफी-जीएसके की वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण को मंजूरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : दवा निर्माता कंपनी सनोफी और जीएसके को भारत में कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के क्लीनिकल परीक्षण के लिए मंजूरी मिल गई है। यह परीक्षण कंपनी की वैक्सीन की सुरक्षा, प्रभावकारिता और प्रतिरक्षात्मकता का आकलन करने को लेकर किया जाएगा।

सनोफी की ओर से गुरुवार को बताया गया कि वैश्विक स्तर पर किए जाने वाले वैक्सीन परीक्षण का तीसरे चरण का अध्ययन 18 प्लस आयु वर्ग के 35 हजार वालंटियर पर किया जाएगा। इसमें अमेरिका, एशिया और लैटिन अमेरिका के लोग भाग लेंगे। सनोफी पाश्चर इण्डिया की प्रमुख अन्नपूर्णा दास ने कहा कि भारत सनोफी पाश्चर के निर्णायक तीसरे चरण के अध्ययन में भाग ले रहा है। जहां तक मंजूरी की बात है तो हम जल्द ही देश में परीक्षण में लोगों का पंजीकरण शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना का वायरस लगातार खुद को बदल रहा है। अभी हम अंदाजा ही लगा सकते हैं कि आने वाले महीनों और सालों में इसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए।

हरिद्वार कुंभ : कोरोना टेस्टिंग फर्जीवाड़े पर ईडी की भी नजर

जागरण संवाददाता, देहरादून

- जून के पहले सप्ताह में सामने आई थी हरिद्वार कुंभ में हुई कोरोना जांच की गड़बड़ी
- अनुबंधित लैब को किए गए भुगतान को मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़कर देखा जा रहा

हरिद्वार कुंभ में कोरोना जांच घोटाले में मैक्स कारपोरेट सर्विसेज और उसकी सहयोगी दो लैब पर मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद अब इस मामले में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की निगाह की टेढ़ी हो गई है। ईडी अधिकारी भी पूरे मामले पर निगाह बनाए हुए हैं। जून के पहले सप्ताह कोरोना टेस्टिंग में फर्जीवाड़ा सामने आया था।

कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की कोरोना जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 22 लैब का चयन किया था। इनमें छह लैब दिल्ली और हरियाणा की थी। कोरोना जांच करने वाली दो लैब हिसार हरियाणा की नलवा लैबारेटरी और नई दिल्ली की डा. लालचंदानी लैब ने मैक्स कारपोरेट सर्विसेज के अधीन काम किया। प्रारंभिक जांच में इन दोनों लैब की जांच में गड़बड़ी पकड़ में आई है। इन पर कोरोना जांच का फर्जी डाटा फीड करने और पूरा लेखा-जोखा वेबसाइट पर अपलोड न करने का आरोप है। हरिद्वार के सीएमओ डा. शंभू कुमार झा ने इन दोनों लैब के साथ ही इनके लिए अनुबंध करने वाली फर्म मैक्स कारपोरेट के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी करके सरकारी धन हड़पने की कोशिश करने का मुकदमा दर्ज कराया हुआ है। हालांकि जांच के दायरे में सभी अनुबंधित लैब हैं, लेकिन फिलहाल गड़बड़ी इन्हीं दो लैब की पकड़ में आई हैं। शासन के निर्देश पर हरिद्वार के डीएम इस प्रकरण की जांच सीडीओ की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय कमेटी से करा रहे हैं। जबकि सीएमओ के स्तर से दर्ज कराए गए मुकदमे की जांच एसआइटी कर रही है। अभी सभी जांच जारी हैं, इस बीच यह भी पता चला कि स्वास्थ्य विभाग के स्तर से अनुबंधित लैबों को करीब तीन करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। कोरोना जांच की एवज में कुल बिल की रकम लगभग 40 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। अब इस प्रकरण में नया मोड़ आता दिख रहा है। क्योंकि ईडी पर भी कोरोना जांच घोटाले को लेकर गोपनीय ढंग से आगे बढ़ रहा है। हालांकि, अभी ईडी ने सीधे तौर पर जांच शुरू नहीं की है। बताया जा रहा है कि कोरोना जांच की एवज में अनुबंधित लैब द्वारा अब तक करीब तीन करोड़ रुपये का भुगतान प्राप्त करने को ईडी मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़कर देख रहा है। यदि ईडी के हाथ कुछ ठोस साक्ष्य लगते हैं तो ईडी अधिकारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई कर सकते हैं।

कोरोना संक्रमित होने के 39 दिन बाद भी टिश्यू में मिला वायरस, बढ़ी चिंता

नईदुनिया, भोपाल

- एम्स भोपाल में कोरोना के 21 मरीजों के शव का किया गया पोस्टमार्टम
- शोध में सामने आया कि रिपोर्ट निगेटिव होने के बाद भी मौजूद था वायरस

अभी तक यह माना जा रहा था कि कोरोना की जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन एक शोध में सामने आया है कि कुछ मरीजों में कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव होने के बाद भी टिश्यू (ऊतक) में वायरस मौजूद रहता है। यह तथ्य अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भोपाल में हुए शोध में सामने आया है। एम्स में कोरोना के 21 मरीजों के शव का पोस्टमार्टम किया है। जिस शव के टिश्यू में वायरस मिला है, वह संक्रमित होने के बाद 39 दिन तक एम्स में भर्ती था। यानी यह कहा जा सकता है कि संक्रमित होने के 39 दिन बाद भी टिश्यू में वायरस मौजूद रह सकता है।

यह बात एम्स के निदेशक प्रो. डा. सरमन सिंह ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कही। इस दौरान एम्स की फोरेंसिक मेडिसिन विभागाध्यक्ष डा. अरनीत अरोरा भी मौजूद थीं। देश में पहली बार एम्स भोपाल में कोरोना मरीजों के शव का पोस्टमार्टम शोध के मकसद से किया गया था। शोध में यह भी पता चला है कि कोरोना वायरस फेफड़े के अलावा मस्तिष्क, किडनी, लिवर, पैंक्रियाज में भी पहुंचता है।

मुख्य शोधकर्ता फोरेंसिक मेडिसिन विभाग की अतिरिक्त प्राध्यापक डा. जयंती यादव ने बताया कि जिस मरीज के टिश्यू में कोरोना वायरस मिला, इलाज के दौरान उसकी कोरोना की जांच रिपोर्ट निगेटिव आ गई थी। संक्रमित होने के 39 दिन बाद मरीज की मौत हो गई। शोध के मकसद से मरीज के फेफड़े और अन्य अंगों से टिश्यू लेकर आरटीपीसीआर जांच कराई गई। इसमें फेफड़े समेत कुछ अंगों में वायरस मिला है। शोध में प्राध्यापक डा. शशांक पोरवार, एनेस्थीसिया के अतिरिक्त प्राध्यापक डा. सौरभ सहगल और पैथोलाजी विभाग के फैकल्टी डा. अश्वनी टंडन और डॉ. गरिमा गोयल शामिल थीं।

सबसे ज्यादा फेफड़े व सबसे कम लिवर को हुआ नुकसान

डा. अरनीत अरोरा ने बताया कि 12 शव की जांच में नौ में यानी 75 फीसद के पैंक्रियाज में कोरोना वायरस मिला है। इनमें पैंक्रियाइटिस (पैंक्रियाज में सूजन) भी देखने को मिली है। बता दें कि पैंक्रियाज में मौजूद बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं, जिससे शुगर नियंत्रित रहती है। उन्होंने बताया कि 57 फीसद शवों में लिवर में वायरस मिला है, लेकिन लिवर में ज्यादा नुकसान नहीं मिला है। सबसे ज्यादा 90 फीसद फेफड़े में वायरस मिला है। सबसे ज्यादा नुकसान भी फेफड़े को हुआ है। मस्तिष्क में 47 फीसद में वायरस मिला है। इसके चलते करीब 24 फीसद के मस्तिष्क में छोटे हेमरेज मिले हैं। इससे खून का रिसाव भी हुआ था। हालांकि, बड़े हेमरेज नहीं मिले हैं, जिससे मरीज की मौत हो सके। खून का थक्का जमा होने के प्रमाण भी हिस्टोपैथोलॉजी जांच में मिले हैं, लेकिन इसके चलते किसी को हार्ट अटैक नहीं हुआ।

गुजरात सरकार ने शर्तों के साथ दी रथ यात्रा को हरी झंडी

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद : भगवान जगन्नाथ की 144वीं रथ यात्रा को गुजरात सरकार की हरी झंडी मिल गई है। कर्फ्यू के बीच कोविड नियमों का पालन करते हुए अखाड़े, भजन मंडलियों व झांकियों के बिना ही रथ यात्रा निकाली जाएगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 12 जुलाई की सुबह भगवान जगन्नाथ की मंगल आरती में सपरिवार शामिल होंगे।

प्रदेश के गृह राज्यमंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने गुरुवार को बताया कि महामारी संबंधी दिशा-निर्देशों के पालन करने की शर्त पर रथ यात्रा को मंजूरी दी गई है। भगवान के रथों को खींचने वालों के लिए 48 घंटे पहले के आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट व कोविड वैक्सीन की कम से कम एक डोज लेना अनिवार्य होगा। 12 जुलाई को सुबह सात बजे अहमदाबाद स्थित मंदिर परिसर से रथ यात्रा प्रारंभ होगी। दोपहर दो बजे तक यात्रा को पूर्ण करना होगा। भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा व बलभद्र के रथ के साथ महंत दिलीप दासजी महाराज के वाहन व चार अन्य यात्रा में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल सोने का झाड़ू लगाकर यात्रा रवाना करेंगे।

कोविड अस्पतालों में सेवा देने वाले मेडिकल छात्रों को नौकरी में मिलेगी प्राथमिकता

राज्य ब्यूरो, रांची

कोविड अस्पतालों में इलाज करनेवाले मेडिकल व नर्सिंग के छात्रों को राज्य में होनेवाली स्थायी नियुक्ति में प्राथमिकता मिलेगी। इसका लाभ अनुबंध पर काम करनेवाले वैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल को मिलेगा, जो अनुबंध पर कोविड अस्पतालों में काम कर रहे हैं या करेंगे। इसके लिए उन्हें न्यूनतम 100 दिन कोविड अस्पतालों में सेवा देना जरूरी होगा।

राज्य सरकार ने चिकित्सकों की कमी को देखते हुए केंद्र की अनुशंसा पर अंतिम वर्ष में पढ़नेवाले पीजी मेडिकल, एमबीबीएस तथा बीएससी नर्सिंग के छात्र-छात्राओं को कोविड अस्पतालों में अनुबंध पर बहाल करने का निर्णय लिया है। इमरजेंसी कोविड-19 रिस्पांस प्लान के तहत छह श्रेणियों में मानदेय के आधार पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल बहाल किए जाएंगे। इनका मानदेय भी तय कर दिया गया है, जिसका भुगतान क्रिटिकल केयर के तहत आवंटित राशि से होगा। साथ ही इन्हें बीमा योजना का भी लाभ मिलेगा। प्रत्येक जिले में विज्ञापन प्रकाशित कर ऐसे छात्रों की बहाली अनुबंध पर छह माह के लिए कोविड अस्पतालों में की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। न्यूनतम 100 दिनों तक कोविड अस्पतालों में सफलतापूर्वक कार्य किए जाने पर इन्हें स्थायी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। झारखंड सरकार के इस पहल से दूसरे राज्य में ऐसी संभावना बन सकती है।

अच्छी पहल

किसको मिलेगा कितना मानदेय	
पीजी मेडिकल के अंतिम वर्ष के छात्र	3500 रुपये
एमबीबीएस डॉक्टर (नीट)	2000 रुपये
इंटर्न मेडिकल छात्र	1500 रुपये
एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के छात्र	1200 रुपये
बीडीएस या आयुष	800 रुपये
बीएससी नर्सिंग, जीएनएम की अंतिम वर्ष की छात्रा	550 रुपय

सर्टिफिकेट के लिए एनसीसी ने घटाए कैंप के दिन

निशांत यादव, लखनऊ : कोरोना काल में एक तरफ जहां आफलाइन शैक्षणिक गतिविधियां ठहर गई हैं, वहीं एनसीसी के कैडेटों के भविष्य पर भी कैंप में हिस्सा न लेने से संकट खड़ा हो गया था। सेना में अफसर व जवान बनने समेत कई तरह के प्रवेश के लिए नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) के सी व बी सर्टिफिकेट का होना जरूरी होता है। ऐसे में कोरोना के कारण बंद चल रहे कैंप को एनसीसी ने फिर लगाया और कई कैडेटों को बी तथा सी सर्टिफिकेट जारी किए। इससे वह अब प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा ले सकेंगे। एनसीसी ने भी अन्य शैक्षणिक संस्थानों की तरह अपना एकेडमिक कोर्स आनलाइन कराने की व्यवस्था की थी। इसके लिए एनसीसी महानिदेशालय दिल्ली ने एक एप भी लांच किया था, लेकिन एनसीसी कैडेटों के सामने सबसे बड़ा संकट कैंप को लेकर था। बिना शिविर लगाए उन्हें बी और सी सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता था। इस कारण उनको एनडीए, सेना और अन्य जगहों पर आवेदन में दिक्कत आ रही थी।

राष्ट्रीय फलक

'जम्मू' ने परिसीमन आयोग को बताया वर्षों से दिल में दबा खुद से हुए भेदभाव का दर्द

राज्य ब्यूरो, जम्मू

जम्मू-कश्मीर में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए परिसीमन आयोग कश्मीर के बाद गुरुवार को जम्मू पहुंचा तो लोगों के दिलों में वर्षों से दबा भेदभाव का दर्द बाहर आ गया। आयोग की सदस्य जस्टिस (सेवानिवृत्त) रंजना देसाई ने बैठकों में जब जम्मू संभाग के लोगों की राय ली तो मानो उन्होंने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। बोले- जम्मू-कश्मीर में परिसीमन के नाम पर अब तक जालसाजी होती रही। दशकों तक सत्ता में रहे कश्मीरी दलों ने बंदरबांट कर जम्मू संभाग के हाथ हमेशा खाली रहे। अब अब पुरानी गलतियों को सुधारा जाए और जम्मू संभाग को उसका हक दिया जाए, जो उससे छीना गया है।

जम्मू की राजनीतिक पार्टियों ने भेदभाव के सुबूत भी आयोग को सौंपे हैं। बैठक में गुलाम कश्मीर कोटे की सीटों को डीफ्रीज कर इन्हें जम्मू-कश्मीर में बसे उपेक्षित वर्गों के लोगों को देने की मांग की गई हे। साथ ही कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर में ही तीन सीटें आरक्षित करने की आवाज भी उठी है।

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत ही परिसीमन आयोग का मार्च 2020 में गठन किया है। परिसीमन आयोग को मार्च 2022 तक या उससे पहले जम्मू-कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा करना है। जम्मू-कश्मीर में मौजूदा 107 निर्वाचन क्षेत्रों को बढ़ाकर 114 करने का प्रस्ताव है। परिसीमन आयोग गत मंगलवार को पहली बार जम्मू-कश्मीर के चार दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुंचा था। इसके बाद यह जम्मू संभाग में दूरदराज पहाड़ी जिले किश्तवाड़ में जन आकांक्षाएं जानकर गुरुवार दोपहर तीन बजे जम्मू पहुंचा। जम्मू में आठ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडलों के अलावा क्षेत्र के सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक, कश्मीर पंडितों, गुलाम कश्मीर, पश्चिम पाकिस्तान से आए लोगों व जनप्रतिनिधियों के 96 प्रतिनिधिमंडलों ने आयोग से मुलाकात की। जम्मू में आयोग का दौरान अतिव्यस्त रहा। मिलने वाले सियासी दलों में भाजपा, बसपा, माकपा, कांग्रेस, नेकां, पीपुल्स कांफ्रेंस, जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी, नेशनल पैंथर्स पार्टी शामिल रही।

आज चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक

जम्मू से पहले परिसीमन आयोग की टीम ने कश्मीर संभाग व जम्मू के किश्तवाड़ में बैठकें कर जनआकांक्षाओं की जानकारी ली। आयोग शुक्रवार को दिल्ली लौटने से पहले कुछ प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात करने के साथ ही चुनाव विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेगा।

राष्ट्रवादी सोच के साथ मुस्लिमों को जोड़ने की पहल करेगा संघ

प्रांत प्रचारकों की बैठक

राजीव द्विवेदी, चित्रकूट

संघ प्रमुख मोहन भागवत के गाजियाबाद में दिए बयान का निहितार्थ प्रभु श्रीराम की तपोभूमि में समझ में आ रहा है। अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की मुख्य बैठक शुरू होने से पहले कोर ग्रुप सदस्यों की संक्षिप्त बैठकों में हुए विमर्श से भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संघ मुस्लिमों को राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ने की पहल करेगा। गुरुवार को कोर ग्रुप की बैठक में योगी सरकार के कामकाज और उसके जनप्रभाव को लेकर भी चर्चा हुई।

प्रांत प्रचारकों की बैठक में आने से पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने गाजियाबाद में कहा था कि पूजन विधि के आधार पर हिंदू और मुसलमानों को अलग नहीं किया जा सकता। सभी भारतीयों का डीएनए एक ही है। उन्होंने भाषा, प्रांत और अन्य विषमताओं को छोड़ एक होकर भारत को विश्वगुरु बनाने की हिमायत भी की थी। प्रचारकों की बैठक शुरू होने से पहले ही समझ में आने लगा है कि संघ ने राष्ट्रवादी सोच के साथ मुस्लिमों को भी जोड़ने का मन बना लिया है। बैठक से पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ अलग-अलग हुईं संक्षिप्त बैठकों में इसपर विमर्श भी किया गया। संघ की सोच में आ रहे बदलाव को बंगाल चुनाव से भी जोड़ कर देखा जा रहा है। शीर्ष नेतृत्व बंगाल में भाजपा के बढ़े प्रभाव को लेकर तो संतुष्ट है पर मुस्लिमों की राष्ट्रवादी सोच वाले दल से दूरी को लेकर फिक्रमंद भी है।

पांच राज्यों के चुनाव को लेकर चर्चा: संघ के शीर्ष नेतृत्व के बीच अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व पंजाब सहित पांच राज्यों में चुनाव के अलावा गुजरात में साल के अंत में होने वाले चुनाव को लेकर लेकर भी चर्चा हुई। माना जा रहा कि बैठक के बाद संघ द्वारा भाजपा को चुनाव के मद्देनजर खास सलाह भी दी जा सकती है।

संघ की शाखाओं का संचालन शुरू करने पर होगा फैसला: चित्रकूट में शुक्रवार से शुरू हो रही अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की बैठक में आगामी कार्य योजनाएं तय की जाएंगी। कोरोना संक्रमण के बाद सामान्य होते जनजीवन के बीच शाखाओं के संचालन, शिक्षा वर्ग पर विचार होगा।

जल्द बनवाएं मंदिर, चंपत राय से बोले महंत

जागरण संवाददाता, चित्रकूट

वर्षों के विवाद के पटाक्षेप के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर हर कोई जल्द से जल्द देखना चाहता है। गुरुवार को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से यहां के महंतों ने यह इच्छा जताई तो उन्होंने आश्वस्त किया कि दो से तीन साल में काम पूरा हो जाएगा।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की प्रांत प्रचारकों की बैठक में शामिल होने चित्रकूट आए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय गुरुवार को महंतों से मिले। रामायणकुटी में हुई बैठक में दिगंबर अखाड़ा के महंत दिव्यजीवन दास ने उनसे कहा कि देर हुई तो तमाम बुजुर्गों का जन्मभूमि में राममंदिर देखने का सपना अधूरा रह जाएगा। महासचिव ने बताया कि मंदिर का फाउंडेशन तैयार करने में दिक्कत है। रामजन्मभूमि स्थल की नींव खोदाई में नीचे बालू ही बालू निकल आई है। मजबूती के लिए डस्ट, राख और सीमेंट से प्लेटफार्म तैयार किया जा रहा है। एक फीट लेयर जमाने में एक दिन लग रहा है। अभी धरातल तक काम हो पाया है।

84 कोसी परिक्रमा में जुड़े रामपथ गमन मार्गः संतों ने महासचिव से चित्रकूट का विकास अयोध्या की तर्ज पर कराने बात रखी। कहा, रामवनगमन पथ को चित्रकूट की चौरासी कोसी परिक्रमा से जोड़ा जाए। इनकी हर साल संत परिक्रमा करते हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने गुरुवार को भगवान कामतानाथ के दरबार में मत्था टेका।

किसान विरोधी

महाराष्ट्र के किसानों को बर्बाद कर देगा 'नया कानून'

कृषि विशेषज्ञ ने कहा, इतने कड़े कानून में तो कोई किसानों से कांट्रैक्ट करेगा ही नहीं

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन नए कृषि कानूनों के जवाब में महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार अपने कृषि कानून बनाने जा रही है। इसका मसौदा भी विधानमंडल के मानसून सत्र में पेश कर दिया गया है, लेकिन कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि प्रस्तावित कानून राज्य के किसानों को लाभ देने के बजाय और बर्बाद कर देंगे।

बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने सिर्फ दो दिन के लिए बुलाए गए मानसून सत्र के आखिरी दिन कृषि कानून का मसौदा विधेयक पेश किया है। यह विधेयक उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने तैयार किया है। राज्य सरकार इसे केंद्र के कृषि कानूनों से संबंधित तीन संशोधन बिल बता रही है। इसे दो माह तक सभी पक्षकारों के विचार-विमर्श एवं चर्चा के लिए रखा जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राजस्व मंत्री बालासाहब थोराट का कहना है कि केंद्र के कृषि कानून बिना चर्चा के पारित किए गए। राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है और हम केंद्र के कृषि कानूनों में संशोधन का सुझाव देना चाहते हैं।

- दो माह तक सभी पक्षकारों के विचार-विमर्श एवं चर्चा के लिए रखा जाएगा



किसानों की हित की बात फाइल फोटो

कुछ माह पहले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार एवं आंदोलनरत किसानों के बीच गतिरोध दूर करने के लिए बनाई गई समिति के एक सदस्य अनिल घनवट कहते हैं कि राज्य सरकार के मसौदा विधेयक में व्यापारियों को किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से अधिक कीमत पर करार करने की बात की जा रही है। साथ ही, समझौते में किसी प्रकार का उल्लंघन होने पर तीन साल की जेल या पांच लाख रुपये जुर्माना या दोनों का प्रविधान किया गया है। इतने बंधन लगाने पर तो कोई किसानों से कांट्रैक्ट करेगा ही नहीं। महाराष्ट्र पुनः लाइसेंस-परमिट राज को बढ़ावा देता दिखाई दे रहा है।

कृषि विशेषज्ञ घनवट के अनुसार मसौदा विधेयक में एक अपीलेट अथारिटी बनाने की बात की गई है। बिल्कुल यही कानून 2006 में महाराष्ट्र सरकार ने बनाया था। आज तक सरकार उस सक्षम अधिकारी या उस अपीलेट अथारिटी के बारे में किसानों को बता नहीं पाई, जहां किसान शिकायत दर्ज करा सकें। वर्ष 2021 में भी वही बात की जा रही है।

घनवट के अनुसार राज्य सरकार उत्पादन, आपूर्ति एवं कृषि उत्पादों के आवागमन को नियंत्रित करने की भी बात कर रही है। ये कानून लागू होंगे तो किसान कमाएगा कैसे। इससे तो किसान और बर्बाद हो जाएगा। घनवट कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति अपनी रिपोर्ट न्यायालय को दे चुकी है।

पीएम ने सायरा बानो खान को दी सांत्वना

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई : हिंदी सिनेमा में ट्रेजडी किंग के तौर पर प्रख्यात दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के निधन के कुछ क्षणों बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना प्रकट की थी। उन्होंने गुरुवार की सुबह दिवंगत अभिनेता की पत्नी सायरा बानो को फोन कर सांत्वना दी और संवेदना प्रकट की। इसकी जानकारी स्वयं सायरा बानो ने दिलीप कुमार के ट्विटर अकाउंट से साझा की।

पीएम मोदी को धन्यवाद करते हुए लिखा, 'माननीय प्रधानमंत्री जी, सुबह आपके विनम्र फोन काल और संवेदना के लिए धन्यवाद। -सायरा बानो खान।' दिलीप कुमार का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ करने के लिए भी सायरा ने पीएम मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का शुक्रिया अदा किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी सायरा बानो को पत्र लिखकर संवेदना प्रकट की।

गैस रिसाव मामले में एनजीटी ने डाला 10 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति

जागरण संवाददाता, अमरोहा

- गजरौला की तेवा एपीआइ के खिलाफ सुनवाई पर फैसला
- शहर में ही जनहित के कार्यों में खर्च करने के भी आदेश दिए

तेवा एपीआइ पर गैस रिसाव मामले में एनजीटी (राष्ट्रीय हरित अभिकरण) ने कंपनी को जिम्मेदार मानते हुए 10 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया है। यह रकम एक माह में जिला मजिस्ट्रेट के यहां जमा करने का आदेश दिया है।

औद्योगिक नगरी में सात जून और दस जून 2020 को गैस रिसाव हुआ था। इससे लोगों को खासी परेशानी हुई थी। इसकी सूचना पर दमकल विभाग की टीम जांच को मंडी रोड स्थित तेवा एपीआइ कंपनी पहुंची। दमकल के चीफ फायर अधिकारी के वर्मा ने फैक्ट्री के एक प्लांट से लीकेज होते पाया था। बाद में प्रदूषण नियंत्रण समेत कई विभागों की संयुक्त जांच टीम के निरीक्षण में भी खामियां पाई गईं थीं। इस मामले को लेकर खादगुजर चौराहा निवासी जितेंद्र सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता मानसी चाहल ने एनजीटी में केस दायर किया था। एनजीटी ने इस मामले में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व कंपनी इत्यादि पक्षों को नोटिस जारी कर रिपोर्ट तलब की। इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत छह जुलाई को एनजीटी ने अपना आदेश सुना दिया।

अधिवक्ता मानसी चाहल के अनुसार गैस रिसाव मामले में एनजीटी ने तेवा एपीआइ के खिलाफ फैसला सुनाया है। आनलाइन सुनवाई के बाद एनजीटी ने कंपनी को गैस रिसाव व अन्य बिंदुओं के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। छह जुलाई को यह आदेश पारित हुआ है।

दैनिक जागरण

परिवर्तन में कोई बुराई नहीं यदि वह सही दिशा में हो

नियंत्रण से बाहर जाता बंगाल

मंत्रियों से अपेक्षाएं

केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल नवनियुक्त मंत्रियों ने अपना कामकाज संभाल लिया। इनमें नए मंत्री भी हैं और पुराने भी, लेकिन उनके सामने चुनौतियां एक जैसी हैं और सबसे बड़ी चुनौती है कम समय में ज्यादा काम करने की तथा प्रधानमंत्री के साथ-साथ जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की। उम्मीद की जाती है कि सभी मंत्री अपने समक्ष उपस्थित चुनौतियों से भली तरह परिचित होंगे और उनका सामना बेहतर ढंग से करेंगे। यह स्वाभाविक है कि जो नेता पहली बार मंत्री बने हैं और खासकर कैबिनेट मंत्री, उन पर सबसे अधिक निगाहें होंगी। वैसे तो नए मंत्रियों में कई ऐसे हैं, जिन्होंने सबका ध्यान आकर्षित किया, लेकिन इनमें से एक प्रमुख नाम है अश्विनी वैष्णव का, जो राज्यसभा सदस्य से सीधे कैबिनेट मंत्री बने। मंत्रिपरिषद में उनकी उपस्थिति ने विदेश सेवा के पूर्व अधिकारियों एस जयशंकर और हरदीप पुरी का स्मरण कराया, जो सीधे मंत्री बने थे। यह एक नया प्रयोग है, लेकिन यह जारी रहना चाहिए, क्योंकि योग्य एवं दक्ष व्यक्ति कहीं भी हो, उनका शासन संचालन में सहयोग लिया जाना चाहिए। अश्विनी वैष्णव वैसे तो पूर्व आइएएस अधिकारी हैं, लेकिन उन्हें तकनीक और प्रबंधन का भी विशेषज्ञ माना जाता है। उनकी एक पहचान यह भी है कि वह प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में पीएमओ में उपसचिव भी रहे हैं। उन्हें ओडिशा में तूफान के बाद चलाए गए प्रभावी राहत कार्य के लिए भी जाना जाता है। अब उन्हें रेलवे, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्री के रूप में चुनौतियों का सामना करना है।

यह अच्छा है कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का काम संभालने के पहले ही दिन अश्विनी वैष्णव ने अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए दो टूक कहा कि भारत में रहने और काम करने वालों को देश के नियम मानने ही होंगे। निःसंदेह उनका इशारा ट्विटर की ओर था, जो इंटरनेट मीडिया के लिए तय किए गए नियमों को मानने से कन्नी काट रहा है। हालांकि इस पर उसे दिल्ली उच्च न्यायालय से फटकार सुनने को मिली है, लेकिन अभी यह कहना कठिन है कि वह आसानी से सीधे रास्ते पर आ जाएगा। नए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में अश्विनी वैष्णव को यह सुनिश्चित करना होगा कि ट्विटर और अधिक हीलाहवाली न करने पाए। बेशक ट्विटर अमेरिका की एक बड़ी कंपनी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह भारत में काम करते हुए यहां के नियम मानने से इन्कार करे। आखिर जब इंटरनेट आधारित अन्य सोशल नेटवर्क साइट को सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी नए नियम मान्य हैं तो फिर ट्विटर को क्या परेशानी है? स्पष्ट है कि वह अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। उसे ऐसे रवैये के लिए सबक सिखाने में देर नहीं की जानी चाहिए।

मानवीय पहल

कोरोना काल में सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बचाने वाली राम मनोहर लोहिया संस्थान लखनऊ की रेजीडेंट डॉक्टर शारदा सुमन के इलाज के लिए डेढ़ करोड़ रुपये मंजूर करके प्रदेश सरकार ने बड़ा मानवीय संदेश दिया है। लोहिया संस्थान में भर्ती पीड़ित के पति भी यूं तो बिहार में रेजीडेंट डाक्टर हैं, लेकिन दोनों के ही स्वजन इतना खर्च उठा सकने की स्थिति में नहीं। इसे देखकर ही लोहिया संस्थान के वरिष्ठ डाक्टरों ने मुख्यमंत्री से मदद मांगी थी। बताया था कि करीब डेढ़ महीने से इकमो मशीन यानी आर्टिफिशियल लंग्स और हार्ट मशीन के सहारे सांसें ले रही डाक्टर को बचाने का इकलौता रास्ता लंग्स ट्रांसप्लांट ही है। यह भी चेन्नई अथवा हैदराबाद में होगा। इतनी जानकारी के बाद सिर्फ तीन दिन में ही रकम मंजूर कर ली गई। डाक्टर अप्रैल में तब संक्रमित हुई थीं, जब महामारी रौद्र रूप दिखाने पर आमादा थी। गर्भवती होने के बावजूद उन्होंने कोई अवकाश नहीं लिया और दिन-रात कोरोना पीड़ित महिलाओं की डिलीवरी व अन्य संक्रमितों के इलाज में जुटी रहीं। अतिगंभीर हाल में ही उन्होंने एक मई को बच्ची को जन्म दिया है। पैसे का बंदोबस्त हो जाने के बाद डाक्टर मां को भी बचाने की प्रबल संभावना बन गई है। महामारी ने लाखों लोगों को जख्म दिए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक दूसरी लहर में शहीद हुए देश के 594 डाक्टरों में से 67 उत्तर प्रदेश के थे। विकट परिस्थितियों और मनोबल तोड़ने वाली अनेक घटनाओं के बावजूद कोरोना वारियर मरीजों को बचाने के लिए जूझते रहे। ऐसे ही एक जुझारू डाक्टर को बचाने के लिए बड़ा आर्थिक सहयोग करने का संदेश भी इसीलिए व्यापक है और इस लड़ाई में जुटे हर वर्ग का हौसला बढ़ाने वाला भी। इससे वैश्विक महामारी से निपटने में लगे डाक्टरों, स्टाफ नर्सों और अन्य सहयोगियों को बहुत संबल मिलेगा।

एक कोरोना वारियर के इलाज का खर्च प्रदेश सरकार के उठाने से महामारी से निपटने में लगे डाक्टरों, स्टाफ नर्सों और अन्य सहयोगियों को बड़ा संबल मिलेगा



सुरेंद्र किशोर

ममता बनर्जी के राज में जो हो रहा है उसे देखकर यही लगता है कि बंगाल और कश्मीर के बीच का अंतर मिटता जा रहा है

विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में जो हुआ या अभी भी हो रहा है, वैसा स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। क्या इससे पहले किसी मुख्यमंत्री ने इस देश के गृह मंत्री को सार्वजनिक रूप से गुंडा कहा? बिल्कुल नहीं, किंतु ममता ने ऐसा कहा। इससे पहले ममता ने 2016 में कोलकाता में सेना के अभ्यास पर सख्त एतराज जताया था। उससे लगा कि उनमें या तो अलगाववादी प्रवृत्ति उभर रही है या फिर मोदी सरकार के विरोध में उन्होंने अपना मानसिक संतुलन ही खो दिया है। ममता ने आरोप लगाया था कि सेना हमारी सरकार को अपदस्थ करना चाहती है। याद रहे कि तब कोलकाता के टोल प्लाजा पर सेना की तैनाती हुई थी। सेना ने कहा था कि हमारे लोग सिर्फ कोलकाता में ही नहीं, बल्कि देश के कुल नौ राज्यों के 80 स्थानों में ऐसा अभ्यास कर रहे हैं। तत्कालीन रक्षा मंत्री के अनुसार इसकी सूचना बंगाल पुलिस को दे दी गई थी। कालांतर में भी ममता केंद्र और उसकी संस्थाओं से टकराव पर आमादा रही हैं। उन्होंने तमाम केंद्रीय योजनाओं को बंगाल में लागू करने से भी परहेज किया है।

कई बार तो ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी को इस देश की न्यायपालिका में भी विश्वास नहीं। अदालती आदेश पर सीबीआइ सारदा और रोज वैली पोंजी घोटालों की जांच कर रही है। इस संबंध में पूछताछ के लिए सीबीआइ कोलकाता पुलिस आयुक्त के आवास पर पहुंची तो सीबीआइ टीम के साथ ही बदसुलूकी हुई। उस पूरे अभियान की कमान भी ममता ने ही संभाली हुई थी। वह सीबीआइ के खिलाफ धरने पर बैठ गईं। क्या आपने इससे पहले कभी किसी मुख्यमंत्री को एक आरोपी अफसर के पक्ष में धरने पर बैठने के बारे में देखा-सुना था? प्रधानमंत्री मोदी जब चक्रवात प्रभावित बंगाल में राहत के लिए अहम बैठक के लिए पहुंचे तो ममता ने न केवल खुद उस बैठक से कन्नी काटी, बल्कि अपने मुख्य सचिव को भी उसमें शामिल नहीं होने दिया।

ममता सरकार और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विपक्ष विशेषकर भाजपा के खिलाफ जैसी निर्ममता की उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। बंगाल में केंद्रीय मंत्रियों तक के साथ दुर्व्यवहार किया गया। चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव बाद बंगाल के हालात देखकर तो यही लगता है कि बंगाल और कश्मीर के बीच अंतर मिटता जा रहा है। हालात इतने भयावह हो गए कि राज्य में भाजपा समर्थकों को अपनी जान बचाने के लिए पड़ोसी राज्यों में शरण लेनी पड़ी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इस राज्य प्रायोजित हिंसा की पड़ताल का निर्देश दिया। हद तो तब हो गई जब जांच के लिए गई आयोग की टीम को भी हमलों का शिकार होना पड़ा।



अवधेश राजपूत

कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल पुलिस को निर्देश दिया है कि वह चुनावी हिंसा के सभी पीड़ितों के केस दर्ज करे। देखना है कि बंगाल पुलिस अदालती आदेश का पालन करके पीड़ितों को न्याय दिलाती है या नहीं? राज्य के मुख्य विपक्षी दल के प्रति शत्रुवत व्यवहार लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक है। इस परिदृश्य को देखते हुए यही लगता है कि भविष्य में जब केंद्र सरकार बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और एनआरसी लागू करने की कोशिश करेगी तो बंगाल में अभूतपूर्व हिंसा देखने को मिल सकती है। इन मुद्दों पर ममता का विरोध इस तथ्य के बावजूद है कि 2005 में उन्होंने ही लोकसभा में अवैध घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था। तब राज्य में वाम सरकार थी, जो घुसपैठियों को संरक्षण दे रही थी। अब स्थिति बदल गई है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के एकमुश्त वोट चूंकि ममता की पार्टी को मिलने लगे हैं इसलिए उनका रवैया बदल गया है। ममता अब कह रही हैं कि अगर बंगाल में सीएए और एनआरसी लागू हुआ तो राज्य में खून की नदियां बहेंगी। बंगाल विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतों की अभूतपूर्व एकजुटता का एक बड़ा कारण यह भी रहा। केरल में भी इस बार ऐसी ही एकजुटता दिखी। केरल के मार्क्सवादी मुख्यमंत्री पी. विजयन ने कहा है कि वह सीएए और एनआरसी लागू नहीं करेंगे। इन मुख्यमंत्रियों के ऐसे दावे पूरी तरह भ्रामक ही हैं, क्योंकि नागरिकता का मसला राज्यों के क्षेत्राधिकार में आता ही नहीं है।

घुसपैठ की समस्या पर 1992 में केंद्र सरकार ने संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी। बैठक में बंगाल से मुख्यमंत्री ज्योति बसु और बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद शामिल हुए थे। तब तय हुआ था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई की जाएगी। उन दिनों बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या करीब 50 लाख थी, जिसके अब करीब एक करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। तृणमूल कांग्रेस ने अभूतपूर्व ढंग से अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच अतिवादियों का जमकर तुष्टीकरण किया है। बंगाल में सत्ता में आने के बाद ममता ने राज्य के 35 हजार इमामों के लिए हर माह 2500 रुपये मानदेय का प्रविधान किया। उनकी सरकार ने उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया। इसके अलावा भूमिहीन-गृहविहीन इमामों के लिए जमीन देने की घोषणा की और 10 हजार मदरसों को सरकार से संबद्ध किया। तृणमूल कांग्रेस ने प्रतिबंधित संगठन सिमी के नेता रहे एक व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य भी बनवाया। वहीं दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के समय ममता सरकार ने विवादास्पद रुख अपना लिया।

2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तो ममता बनर्जी ने वे सभी काम किए और बयान दिए जो मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ जाते हों, ताकि बंगाल के अल्पसंख्यक मतदाताओं की तृणमूल कांग्रेस के साथ एकजुटता मजबूत हो। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने हालिया चुनाव नतीजों के बाद कहा कि हमारे समर्थक मुसलमानों ने तृणमूल कांग्रेस को वोट दे दिए। माकपा ने भी अपने मतदाताओं को तृणमूल के पाले में भेज दिया। एक मजबूत वोट बैंक की ताकत से लैस ममता केंद्र सरकार से दो-दो हाथ करने पर अमादा हैं। शेष भारत के लोग बंगाल में केंद्र सरकार को इस तरह असहाय देखकर इंदिरा गांधी को याद करने लगते हैं, लेकिन इंदिरा सरकार और मोदी सरकार के बीच एक बड़ा फर्क यह है कि मोदी के पास राज्यसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

मंत्रिपरिषद विस्तार का राजनीतिक संदेश



हर्ष वर्धन त्रिपाठी

कभी ब्राह्मण-बनियों की पार्टी मानी गई भाजपा ने समय के साथ समावेशन की एक शानदार यात्रा तय की है

गुजरात में 1998 तक सहकारी संस्थानों, बैंकों में कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। सिर्फ एक सहकारी बैंक पर भाजपा काबिज थी। अमित शाह ने सहकारी संस्थानों से कांग्रेस को बेदखल करने की योजना तैयार की। धीरे-धीरे कांग्रेस गुजरात के सहकारी संस्थानों से पूरी तरह गायब हो गई। अब जब नरेंद्र मोदी ने नया सहकारिता मंत्रालय बनाया तो उसके मंत्री के तौर पर अमित शाह को नियुक्त किया। दरअसल यह दृष्टांत ही तय कर देता है कि मोदी के इस सबसे बड़े बदलाव के मूल में क्या है? पारंपरिक तरीके से राजनीति को देखने पर शायद ही समझ में आए कि गृह मंत्रालय के साथ सहकारिता मंत्रालय एक ही व्यक्ति को भला कैसे दिया जा सकता है, लेकिन इसी सोच के तहत मनसुख मांडविया नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय का जिम्मा वह किस प्रकार ठीक से संभाल पाएंगे, इसे समझने के लिए उस प्रसंग को याद करें जब नितिन गडकरी को स्पष्ट करना पड़ा था कि, वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने को लेकर मैंने कुछ सुझाव दिए थे, पर मुझे जानकारी नहीं थी कि मांडविया पहले ही बता चुके थे कि यह सब हो चुका है।

स्वास्थ्य और सहकारिता मंत्रालय की ही तरह दूसरे मंत्रालयों का जिम्मा जिन मंत्रियों को दिया गया है, उसके पीछे बहुत सोची समझी रणनीति है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल से हटाए गए मंत्रियों रविशंकर प्रसाद, रमेश पोखरियाल निशंक, प्रकाश जावडेकर और डॉ. हर्षवर्धन को हटाने के पीछे यह एक सूत्र है कि वे मोदी सरकार के राष्ट्रीय विमर्श को स्थापित करने में कामयाब नहीं रहे। मोदी सरकार के बारे में एक बात पक्के तौर पर कही जाती है कि वह फीडबैक पर काम करने वाली सरकार है और विशेषकर जनता क्या सोचती है, यह उसके लिए बहुत महत्व रखता है। किसी भी सरकार के वैचारिक विमर्श को स्थापित करने में सूचना प्रसारण मंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन जावडेकर उस भूमिका से न्याय नहीं कर पाए और अब अनुराग सिंह ठाकुर को यह जिम्मा सौंपा गया है। शिक्षा मंत्री के तौर पर निशंक का पूरा समय सिर्फ विवादों और टालमटोली में ही बीतता रहा। देश के आधे से अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपति नहीं हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करके राष्ट्रीय विमर्श को आगे बढ़ाने की दिशा में भी शिक्षा मंत्रालय कुछ खास नहीं कर सका। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सबसे पैनी दृष्टि भी इसी मंत्रालय के कामकाज पर रहती है, फिर भी शैक्षणिक संस्थानों में विरोधी विचार का कब्जा बना रहा। इसे संघ ने बहुत गंभीरता से लिया। इन हालात को बदलने की जिम्मेदारी अब धर्मेंद्र प्रधान को सौंपी गई है। प्रधान लंबे समय तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं। वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय में प्रधान की विरासत को अब हरदीप सिंह पुरी आगे बढ़ाएंगे। पुरी के पास आवास और शहरी विकास का प्रभार पहले से ही है। पंजाब चुनाव से पहले सिख चेहरे के तौर पर और सेंट्रल विस्टा परियोजना पर कांग्रेस के दुष्प्रचार को ध्वस्त करने के लिहाज से विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी पुरी की खास उपयोगिता है।



मंत्रिपरिषद विस्तार में साधे गए कई समीकरण। फाइल

बुधवार को शामिल किए गए 43 नए मंत्रियों में असम, त्रिपुरा, अरुणाचल और मणिपुर से एक-एक प्रतिनिधि जोड़े गए हैं, जो पूर्वोत्तर के प्रति मोदी की दृष्टि को प्रमाणित करता है। चीन से सटे अरुणाचल प्रदेश के किरण रिजिजू को केंद्रीय कानून मंत्री की कुर्सी देना दिखाता है कि प्रधानमंत्री के लिए रिजिजू रणनीतिक तौर पर कितने महत्वपूर्ण हो गए हैं। पूर्व नौकरशाह अश्विनी वैष्णव को रेलवे, कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और आइटी मंत्रालय देने के पीछे बहुत स्पष्ट वजह है। वह वाजपेयी सरकार में उपसचिव रहे हैं। दो पूर्व नौकरशाह और 24 पेशेवर मोदी सरकार में बदलाव का हिस्सा बने हैं। 43 नए मंत्रियों में 61 प्रतिशत मंत्री अन्य पिछड़े, अनुसूचित जाति और जनजाति से हैं। 27 ओबीसी, 12 एससी और आठ एसटी मंत्रियों को मोदी ने शामिल किया तो कई चैनलों ने 'अबकी बार-ओबीसी सरकार' तक लिख दिया। एक समय मुख्य रूप से ब्राह्मण-बनियों की पार्टी मानी जाने वाली भाजपा ने समय के साथ कितनी शानदार यात्रा की है, इससे आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है।

महाराष्ट्र में पूर्व शिवसैनिक और आक्रामक नेता नारायण राणे को एमएसएमई मंत्री बनाकर मोदी ने शिवसेना को स्पष्ट संदेश दे दिया है। दिल्ली से डॉ. हर्षवर्धन गए तो मीनाक्षी लेखी आईं और इसी तरह उत्तराखंड से ब्राह्मण रमेश पोखरियाल निशंक गए तो अजय भट्ट आए, लेकिन सबसे शानदार तरीके से जाति और क्षेत्र का संतुलन बैठाने में मोदी को उत्तर प्रदेश में कामयाबी मिली है। सपा-बसपा से आए आगरा के सांसद एसपीएस बघेल हों या फिर मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर। किशोर ने योगी सरकार के कोरोना प्रबंधन पर सवाल भी उठाए थे, लेकिन उन्हें मंत्री बनाया गया। बघेल और पासवान समाज के बड़े नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करके मोदी ने दो संदेश दिए हैं। पहला-सामाजिक समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया, दूसरा-किसी भी पार्टी के ताकतवर नेता के लिए भाजपा में सम्मानपूर्वक रहने का पूरा अवसर है। मोदी ने लखीमपुर खीरी से दो बार के भाजपा सांसद अजय कुमार मिश्र को मंत्री बनाकर इसका जवाब दे दिया कि क्या भाजपा के पास ब्राह्मण नेता नहीं हैं? अनुप्रिया पटेल को सहयोगी और पटेलों में संदेश देने के लिए मंत्री बनाया तो लगे हाथ महाराजगंज से लगातार सांसद बनने वाले कुर्मी नेता पंकज चौधरी को मंत्री बनाकर यह भी स्पष्ट किया कि भाजपा में किसी भी जाति के नेताओं की कमी नहीं है। सही मायने में पूरे देश में राजनीतिक संतुलन के साथ सुशासन के पैमाने पर नरेंद्र मोदी की दूसरी पारी अब शुरू हुई है।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ पत्रकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

आत्मबल और धैर्य

हम कई बार जीती हुई बाजी हार जाते हैं तो केवल आत्मबल व धैर्य की कमी के कारण। आत्मबल हमें ऊर्जा देता है। यह हर परिस्थिति में हमें भीतर से मजबूत करता है। हमें निराशा से बचाता है, लेकिन यदि आत्मबल क्षीण होने लगे तो हम हारने लगते हैं। हमें निराशा घेरने लगती है। हम मानसिक रूप से कमजोर पड़ने लगते हैं। यही परिस्थितियां हमारी हार का कारण बनने लगती हैं। आत्मबल के कमजोर हो जाने पर हम असहाय होने लगते हैं। हमारे जीतने की इच्छा कुंद होने लगती है। जब ऐसा हो जाता है तो घात लगाए बैठी पराजय हमले के लिए तैयार हो जाती है। हम अपने आत्मबल के जागरण से प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल बना सकते हैं। विजय का संकल्प आत्मबल के मजबूत होने से ही दृढ़ होता है। आत्मबल सकारात्मक विचारों से पोषण पाता है। पूर्ण समर्पण से किया गया कार्य हमारे आत्मबल को कई गुना बढ़ा देता है। फिर इसी के सहारे हम सफलता प्राप्त करते हैं।

धैर्य भी हमें सफलता की ओर उन्मुख करता है, जबकि अधीरता अक्सर पराजय का कारण बनती है। धैर्य के साथ किया गया कार्य अपने उत्कर्ष को प्राप्त होता है। धैर्य का गुण मानव के स्वभाव का महत्वपूर्ण आभूषण है। इस आभूषण के जरिये हम अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बना सकते हैं। धैर्यवान व्यक्ति सम्मान व सफलता दोनों को प्राप्त करता है। हमें धैर्यवान बनने का अभ्यास करना चाहिए। जीवन में धैर्य अभ्यास करने से ही आता है। हम स्वयं को नियंत्रित करने का प्रयास करते रहें तो धैर्य का गुण स्वयं प्रस्फुटित होने लगेगा। इंद्रिय संयम से ही धैर्य का जन्म होता है। धैर्य तप है। इसे अंगीकार करने के लिए हमारे भीतर तपस्वी जैसा भाव होना चाहिए। आत्मबल व धैर्य, उक्त दोनों गुण दैवीय गुण हैं। ये मानव जीवन को परिमार्जित करते हैं। हमें अपने भीतर इन दोनों ही गुणों के प्रसार के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। यही गुण हमारे जीवन में सफलता का निमित्त बनते हैं।

ललित शौर्य

हर मोर्चे पर बदलाव लाने वाली भागीदारी

डॉ. मोनिका शर्मा

समावेशी और संतुलित सोच के साथ किए गए मोदी सरकार के विस्तार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ा है। अब मंत्रिपरिषद में महिला मंत्रियों की कुल संख्या 11 हो गई है। नवनियुक्त चेहरों में दर्शना जरदोश, प्रतिमा भौमिक, शोभा करंदलजे, भारती पवार, मीनाक्षी लेखी, अनुप्रिया पटेल और अन्नपूर्णा देवी शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ ही राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और रेणुका सिंह सरुता पहले से ही सरकार का हिस्सा हैं।

सरकार में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को तरजीह देना कई मायनों में अहम है। देश के अलग-अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली सातों महिला केंद्रीय मंत्री कहीं न कहीं राजनीतिक पटल पर आधी आबादी की बढ़ती हिस्सेदारी को रेखांकित करती हैं। गौरतलब है कि अपनी सरकार में महिलाओं को जिम्मेदारी दिए जाने के मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू से ही नई लकीर खींची है। भाजपा सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान भी मंत्रिपरिषद में नौ महिला मंत्री शामिल थीं। उसमें एक समय छह महिलाएं तो कैबिनेट मंत्री थीं। उम्मीद है कि आपदा के दौर में कैबिनेट विस्तार में महिला सांसदों पर जताया गया यह भरोसा आगे के लिए भी पुख्ता बदलाव की बुनियाद बनेगा।

सत्ता के गलियारों में निर्णायक भूमिका में आने वाली महिलाएं अब स्वयं से जुड़े जरूरी मुद्दे अधिक मुखरता से उठा सकेंगी

परंपरागत पितृसत्तात्मक समाज, घरेलू जिम्मेदारियां, दोयम दर्जे की सामाजिक सोच, लैंगिक भेदभाव और राजनीति में पुरुषों के वर्चस्व जैसे कई कारणों के चलते भारत में आज भी महिलाओं की सियासी भागीदारी कम ही है। उम्मीद है कि सत्ता के गलियारों में पहुंचकर निर्णायक भूमिका में आने वाली महिलाएं स्त्री शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता जैसे मुद्दों पर मुखर होकर अपनी बात रखेंगी। आधी आबादी की समस्याओं को न केवल समझेंगी, बल्कि नीतियों और योजनाओं में उनका हल तलाशने के मार्ग भी सुझाएंगी।

इस उम्मीद को बल देने वाली एक वजह यह भी है कि महिलाओं का राजनीति में बढ़ता प्रतिनिधित्व आम महिलाओं को भी मुखर और आत्मविश्वासी बनाता है। यही कारण है कि सियासत में महिलाओं की भागीदारी समाज की स्त्रियों की सामाजिक-पारिवारिक परिस्थितियों की बानगी भी कही जाती है। सुखद है कि समय के साथ महिलाओं के हालात और सियासी दुनिया में हिस्सेदारी, दोनों में बदलाव आया है। इसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि राजनीति में आम स्त्रियों की जमीन पुख्ता करने के लिए हर स्तर पर उनकी सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए सामाजिक-पारिवारिक और आर्थिक मोर्चे पर भी उनका निर्णयकारी भूमिका में आना आवश्यक है। साथ ही समाज की सोच और अपनों की संवेदनाओं के धरातल पर भी सकारात्मक बदलाव जरूरी है। तभी अपेक्षित परिवर्तन साकार हो सकेगा।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

प्रदर्शन को मिली प्राथमिकता

आखिरकार एक लंबी प्रतीक्षा के बाद मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बहुप्रतीक्षित विस्तार ने गत बुधवार को आकार ले ही लिया। इसे मात्र विस्तार कहना उचित नहीं होगा, अपितु यह सरकार के नए तेवरों का उद्घोष अधिक है। नए मंत्रियों के पद और गोपनीयता की शपथ से पहले ही पुराने मंत्रियों को जिस रफ्तार से बाहर का रास्ता दिखाया गया, वह भी कम चौंकाने वाला नहीं रहा। यह न केवल राजनीतिक रूप से, बल्कि प्रशासनिक रूप से भी कठिन चुनौती थी। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी निर्णायक फैसलों में माहिर माने जाते हैं तो उन्होंने बुधवार को एक बार फिर उसमें अपनी महारत का प्रदर्शन किया। जिस प्रकार पुराने और पार्टी के दिग्गज नेताओं को मंत्रीपद से रुखसत किया गया है, उसे देखकर यही लगता है कि प्रधानमंत्री की अपने मंत्रियों के कामकाज पर कड़ी नजर थी और वह किसी को भी इस मामले में रियायत देने के लिए राजी नहीं थे। वहीं सरकार में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को प्रोन्नत करके यह संदेश भी दिया कि उनकी दृष्टि में काम को ही सलाम है। इस प्रकार उन्होंने एक बड़ी लकीर खींच दी है कि प्रदर्शन करिए तो प्रोन्नति पाइए, अन्यथा बाहर जाइए। अब जिन नए चेहरों पर प्रधानमंत्री ने दांव लगाया है, उन पर बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव बढ़ गया है। यह दबाव अगर बेहतर गवर्नेंस सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होता है तो बेहतर ही है।

श्रुति त्रिपाठी, गाजियाबाद

हठधर्मिता नहीं, संशोधन ही विकल्प

सात महीनों से सड़कों पर काबिज और संवैधानिक तौर पर पारित तीनों कृषि सुधार कानूनों की वापसी पर अड़े तथाकथित किसान आंदोलन के संचालक संयुक्त किसान मोर्चा केवल अपनी राजनीति चमकाने के साथ राजनीतिक दलों से ज्यादा प्रेरित लगते हैं। छोटे मझोले किसानों की असली समस्याओं से कोसों दूर, किसान नेता हरियाणा के मुख्यमंत्री को सरेआम पाकिस्तानी कहने में शर्म महसूस नहीं करते। हालांकि, इस पाकिस्तानी शब्द का खामियाजा भविष्य में तथाकथित आंदोलनजीवियों व आंदोलन को समर्थन दे रहे विपक्षी राजनीतिक दलों को आगामी चुनावों में पंजाबी समुदाय के आक्रोश का सामना अवश्य करना पड़ेगा। कितना हास्यास्पद लगता है जब किसान नेता विधानसभा चुनावों में भी केंद्र सरकार को घेरने की बात करते हैं। किसान नेता और किसान मोर्चा के प्रवक्ता विभिन्न टीवी डिबेट्स व साक्षात्कार के दौरान हिंदू-मुस्लिम आधारित राजनीति करते नजर आते हैं और यहां तक कि चीन और पाकिस्तान जैसे देशों पर केंद्र सरकार की नीतियों को विफल बता अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक ज्ञान बांटने के साथ आमजन में भ्रमजाल की स्थिति उत्पन्न करने की नाकाम कोशिश भी करते हैं। आखिरकार किसान नेताओं का राजनीति से क्या लेना देना? निःसंदेह आंदोलन हठधर्मिता और कोरी राजनीति पर आधारित नहीं होते। निश्चित ही किसान आंदोलन की आड़ में यह एक बड़ा राजनीतिक एजेंडा लगता है। यूपीए शासन काल में कृषि मंत्री रहे, एनसीपी के अध्यक्ष और भारतीय राजनीति के वरिष्ठ दिग्गज शरद पवार द्वारा हाल ही में तीनों कृषि सुधार कानूनों की वापसी के बजाय कानूनों में ही संशोधन की पैरवी करना, एक सराहनीय वक्तव्य है।

दीपक गौतम, सोनीपत

सांसों में घुलते जहर को रोकना बड़ी चुनौती

आज के समय में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला हर युवा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर की तरफ भागता है, ताकि अच्छी नौकरी हासिल कर सके। उसका भागना भी बिल्कुल सही होता है। शहर में वे तमाम सुविधाएं मौजूद होती हैं, जो गांवों में नहीं मिल पाती है। हालांकि, शहर आने के साथ ही यहां पर वह जहरीली हवा का शिकार हो जाता है। जहरीली हवा के खतरनाक परिणाम तुरंत सामने नहीं आते हैं। यह धीरे धीरे हमारी उम्र के साथ दिखने लगते हैं। हमको सांस लेने में परेशानी होने लगती है। वे तमाम बीमारियां हो जाती हैं, जिनसे हम गांव में कोसो दूर रहते है। अब सवाल यह है कि बड़े शहरों की हवा में घुलते हुए जहर को रोका नहीं जा सकता है क्या? इसका जवाब तलाशना होगा।

नेहा रानी, फरीदाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

[illegible]

दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 [illegible]

49 युवा वनाधिकारी पासआउट हो गए हैं केंद्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, देहरादून से दो साल का प्रशिक्षण पाकर। ये अधिकारी सहायक वन संरक्षक के रूप में अपने-अपने प्रदेश में सेवा देंगे।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 9 जुलाई, 2021

बंगाल

बजट और रोजगार के वादे

तीसरी बार बंगाल की सत्ता पर काबिज होने के बाद पहला आम बजट ममता सरकार ने बुधवार को विधानसभा में पेश किया। इस बजट में ममता सरकार ने डेढ़ करोड़ लोगों को रोजगार देने की घोषणा की है, परंतु यहां एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह रोजगार कैसा होगा? सूबे में जब तक निवेश नहीं आएगा और बड़े उद्योग नहीं आएंगे तो इतनी बड़ी संख्या में रोजगारों का सृजन कैसे होगा? हालांकि इस बात का उल्लेख बजट में नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि इसके लिए राज्य सरकार की ओर से खाका जरूर तैयार किया गया होगा। वैसे तो हर वर्ष बजट में बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन वे कितना पूरा होते हैं यह सबको पता है। परंतु जिस तरह से बड़ी जीत के साथ ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी हैं तो उसी प्रकार उनका दायित्व भी बढ़ गया है।

ऐसे में उनका कर्तव्य है कि लोगों की उम्मीद और आकांक्षाओं को पूरा करें। पर राज्य की आर्थिक हालत खराब है। ऋण लेकर कर्मचारियों को वेतन और पेंशन दिए जाते हैं। राज्य पर ऋण का बोझ चार लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। ऐसे में डेढ़ करोड़ रोजगार समेत अन्य जो वादे किए गए हैं उसे किस तरह से पूरा किया जाएगा? यही नहीं लोगों को फौरी राहत देने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स में छूट, दिसंबर तक वाहनों का रोड टैक्स माफ समेत कई और योजनाओं को लागू करने की घोषणा की गई है। कोरोना महामारी से निबटने को 1,830 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा के बीमार होने की वजह से उद्योग एवं संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। यह बजट सात करोड़ रुपये घाटे का है, लेकिन विपक्षी दल सवाल यह उठा रहे हैं कि बजट आवंटन बढ़ा गया और कोरोना महामारी के चलते राजस्व उगाही का जो लक्ष्य रखा गया था वह भी पूरा नहीं हुआ तो फिर घाटा महज सात करोड़ रुपये ही कैसे।

> बंगाल की आर्थिक हालत बेहद खराब है। वहां ऋण लेकर सरकारी कर्मचारियों को वेतन और पेंशन दिए जाते हैं। राज्य पर ऋण का यह बोझ चार लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है

खैर यह तो आंकड़ों का खेल है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि राजस्व उगाही नहीं बढ़े तो विकास कार्यों का क्या होगा? अगले पांच साल में डेढ़ करोड़ नौकरियों देने का वादा किया गया है उसका क्या होगा? पेट्रोलियम उत्पादों के टैक्स छूट की भी बात कही गई है तो फिर राजस्व उगाही भी कम होगी। ऐसे में सरकार को वैकल्पिक रास्ता तलाशना होगा। नहीं तो रोजगार और अन्य वादे पूरे नहीं हो सकेंगे। इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों को अधिक से अधिक रोजगार देना, ताकि मांग बढ़ सके।

झारखंड

पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे

> स्मार्ट फोन के अभाव में बच्चों की बाधित पढ़ाई को जल्द से जल्द शुरू कराने की जरूरत है

झारखंड के ग्रामीण इलाकों में सरकारी शिक्षा की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। स्कूल हैं तो शिक्षक नहीं। कोरोना संक्रमण ने रही-सही कसर भी पूरी कर दी है। गांवों में आनलाइन की कवायद परवान नहीं चढ़ पाई है, क्योंकि पहाड़ों से घिरे कई गांवों में मोबाइल नेटवर्क ही नहीं पहुंचता है। पढ़ाई एक तरह से ठप ही समझिए।

पिछले दिनों पूर्वी सिंहभूम में दो ऐसी छात्राएं सुर्खियों में रहीं, जो आनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल खरीदना चाहती थीं। इसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे। एक छात्रा मोबाइल के पैसे जुटाने के लिए आम बेच रही थी तो दूसरी बबुई घास से बनीं रस्सियां। ये दोनों छात्राएं भाग्यशाली रहीं कि इनकी कहानी इंटरनेट मीडिया में वायरल होने के बाद मुंबई की एक कंपनी के मालिक ने मदद वास्ते साढ़े 12 लाख रुपये में 12 आम खरीद लिए। वहीं राजस्थान से भी एक युवक ने रस्सी बेचने वाली छात्रा को 10 हजार रुपये का मोबाइल भेज दिया। सुदूर गांवों के सभी आदिवासी विद्यार्थी इतने भाग्यशाली नहीं। उनके लिए स्मार्ट फोन सपने की तरह है। इस कारण आनलाइन पढ़ाई की सुविधा का लाभ भी इन्हें नहीं मिल पा रहा है।


गरीब छात्रों को नहीं मिल पा रही आनलाइन शिक्षा। फाइल

सरकारी और गैरसरकारी स्तर पर कुछ प्रयास हो रहे हैं, लेकिन इसका पूरा-पूरा लाभ तेजी से जरूरतमंदों को मिल सके, इसकी कोशिश होनी चाहिए। झारखंड में 92 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जो कवायद शुरू हुई है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। केंद्र सरकार में जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा बीते दिनों ही पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी एवं सरायकेला खरसावां जिलों में इन विद्यालयों का शिलान्यास कर चुके हैं। अन्य जिलों में भी कवायद जारी है।

केंद्र सरकार प्रायोजित यह विद्यालय आदिवासी बच्चों की जिंदगी में नई क्रांति ला सकता है। इन विद्यालयों में शिक्षा के साथ-साथ खेल व अन्य गतिविधियों का उन्हें निःशुल्क लाभ मिलेगा। अपने परिवेश में रहकर आदिवासी छात्र शिक्षा ग्रहण करेंगे। इस कवायद में अच्छी बात यह रही कि राज्य सरकार ने भी जिलों में भूमि मुहैया कराने में कोई देरी नहीं की। केंद्र और राज्य दोनों की मंशा है कि जल्दी से आदिवासी बच्चों के विद्यालय बनकर तैयार हो जाएं। बहरहाल, अब जरूरत इस बात की है कि स्थानीय प्रशासन समय पर इनका जल्द निर्माण सुनिश्चित कराए।

हरियाणा

सार्वभौमिक सत्य

हरियाणा के किसी सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुए विस्तार में स्थान नहीं मिला, बल्कि अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं रहे। कहां तो अपेक्षा था कि हरियाणा का कोई एक और सांसद मंत्री बन जाएगा तो मंत्रिमंडल में हरियाणा के चार सदस्य हो जाएंगे, लेकिन अपेक्षा पर तुषारापात हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह अपने पुत्र बृजेंद्र सिंह को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान दिलाना चाहते थे। उनकी भी इच्छा धरी रह गई। बृजेंद्र सिंह हिसार से सांसद हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं। वह शासकीय सेवा से त्यागपत्र देकर राजनीति में आए हैं। वैसे यह चर्चा भी थी कि रतनलाल कटारिया का त्यागपत्र लेकर उनके स्थान पर सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा सकता है।

इस तरह हरियाणा की भागीदारी यथावत रहेगी, जब रतनलाल कटारिया ने मंत्री पद से त्यागपत्र दिया तो लोग यह मान बैठे कि दुग्गल का मंत्री बनना तय है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। कटारिया मंत्रिमंडल से


मोदी मंत्रिमंडल में आप तभी तक बने रह सकते हैं, जब तक आपका प्रदर्शन अच्छा होगा। फाइल

> इसमें कोई दो राय नहीं कि जो व्यक्ति सतत उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, वही टीम का हिस्सा बना रह सकता है

क्यों हटे या हटाए गए, यह उनका और उनके दल का आंतरिक मामला है। संभव है कि कटारिया का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप न रहा हो अथवा यह भी हो सकता है कि भाजपा नेतृत्व उनका कहीं और उपयोग करना चाहता हो। वैसे यह तो तय है कि किसी भी टीम में आप तभी तक बने रह सकते हैं, जब तक आपका प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप रहेगा।

आपके कमजोर प्रदर्शन से टीम की भी किरकिरी होती है और जनता भी निराश होती है। यह केवल राजनीतिक क्षेत्र की ही बात नहीं है, हर क्षेत्र में यह नियम लागू होता है। रही बात केंद्रीय मंत्रिमंडल में हरियाणा के प्रतिनिधित्व की तो यहां से दस सांसद चुने जाते हैं, उनमें दो मंत्री हैं। इस तरह देखा जाए तो यहां के बीस प्रतिशत सांसद केंद्र में मंत्री हैं और हरियाणा का प्रतिनिधित्व अन्य प्रदेश की अपेक्षा अब भी अधिक ही है। इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सांसदों को भी चाहिए कि बतौर सांसद वे उत्कृष्ट काम करें और उनके काम को देखते हुए उनके दल का नेतृत्व उन्हें मंत्रिमंडल में समायोजित कर ले।

उत्तराखंड

अपेक्षाओं पर खरा उतरने की चुनौती

उत्तराखंड की भाजपा सरकार में नेतृत्व परिवर्तन के बाद अब युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की टीम वजूद में आ गई है। मंत्रियों के विभाग बंटने के साथ ही उन्हें जिलों का प्रभार भी दे दिया गया है। नौकरशाही में फेरबदल की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और उसे सरकार के एजेंडे से अवगत करा दिया गया है। दरअसल सरकार के पास सीमित समय है। धामी सरकार को कामकाज के लिए बामुश्किल आठ माह का वक्त मिलेगा और इसमें भी दो माह चुनाव में गुजरेंगे। अब जबकि सरकार में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है तो उसके पीछे अवधारणा यही है कि अगले छह माह में विकास की गति बढ़ाई जाए। हालांकि पिछली सरकारों के कार्यकाल में भी काफी काम हुए, लेकिन यह चुनावी वर्ष है। इसलिए सरकार की आकांक्षाएं भी अधिक हैं। इसे देखते हुए वह जनता के और नजदीक जाने का प्रयास करेगी। नेतृत्व परिवर्तन को भी इससे जोड़कर देखा गया। यद्यपि सरकार के सामने तमाम चुनौतियां हैं, लेकिन इनके बीच से उसे राज्य की प्रगति का रास्ता तलाशना है। सरकार ने शुरुआती दिनों में ही संकेत दे दिए हैं कि गांव-गांव तक यह अहसास दिलाया जाएगा कि सरकार उनकी अपनी है और विकास का पैगाम जनता तक पहुंचाएगी। मुख्य सचिव भी कह चुके हैं कि योजनाओं को धरातल पर उतारना प्राथमिकता है। इसे भी सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि सरकार के सामने दोहरी चुनौतियां हैं। उसे छह माह में ऐसा माहौल तैयार करना है, जिसके बूते 2022 में दोबारा में वापसी का ताना-बाना बुना जा सके। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने भी इसी सोच के तहत चुनावी साल में नेतृत्व परिवर्तन का जोखिम लिया। केंद्रीय नेतृत्व की उम्मीदों पर खरा उतरना भी नई सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरी चुनौती खुद को साबित करने की है। नए मुख्यमंत्री के पास सरकार चलाने का अनुभव न हो, मगर उनकी टीम में दिग्गज नेता हैं। उन्हें साधने और उनके अनुभव का लाभ लेते हुए आगे बढ़ने की चुनौती नई सरकार के सामने है। मुख्यमंत्री इसे बखूबी समझ रहे हैं और विभागों के बंटवारे में इसकी झलक दिखी है। इसके अलावा राज्य की खराब माली हालत को सुधारने की बड़ी चुनौती सरकार के समक्ष है। कुल मिलाकर मौजूदा सरकार के पास काम अधिक और समय कम है। इस सबके बीच उसे चुनौतियों से पार पाना है। उम्मीद है कि धामी कैबिनेट में शामिल अनुभवी मंत्री इन चुनौतियों को दूर करने के लिए आगे आएंगे। उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है तो उनका दायित्व भी है कि वे राज्य की जनता और पार्टी की अपेक्षाओं पर खरा उतरें।

> धामी सरकार के पास काम अधिक है और समय कम। इस सबके बीच से ही उसे चुनौतियों से पार पाने का रास्ता तलाशना है। उम्मीद है नए मुख्यमंत्री इस पर खरा उतरेंगे

चीन के 'जाल' से निकल बुनकर फिर लौटे देसी धागों की ओर

आनंद कुमार सिंह, भागलपुर

चीन की कर्ज देकर किसी देश को फंसाने की नीति अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बन गई है। भागलपुर के बुनकरों को शुरू में सस्ता सिल्क देकर उन्हें भी फंसाने का छल चीन ने किया। कम कीमत पर तसर के धागों की आपूर्ति शुरू करने के बाद जब बुनकर उन धागों पर निर्भर हो गए तो चीन ने इनके दाम तो बढ़ाए ही, गुणवत्ता भी खराब कर दी। बुनकरों को चीन का यह छल समझ में आ गया। गलवन घाटी में भारत-चीन के बीच तनाव के बाद तो बुनकरों ने चीनी धागों के बहिष्कार की मुहिम ही चला दी। अब भी बुनकर देसी धागों से ही माल तैयार कर रहे हैं।

बिहार बुनकर कल्याण समिति के सदस्य अलीम अंसारी ने बताया कि भागलपुरी सिल्क की मांग हमेशा से रही है। 1989 के आसपास दंगों के कारण काम प्रभावित हुआ। इसके बाद 1991 से इस करोबार को फिर पंख लगे। 1997 तक भागलपुरी सिल्क का स्वर्णिम काल रहा। इस समय एक्सपोर्टरों ने खुला आर्डर दे रखा था कि जितना भी माल बना लें, सब खरीद लेंगे। 24 घंटे काम करने के बाद भी बुनकर उस स्थिति में नहीं थे कि वे आर्डर पूरा कर दें। ऐसी स्थिति में दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई के कई एक्पोर्टरों ने भागलपुर में अपना कार्यालय खोलकर माल बनवाना शुरू किया। यही वह दौर था, जब इस शानदार बाजार को देखकर चीन ने 1998 में अपने सस्ते तसर के धागे भेजने शुरू किए। उस समय 33 से 37 डीनियर (रैखिक घनत्व का मापक या धागे की गुणवत्ता का मापक) के चीनी धागों की कीमत 250 रुपये प्रति किलो थी, जबकि देसी तसर के धागे 700 रुपये


भागलपुर में तसर के कोकून को दिखाते विज्ञानी। जागरण

> बुनकरों ने देसी धागों को तरजीह देनी शुरू कर दी है। देसी तसर से तैयार कपड़ों को लोगों ने हाथों-हाथ लिया। विदेश में भी मांग बढ़ी है। लाकडाउन और कोरोना काल की परेशानियों के बाद देश-विदेश के बाजार में देसी सिल्क चीनी सिल्क पर भारी पड़ने लगा है।
>
> -जियाउर रहमान, सिल्क कपड़ों के एक्सपोर्टर, भागलपुर

प्रति किलो मिलते थे। कम कीमत होने के साथ ही तब कारीगरों को लालच भी दिया गया कि चीनी धागों में कड़ापन लाने के लिए तासन (स्टार्च) नहीं देना पड़ेगा। देसी धागे मुलायम होते हैं, जिस कारण इनमें तासन देना होता है। सस्ता होने की वजह जब बहुतायत बुनकर चीनी धागों का प्रयोग करने लगे तो चीन ने धागों की कीमत बढ़ाने के साथ गुणवत्ता गिराकर 22 से 24 डीनियर के बीच कर दी। बुनकर इलियास अंसारी व पृथ्वीराज नवल ने बताया कि सस्ता माल लेने के लिए उस दौरान कुछ एक्सपोर्टरों ने भी गलती की। परिणामस्वरूप आर्डर कम होने के बाद बुनकरों को गलती का एहसास हुआ। धीरे-धीरे बुनकर देसी धागों की ओर लौटने लगे। सिल्क के कपड़े बनाने में टीजीएन मिक्सचर (तसर-घिच्चा-न्वाइल, तीनों सिल्क की अलग-अलग क्वालिटी) का प्रयोग होता है।

दक्षिण भारतीय शहरों में अब ठिकाना बना रहे बांग्लादेशी घुसपैठिए

चिंताजनक

राजीव कुमार झा, कोलकाता

- त्रिपुर, एर्नाकुलम व अन्य शहरों में पहचान छिपाकर बड़ी संख्या में मजदूरी व अन्य पेशे से जुड़े हैं बांग्लादेशी
- जाली भारतीय कागजात भी आसानी से बनवा लिए हैं


परेशानी : घुसपैठ करते रोहिंग्या। फाइल फोटो

- अवैधरूप से सीमा पार करते पकड़े गए आरोपितों के हवाले से बीएसएफ ने किया दावा

यहां ठिकाना बनाने की यह है वजह

बीएसएफ सूत्रों की मानें तो हाल के दिनों में पकड़े गए बांग्लादेशियों से पूछताछ में पता चला है कि दक्षिण भारत के शहर उन्हें ज्यादा महफूज लग रहे हैं। इन शहरों में देश के दूसरे राज्यों की तुलना में मजदूरी भी अधिक मिलती है। साथ ही आसानी से आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज भी बन जाते हैं। इससे उन्हें वहां रहने में ज्यादा परेशानी नहीं होती।

अवैध तरीके से सीमा पार करके देश में आने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों में से अधिकतर अब दक्षिण भारत के शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के विभिन्न शहरों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी पहचान छिपाकर अपना ठिकाना बनाने के साथ मजदूरी व विभिन्न प्रकार के पेशे से जुड़े हैं। अवैधरूप से सीमा पार करते पकड़े गए आरोपितों के हवाले से सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने यह दावा किया है। बीएसएफ के अधिकारी घुसपैठियों का इस तरह देश के अलग-अलग राज्यों में घुस आना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बता रहे हैं।

बीएसएफ ने एक हफ्ते के अंदर बंगाल के सीमावर्ती नदिया व उत्तर 24 परगना जिले से दो अलग-अलग घटनाओं में अवैधरूप से सीमा पार करते तीन बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये सभी दक्षिण भारत के शहरों में काम करते थे। इनसे पूछताछ में बेहद ही चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। बीएसएफ अधिकारियों के अनुसार, नदिया से पकड़े गए दोनों बांग्लादेशी युवकों ने बताया कि तमिलनाडु के त्रिप्पुर शहर में जिस कपड़े के मिल में वे काम करते हैं, उसमें करीब 200 बांग्लादेशी नागरिक और काम कर रहे हैं। यही नहीं अपनी पहचान बदलकर गैरकानूनी तरीके से वहां रह रहे बांग्लादेशियों ने जाली भारतीय पहचान-पत्र भी बनवा लिए हैं। वहां कपड़े की दो- तीन और बड़ी मिल हैं, जिसमें अधिकतर बांग्लादेशी ही कार्यरत हैं और यह मुस्लिम बहुल इलाका है। उत्तर 24 परगना से पकड़े गए एक अन्य बांग्लादेशी ने बताया कि केरल के एर्नाकुलम शहर में उसके जैसे कम से कम 60 बांग्लादेशी लेबर व राजमिस्त्री का काम करते हैं। एक साल पहले भारत आने वाले उक्त युवक ने भी दावा किया कि एर्नाकुलम में भी सभी बांग्लादेशियों ने भारतीय पहचान-पत्र बनवा लिए है।

हिंसा पीड़ितों को धमकी दे रही है बंगाल पुलिस

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

- एनएचआरसी ने कहा- भाजपा को वोट देने के कारण पुलिस कर रही है प्रताड़ित
- कलकत्ता हाई कोर्ट ने हिंसा पीड़ितों की शिकायत दर्ज करने का दिया था निर्देश

बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच कर रही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की टीम के एक सदस्य ने गुरुवार को गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की पुलिस पीड़ितों को मामले में शिकायत दर्ज नहीं कराने की धमकी दे रही है। इस दावे के बाद हिंसा की जांच ने एक नया मोड़ ले लिया है।

गौरतलब है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के पांच जजों की पीठ ने एनएचआरसी की टीम की रिपोर्ट के आधार पर बीते दो जुलाई को राज्य पुलिस को सभी हिंसा पीड़ितों की शिकायतों को दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद अब एनएचआरसी टीम ने राज्य पुलिस पर उक्त आरोप लगाया है। हाई कोर्ट के निर्देश पर मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर रही टीम के सदस्यों ने गुरुवार को मुर्शिदाबाद जिले के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर पीड़ितों की शिकायतें सुनीं। इसके बाद टीम के सदस्य व राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ रशीद ने मुर्शिदाबाद के पुलिस अधीक्षक (एसपी) के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने एसपी से शिकायत की कि जनता पुलिस से डरी हुई है। उनकी (पीड़ितों की) गलती यही है कि उन्होंने भाजपा को वोट दिया है। उन्होंने सवाल किया कि भाजपा को वोट देने के लिए पुलिस लोगों को क्यों प्रताड़ित कर रही है? रशीद ने दावा किया कि पुलिस पीड़ितों को शिकायत दर्ज न करने की धमकी दे रही है। एसपी से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रशीद ने उक्त बातें कहीं।

मालदा व मुर्शिदाबाद जिले के दौरे पर है टीम

हाई कोर्ट ने दो जुलाई को एनएचआरसी जांच की अवधि को 13 जुलाई तक बढ़ाने का निर्देश दिया था। इसके बाद एनएचआरसी की टीम मंगलवार से फिर से हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा शुरू किया। टीम के सदस्य मालदा और मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर पीड़ितों की शिकायत सुन रहे हैं। गौरतलब है कि भाजपा ने बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं पर हमले, उनकी घर व दुकानें लूटने, घर जलाने, तोड़फोड़ और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर लगाया था। इन्हीं शिकायतों की टीम हाई कोर्ट के निर्देश पर जांच कर रही है।

केदारनाथ धाम में स्थापित होगी आदि शंकराचार्य की प्रतिमा

जासं, रुद्रप्रयाग

आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची व 35 टन वजनी प्रतिमा गौचर (चमोली) पहुंच गई है। मैसूर में तैयार इस प्रतिमा को जल्द ही हेलीकाप्टर से केदारनाथ धाम भेजा जाएगा। वहां से शंकराचार्य समाधि स्थल के पास स्थापित किया जाएगा।

2013 में केदारनाथ आपदा में आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल क्षतिग्रस्त हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों के तहत शंकराचार्य के समाधि स्थल को भी तैयार किया जा रहा है। केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य से जुड़ी वुड स्टोन कंस्ट्रक्शन कंपनी के केदारनाथ प्रभारी मनोज सेमवाल ने बताया कि मैसूर से यह प्रतिमा तीन भागों में गोचर पहुंची है। जल्द ही हेलीकाप्टर से प्रतिमा को केदारनाथ लाया जाएगा। अक्टूबर तक शंकराचार्य की समाधि स्थल का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। प्रतिमा मंदिर के पीछे तैयार हो रहे समाधि स्थल के पास स्थापित की जाएगी।


शंकराचार्य की प्रतिमा को चमोली के गौचर तक पहुंचाया जा चुका है। साभार- मनोज सेमवाल, प्रभारी वुडस्टोन कंस्ट्रक्शन कंपनी

जागरण विशेष

इस जैविक खाद का दोहरा लाभ, बचे पानी और बढ़े पैदावार

छत्तीसगढ़ के युवा कृषि उद्यमी योगेश ने तैयार की खाद, इससे 20 फीसद बढ़ेगा उत्पादन और 50 फीसद होगी पानी की बचत

संदीप तिवारी • रायपुर

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के समीप के गांव धमधा के युवा कृषि उद्यमी योगेश कुमार सोनकर ने कृषि क्षेत्र में अनुकरणीय पहल की है। उन्होंने एक ऐसी जैविक खाद तैयार की है, जिससे धान, गेहूं, फल, सब्जी आदि की पैदावार 20 फीसद तक बढ़ेगी साथ ही 50 फीसद तक पानी की बचत भी होगी।

यह खाद पोटेशियम बेस्ड सेलूलोज (कोशिकारस) और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स (सूक्ष्म पोषक तत्व) के इस्तेमाल से तैयार की गई है। इसका नाम अर्थ एलिक्सिर यानी 'जमीन का अमृत' दिया गया है। इसे गोबर के रस (हुमिक एसिड) व समुद्री घास (सीवीड एक्स्ट्रेक्ट) और अन्य सूक्ष्म तत्वों को मिलाकर तैयार किया जाता है। इसमें अपने वजन से 200 से लेकर 300 गुना तक पानी को अवशोषित करने की क्षमता होती है। इसमें पौधों के पोषक तत्वों की प्राप्ति का भी फार्मूला है। 400 रुपये प्रति किलो के भाव से उपलब्ध इस खाद को किसी भी फसल में केवल एक बार प्रति हेक्टेयर तीन से चार किलो डाला जाता है। यह नवाचार केंद्र के कृषि मंत्रालय एवं इंदिरा गांधी कृषि विवि के एग्री बिजनेस इन्क्यूबेशन सेंटर की मदद से चल रहा है।

ऐसे की शुरुआत : योगेश ने बताया कि विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई थी कि पानी की कमी या बारिश नहीं होने से फसल बर्बाद होने के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं या खेती छोड़ रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए वर्ष 2016 से काम करना शुरू किया। जर्मनी और चीन जैसे देशों के रिसर्च पेपर पढ़े। तीन साल की मेहनत के बाद पोटेशियम बेस्ड सेलूलोज और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से खाद तैयार की। कई बार प्रयोग के बाद परिणाम यह मिला कि इस खाद से खेतों में पानी रोकने के साथ जमीन की उर्वरक क्षमता भी बढ़ जाती है।

ऐसे मिला बाजार: फार्मूला तैयार होने के बाद योगेश ने कुछ कंपनियों से स्वयं संपर्क किया। इंदिरा गांधी कृषि विवि ने केंद्र सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत उनके नाम का चयन किया। इससे केंद्र सरकार से योगेश को 12 लाख रुपये स्वीकृत हुए। साथ ही दो नेशनल स्टार्टअप प्रतियोगिता में प्रथम स्थान भी हासिल किया। एक कंपनी ने मदद की और उत्पाद को पांच अप्रैल, 2019 में अंतराष्ट्रीय स्तर पर थाईलैंड में लांच किया। अब योगेश अपने ही गांव की महिलाओं को रोजगार देते हुए खाद का उत्पादन कर रहे हैं। उनको कृषि विवि में अनुसंधान के लिए अलग से सर्वसुविधायुक्त व्यवस्था दी गई है।


<< खेत में खाद का छिड़काव करते किसान विदेशी राम कश्यप • नईदुनिया

> योगेश ने एक विशेष खाद का प्रोटोटाइप तैयार किया है। इसमें हाइड्रोजेल जैसा गुण है, जिससे मिट्टी में जल को अवशोषित करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसका इस्तेमाल बंजर भूमि में भी कर सकते हैं।
>
> डा. हुलास पाठक, कृषि विज्ञानी एवं सीईओ, एग्री बिजनेस इन्क्यूबेशन सेंटर, इंदिरा गांधी कृषि विवि रायपुर



अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान के बाद खोल ली कंपनी

योगेश के उत्पाद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने के बाद छह कंपनियों ने उत्पाद को खरीदने की इच्छा जताई। फल विज्ञान से एमएससी में गोल्ड मेडल हासिल कर चुके योगेश ने नेचर वाल बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड और नेचर वाल नेचुरल वाटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्थापित की है। 14 तरह की खाद बनाने वाली कंपनियों के मालिक योगेश ने बताया कि लगातार तीन महीने खाद डालकर बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने में भी सफलता मिली है। यह खाद पौधों में रोगप्रतिरोधक क्षमता का विकास भी करती है।


योगेश सोनकर

ननिहाल में पत्थर तराशकर बनाई जा रही भगवान श्रीराम की 51 फीट ऊंची मूर्ति

वाकेश कुमार साहू, रायपुर

राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में शामिल राम वनगमन परिपथ के तहत छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के चंदखुरी में भगवान श्रीराम के ननिहाल में उनकी 51 फीट ऊंची मूर्ति बनाई जा रही है। मूर्ति का काम 90 फीसद पूरा कर चुका है। इसी माह मूर्ति को चंदखुरी में स्थापित की जाएगी।

चंदखुरी भगवान श्रीराम की माता कौशल्या का मायका है। देश में माता कौशल्या का यह एकमात्र मंदिर है। राज्य सरकार ने भगवान श्रीराम के 14 वर्ष की वनवास की कहानी को सहजने के लिए कोरिया से बस्तर तक श्री राम वनगमन परिपथ बनाने का काम शुरू किया है। जहां-जहां श्रीराम के चरण पड़े थे, पर्यटन की दृष्टि से उन्हें विकसित किया जा रहा है। प्रदेश भर में 11 से अधिक जगहों को चिह्नित किया गया है।

ओडिशा और मध्य प्रदेश के कारीगर: राम वनगमन परिपथ के नोडल अधिकारी अनुराधा दुबे के अनुसार भगवान श्रीराम की मूर्ति को बनाने के लिए ओडिशा और मध्य प्रदेश के 50 से अधिक कारीगर आए हैं, जो विशाल पत्थर को तराशकर मूर्ति तैयार कर रहे हैं। मूर्ति बनाने का 90 फीसद कार्य हाथों से किया जा रहा है। मूर्ति बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के बिल्हा स्टोन (पत्थर) का उपयोग किया जा रहा है। यह गुलाबी रंग का होता है।

एलआइसी का चेयरमैन पद आइपीओ से पहले खत्म

नई दिल्ली : देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) के प्रारंभिक पब्लिक ऑफर (आइपीओ) की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए सरकार ने इसके चेयरमैन का पद खत्म कर दिया है। इसकी जगह कंपनी में अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) व प्रबंध निदेशक (एमडी) का पद होगा। इसके साथ ही आर्थिक मामलों के विभाग ने सिक्युरिटीज कांट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) रूल्स में भी बदलाव किए हैं। (प्रेट्र)

हमारे प्रमुख बाजारों ने पहली तिमाही में अच्छा प्रदर्शन किया है। दूसरी तरफ देश में कारोबार खासा प्रभावित हुआ है।
– राजेश गोपीनाथन
एमडी, टीसीएस



सेंसेक्स	निफ्टी	सोना (प्रति दस ग्राम)	चांदी (प्रति किलोग्राम)	डॉलर	क्रूड (ब्रेंट) (प्रति बैरल)
52,568.94 ▼ 485.82	15,727.90 ▼ 151.75	₹46,981 ▲ ₹09	₹67,758 ▼ ₹902	₹74.71 ▲ ₹0.09	$ 72.75

एक नजर में

जेपी इन्फ्रा के लिए समाधान योजना एनसीएलटी में पेश

नई दिल्ली : जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड के अंतरिम समाधान पेशेवर (आइआरपी) अनुज जैन ने सुरक्षा ग्रुप की समाधान योजना को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के समक्ष पेश किया है। सुरक्षा ग्रुप की समाधान योजना को हाल ही में जेपी इन्फ्राटेक के वित्तीय कर्जदाताओं ने मंजूरी दी थी। नियामकों को दी जानकारी में कंपनी ने बताया कि आइआरपी ने सात जुलाई को सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड व लक्षदीप इंवेस्टमेंट्स एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (सुरक्षा) द्वारा पेश समाधान योजना एनसीएलटी के समक्ष पेश की, जिसे वित्तीय कर्जदाताओं की मंजूरी मिल चुकी है। (प्रेट्र)

स्पाइसजेट लांच करेगी 42 नए फ्लाइट

नई दिल्ली : निजी विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने गुरुवार को कहा कि वह 10-30 जुलाई के दौरान घरेलू और अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए 42 नए फ्लाइट लांच करेगी। कंपनी सूरत से जबलपुर, पुणे, जयपुर, हैदराबाद, कोलकाता, पटना व बेंगलुरु तथा ग्वालियर से अहमदाबाद, मुंबई और पुणे की फ्लाइट का भी संचालन करेगी। कंपनी के अनुसार वह पटना-कोलकाता, अहमदाबाद-उदयपुर तथा बेंगलुरु-कोच्चि मार्गों पर भी विमान सेवा देगी। इनमें से कई मार्गों पर कंपनी पहली बार विमानों का परिचालन करने वाली है। (प्रेट्र)

आइसीआइसीआइ प्रू ने पेश किया फ्लेक्सीकैप फंड

नई दिल्ली : आइसीआइसीआइ प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने आइसीआइसीआइ प्रूडेंशियल फ्लेक्सीकैप फंड लांच किया है। यह ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है। इसका उद्देश्य इन-हाउस मार्केटकैप आवंटन मॉडल के आधार पर पूरे बाजार पूंजीकरण में इक्विटी और इक्विटी से संबंधित सिक्युरिटीज में निवेश करके पूंजी में वृद्धि करना है। इस फंड का लक्ष्य लार्ज, मिड और स्मॉलकैप के क्षेत्र में अवसरों की पहचान करना है। इसका दायरा एसएंडपी बीएसई-500 होगा। स्टॉक चयन कंपनी के फंडामेंटल और वैल्यूएशन जैसे कई मापदंडों पर आधारित होगा। (जाब्यू)

पुरी के सामने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की चुनौती

घटने के बजाय पेट्रोलियम आयात पर बढ़ी है देश की निर्भरता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : रोजाना बढ़ रही कीमतों के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय में कोई भी मंत्री आए, दाम को काबू में लाना उसकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल व डीजल के दाम में बढ़ोतरी का सिलसिला गुरुवार को हरदीप सिंह पुरी के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का कार्यभार संभालने के दिन भी जारी रखा है। यही नहीं, रसोई में पाइप के जरिये पहुंचाई जाने वाली गैस (पीएनजी) और वाहनों में इस्तेमाल होने वाले सीएनजी की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। माना जा रहा है कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों को लेकर कई देशों के साथ बातचीत हो रही है तो कई देशों में राजदूत रह चुके हरदीप पुरी का अनुभव खासा उपयोगी साबित होगा।

सरकारी तेल कंपनियों ने गुरुवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इस साल की 62वीं वृद्धि की। मुंबई, दिल्ली समेत देश के सभी महानगरों में पेट्रोल 100 रुपये के पार कर चुका है। कई राज्यों में डीजल भी 100 रुपये प्रति लीटर के ऊपर बिक रहा है। गुरुवार की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100.56 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर हो चुकी है। हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय में पहुंचने के बाद इस सवाल का स्पष्ट जवाब देने से बचते हुए उन्होंने कहा कि देश में कच्चा तेल और गैस उत्पादन बढ़ाना उनकी एक अहम प्राथमिकता होगी।



नई दिल्ली में गुरुवार को पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बात करते नए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी • प्रेट्र

पुरी वर्ष 1974 बैच के आइएफएस अधिकारी हैं। पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय का कार्यभार देने के पीछे एक वजह यह माना जा रहा है कि वह तेल उत्पादक देशों के अलावा अमेरिका और रूस जैसे ऊर्जा साझेदारों के साथ बेहतर सामंजस्य स्थापित करने वाले साबित होंगे। वर्ष 2015 में ऊर्जा संगम कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयातित तेल पर निर्भरता में वर्ष 2020 तक पांच फीसद कटौती का लक्ष्य रखा था लेकिन इस दौरान आयातित क्रूड पर भारत की निर्भरता बढ़कर 85 फीसद हो गई है। विश्व से सस्ता क्रूड लाने में उन्हें अपनी दक्षता दिखानी होगी।

पेट्रोलियम उत्पादों की लगभग हर दूसरे दिन हो रही बढ़ोतरी पर किसी न किसी सूरत में लगाम लगाना पुरी की सबसे बड़ी चुनौती होगी। यह तभी होगा अगर वह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को केंद्रीय उत्पाद शुल्क घटाने के लिए तैयार कर लें, या फिर राज्य सरकारों को वैट की दरों में कटौती के लिए मना लें।

संहिता लागू करवाने में भूपेंद्र को करना होगा श्रम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : नए श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कार्यभार संभालते ही अधिकारियों को नए विचारों के साथ आने को कहा है, ताकि विभिन्न योजनाओं को समय सीमा के भीतर लागू किया जा सके। यही उनकी चुनौती है।

दरअसल, पूर्व श्रम मंत्री संतोष गंगवार समय सीमा खत्म होने के बावजूद श्रम संहिता लागू नहीं करा पाए। प्रवासी श्रमिकों की सुविधाओं के लिए पोर्टल भी आरंभ नहीं हो पाया। कोरोना काल में प्रवासी मजदूर गंभीर राजनीतिक मुद्दा बन गए थे। असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना भी नए मंत्री की प्रमुख चुनौतियों में शामिल है।

वर्तमान राजग सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में सभी श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में बदलकर उसे लागू करवाने की घोषणा की थी। चार श्रम संहिताओं के लागू होते ही 44 प्रकार के केंद्रीय श्रम कानून निरस्त हो जाएंगे। इससे भारत में श्रम कानून की पेचीदगियों को लेकर कारोबार में होने वाली दिक्कतें दूर होंगी और भारत में औद्योगिक निवेश में बढ़ोतरी होगी।



नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालय में पदभार संभालने के बाद मीडिया का अभिवादन करते केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव • प्रेट्र

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराना भी नए मंत्री की प्रमुख चुनौतियों में शामिल

पिछले वर्ष संसद से पारित श्रम संहिताओं को अभी तक अधिसूचित नहीं किया जा सका है। श्रम संहिता के अधिसूचित होने के बाद मंत्रालय वेज बोर्ड गठित करेगा जो न्यूनतम वेतन का प्रारूप तैयार करेगा। पिछले वर्ष श्रम मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल, 2021 से श्रम संहिताओं को लागू कर दिया जाएगा। लेकिन इस काम में मंत्रालय सफल नहीं रहा।

नए श्रम मंत्री के सामने दूसरी प्रमुख चुनौती प्रवासी श्रमिकों का पोर्टल शुरू करवाना है। कोरोना की पहली लहर में प्रवासी श्रमिकों को होने वाली दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने इनके रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल आरंभ करने का निर्णय लिया था।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी मंत्रालय को पोर्टल में देरी को लेकर झाड़ लगाते हुए इस वर्ष दिसंबर तक प्रवासी श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन पूरा करने को कहा था। मंत्रालय के समक्ष निर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों को आयुष्मान भारत कार्यक्रम से जोड़ने की भी चुनौती होगी।

निर्यात योजनाओं पर प्रोत्साहन लाभ स्थगित

नई दिल्ली, प्रेट्र : वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यात योजनाओं के तहत विभिन्न प्रोत्साहन लाभों को अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिया है। मंत्रालय ने आवंटन प्रक्रिया में बदलाव को इसकी वजह बताया है। निर्यातकों को मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआइएस), सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (एसईआइएस), रिबेट ऑफ स्टेट लेवीज (आरओएसएल) और रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेज एंड लेवीज (आरओएससीटीएल) जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। निर्यात की प्रकृति के आधार पर केंद्र सरकार निर्यातकों को ड्यूटी क्रेडिट सर्टिफिकेट जारी करती है। निर्यातक इनका उपयोग बेसिक कस्टम ड्यूटी समेत विभिन्न शुल्कों के भुगतान में कर सकते हैं।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटन प्रक्रिया में बदलाव किए जा रहे हैं। इस वजह से इस अस्थायी स्थगन अवधि के दौरान इन योजनाओं के तहत लाभ लेने के लिए डीजीएफटी के ऑनलाइन आइटी मॉड्यूल पर कोई आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

विदेशी बाजारों के दम पर टीसीएस का लाभ 28% बढ़ा

मुंबई, प्रेट्र : देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून, 2021) में 28.5 फीसद बढ़कर 9,008 करोड़ रुपये पर जा पहुंचा। कंपनी ने कहा कि कोरोना संकट की दूसरी लहर का संक्रमण थामने के लिए राज्यों में लगाए गए लॉकडाउन के चलते घरेलू कारोबार पर खासा असर दिखा है। इससे उसकी सकल विकास दर प्रभावित हुई है। टीसीएस को 10,000 करोड़ डॉलर (करीब सवा सात लाख करोड़ रुपये) मूल्य वाले टाटा ग्रुप की सर्वाधिक कमाई वाली कंपनी मानी जाती है। टीसीएस के साथ ही शेयर बाजारों में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए बड़ी कंपनियों के वित्तीय नतीजों की शुरुआत हो गई है।

टीसीएस ने कहा कि पहली तिमाही के वित्तीय नतीजों में विपरीत धाराओं का समावेश दिख रहा है। एक तरफ अमेरिका जैसे बड़े बाजारों और बैंकिंग जैसे प्रमुख सेक्टरों में कारोबार ने अच्छी विकास दर दिखाई है। दूसरी तरफ घरेलू बाजार में कारोबार पिछड़ता दिखाई दे रहा है। फिर भी, कंपनी के लिए भारत एक परंपरागत और प्रमुख बाजार रहा है। यहां भी बीते दिनों कारोबार में कुछ सुधार दिखा है।

टीसीएस के सीईओ व एमडी राजेश गोपीनाथन ने कहा कि नतीजे दो बाजारों की अलग-अलग कहानी बयां कर रहे हैं। हमारे प्रमुख बाजारों ने बेहद अच्छा प्रदर्शन किया है। दूसरी तरफ हमारे प्रमुख बाजार भारत में कारोबार खासा प्रभावित हुआ है। भारतीय बाजार में समीक्षाधीन तिमाही के दौरान कंपनी का राजस्व 14% गिरकर 2,085 करोड़ रुपये रह गया।

राज्यों को चौथी किस्त में 9,871 करोड़ जारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : वित्त मंत्रालय ने संसाधनों के बंटवारे के बाद राज्यों के राजस्व घाटे (पीडीआरडी) की क्षतिपूर्ति के तहत 17 राज्यों को अनुदान की 9,871 करोड़ की चौथी किस्त जारी कर दी है। किस्त के साथ इस मद में राज्यों को कुल 39,484 करोड़ जारी किए जा चुके हैं।

वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 17 राज्यों को पीडीआरडी अनुदान के रूप में 1,18,452 करोड़ देने की सिफारिश की थी। इसमें से चार किस्तों में 39,484 करोड़ की रकम जारी की गई है। राज्यों की आय और खर्च के अंतर को आधार बनाकर वित्त आयोग यह फैसला करता है। 15वें वित्त आयोग ने पीडीआरडी अनुदान को आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और बंगाल की सिफारिश की थी।

आयात घटा तो लेदर इंडस्ट्री को मिला दम

जागरण संवाददाता, आगरा : चीन से आयातित फुटवियर पर शुल्क 25 से बढ़कर 35 फीसद होने से घरेलू बाजार में आगरा की हिस्सेदारी 55 फीसद से बढ़कर 65 फीसद हो गई है। देश के इस फुटवियर हब को बाटा, पेंटालून समेत कई बड़ी कंपनियों के भी आर्डर मिले है। अमेरिका समेत 15 देशों से भी ऑर्डर मिलने की उम्मीद बढ़ी है। आगरा फुटवियर मैन्यूफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स चेंबर (एफमेक) के प्रेसिडेंट पूरन डावर का कहना है कि कोरोना काल से पूर्व यहां प्रतिदिन करीब 10 लाख जोड़ी जूते तैयार होते थे। मार्च, 2020 में कारोबार करीब 10 फीसद प्रभावित हुआ। हालांकि अब स्थिति सामान्य है। शीघ्र ही अमेरिका समेत 15 देशों से बड़े ऑर्डर मिलने की उम्मीद है।

एफमेक के वाइस प्रेसिडेंट रूबी सहगल ने बताया, उनका ध्यान इस समय घरेलू बाजार पर है। आगरा से यूरोपीय देशों को 80% व अमेरिका को 16% फुटवियर निर्यात होता है। इस बार अमेरिका को अधिक फुटवियर निर्यात होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि आयात शुल्क बढ़ने से चीन के जूते महंगे हो गए हैं। इससे एक हजार रुपये तक की कीमत के जूते बनाने वाली इकाइयों को संजीवनी मिल गई है।

चर्म निर्यात परिषद (सीएलई) ने हाल में 2020 और 2021 के मार्च-अप्रैल के तुलनात्मक आंकड़े जारी किए थे। वित्तीय वर्ष 2020-21 में संक्रमण से 2019-20 की अपेक्षा चर्म उत्पादों व जूते के निर्यात में 27.72% की गिरावट दर्ज की गई थी। सीएलई ने वर्ष 2021 के अप्रैल-मई के आंकड़ों को उत्साहजनक माना है। इस अवधि में 64.17 करोड़ डॉलर यानी 4,620 करोड़ रुपये मूल्य से अधिक का निर्यात हुआ। पिछले वर्ष अप्रैल-मई में 14.68 करोड़ डॉलर यानी 1,057 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात हुआ था।



चीन से आयातित फुटवियर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने का पड़ा असर, देश में आगरा की हिस्सेदारी 10 फीसद बढ़ी • फाइल फोटो

जूता उद्योग : एक नजर

- आगरा से करीब 5,000 करोड़ रुपये मूल्य का फुटवियर निर्यात होता है
- निर्यात में यूरोपीय देशों की 80 फीसद और अमेरिका की करीब 16 फीसद हिस्सेदारी है
- देश के फुटवियर निर्यात में आगरा की 28 फीसद भागीदारी है।
- घरेलू फुटवियर बाजार में आगरा की 60 फीसद भागीदारी है

बिजली की मांग रिकॉर्ड 200 गीगावाट के पार

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश में बिजली की मांग बुधवार को 200 गीगावाट के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गई। मानसून में देरी के कारण पारा चढ़ने और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में ढील के बाद बिजली की मांग बढ़ी है। बिजली मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार बिजली की अधिकतम मांग या सर्वाधिक आपूर्ति बुधवार को 200.57 गीगावाट पहुंच गई। इससे पहले मंगलवार को बिजली की अधिकतम मांग रिकॉर्ड 197.07 गीगावाट पर पहुंची थी।

विशेषज्ञों के अनुसार मानसून में देरी के कारण कई राज्यों में गर्मी काफी बढ़ी हुई है। वहीं, अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन में चरणबद्ध ढील से उद्योग जगत की गतिविधियों में तेजी आई है। इससे बिजली की मांग बढ़ रही है। पिछले महीने बिजली की अधिकतम मांग 30 जून को 191.51 गीगावाट पहुंच गई थी।

न्यूज गैलरी

डेढ़ किलो अफीम व ड्रग मनी सहित तीन गिरफ्तार

अबोहर (फाजिल्का) : पुलिस की नारकोटिक्स सेल ने डेढ़ किलो अफीम व एक लाख की ड्रग मनी के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। नारकोटिक्स सेल के प्रभारी सज्जन सिंह ने बताया कि आरोपितों की पहचान राधेश्याम निवासी पिपरवान, निवासी नीमच (मप्र), मल्ला सिंह उर्फ सोभा सिंह और गुरमीत सिंह उर्फ हैप्पी निवासी फिरोजपुर के रूप में हुई। (संस)

हरकी पैड़ी पर हुक्का पीने वालों को तीर्थ पुरोहितों ने पीटा

हरिद्वार : हरकी पैड़ी पर गंगा स्नान के दौरान हुक्का पी रहे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के यात्रियों को तीर्थ पुरोहितों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। गुस्साए पुरोहितों ने उनका हुक्का भी तोड़ दिया। पुलिस ने हंगामा शांत कराते हुए छह आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। (जासं)

पूर्वांचल में कुदरत का कहर वज्रपात से चार की मौत

वाराणसी : पूर्वांचल में मऊ, आजमगढ़ और गाजीपुर में आकाशीय बिजली गिरने से चार लोगों की मौत हो गई। मऊ के मधुबन थाना क्षेत्र के गंगउपुर गांव में शिवधर प्रसाद तथा राजनाथ यादव सुबह पशुओं को चराने खेत में गए थे। आजमगढ़ के लंगड़पुर गांव निवासी झिनकी अपने खेत में धान की रोपाई कर रही थीं। गाजीपुर के बेनसागर गांव निवासी विक्रम यादव की भी मौत हो गई। (जासं)

डंपर ने एक ही परिवार के पांच लोगों को कुचला

जयपुर : राजस्थान में झालावाड़ जिले के मंडावर थाना इलाके में एक डंपर ने एक ही परिवार के पांच सदस्यों को कुचल दिया। पुलिस थानाप्रभारी बृजराज सिंह ने बताया मरने वालों में सुरेश और उसकी पत्नी सीता के साथ ही बच्चे पवन, कमलेश और निर्मल शामिल हैं। (जासं)

छत्तीसगढ़ के दो नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

सुकमा : छग के सुकमा जिले में सक्रिय दो नक्सलियों हमेला रामा और मड़कम पायकी ने तेलंगाना के कोत्तागुड़म जिला मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। (नईदुनिया)

अपराध के वक्त नाबालिग घोषित 13 कैदियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अपराध के समय 18 वर्ष से कम आयु यानी किशोर (नाबालिग) होने के आधार पर रिहाई मांग रहे आगरा सेंट्रल जेल में बंद 13 कैदियों को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। जुवेनाइल जस्टिस (जेजे) बोर्ड ने अपनी जांच में इन कैदियों को अपराध के वक्त नाबालिग यानी किशोर घोषित किया है। हालांकि बोर्ड का आदेश आने तक हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा पाए ये 13 कैदी 14 से 22 साल तक की सजा भुगत चुके हैं।

गुरुवार को जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस वी. रामासुब्रामण्यम की पीठ ने याचिकाकर्ताओं के वकील ऋषि मल्होत्रा और उत्तर प्रदेश सरकार की वकील गरिमा प्रसाद की दलीलें सुनने के बाद सभी 13 कैदियों को अंतरिम जमानत पर निजी मुचलके पर तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने अपने आदेश में घोषित किया है कि ये 13 याचिकाकर्ता अपराध के वक्त किशोर थे। कोर्ट ने गरिमा प्रसाद से कहा कि अगर ये सभी तीन साल से ज्यादा की कैद काट चुके हैं तो इन्हें रिहा किया जाना चाहिए। प्रसाद ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रथमदृष्टया पाया है कि जेजे बोर्ड ने अपने आदेश में इन सभी को अपराध के वक्त किशोर होना पाया है। ऐसे में राज्य सरकार को इन्हें अंतरिम जमानत दिए जाने पर आपत्ति नहीं है। सभी के खिलाफ अदालत के अलग आदेश हैं।

वैवाहिक अधिकारों के प्रविधानों को निरस्त करने का आग्रह

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उन याचिकाओं को महत्वपूर्ण करार दिया, जिनमें वैवाहिक कानून से संबंधित उन प्रविधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, जो अदालतों को अलग रह रहे दंपतियों को यह कहने की शक्ति प्रदान करते हैं कि वे वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए शारीरिक संबंध बनाएं। शीर्ष अदालत ने केंद्र को इस मुद्दे पर 10 दिन के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। जस्टिस आरएफ नरीमन, केएम जोसेफ और बीआर गवई की पीठ ने मामले को 22 जुलाई को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। इसके साथ ही इस मामले में हस्तक्षेप के लिए दाखिल विभिन्न आवेदनों को इसकी अनुमति भी प्रदान कर दी। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि उन्हें लिखित अभिवेदन दायर करने के लिए समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में वेणुगोपाल से मदद मांगी थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि मामला हिंदू विवाह अधिनियम की धारा-9 और अन्य संबंधित प्रविधानों की वैधता के संबंध में कानून से जुड़े सवाल का है। इसलिए कम अवधि की तारीख देनी चाहिए। पीठ ने कहा कि वह मामले पर दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगी।

येदियुरप्पा व अन्य के खिलाफ दाखिल निजी वाद खारिज

बेंगलुरु, प्रेट्र : कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित एक अदालत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, उनके पुत्र, रिश्तेदार व एक मंत्री के खिलाफ दाखिल निजी वाद (प्राइवेट कंप्लेंट) को खारिज कर दिया। इसमें सभी के खिलाफ एक आवासीय परियोजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उसकी जांच कराने की मांग की गई थी। येदियुरप्पा, उनके बेटे व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र, दामाद वीरूपक्ष, नाती-पोते शशिधर, संजय श्री, चंद्रकांत, मंत्री एसटी सोमशेखर तथा आइएएस अधिकारी जीसी प्रकाश व के. रवि के खिलाफ यह वाद टीजे अब्राहम ने दाखिल किया था। उसने आरोप लगाया था कि बेंगलुरु विकास प्राधिकरण की एक आवासीय परियोजना में हुए भ्रष्टाचार में येदियुरप्पा व अन्य की संलिप्तता है। उसने अदालत से मामले में संज्ञान लेने की अपील की थी। अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता के आरोपों में दम नहीं है, इसलिए उस पर कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसके बाद कोर्ट ने वाद को खारिज कर दिया।

...तो विधवाओं व अनाथों से भर जाएगा समाज : हाई कोर्ट

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

नसीहत

- जहरीली शराब बेचने के मामले में आरोपित की जमानत याचिका खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने की टिप्पणी
- पैसा कमाने की इच्छा से जहरीली शराब बेचकर लोगों का जीवन छीनने वाले रहम के हकदार नहीं

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने जहरीली शराब बेचने के मामले में आरोपित की जमानत याचिका को खारिज करते हुए सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि ऐसे लोगों को रिहा किया गया तो समाज अनाथों और विधवाओं से भर जाएगा। कुछ पैसों के लिए लोगों का जीवन छीनने वाले किसी भी प्रकार से रहम के हकदार नहीं हैं।

तरनतारन के रहने वाले अवंश सिंह ने याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट को बताया कि 22 अगस्त, 2020 को जहरीली शराब के मामले में एफआइआर दर्ज की गई थी। इस एफआइआर में याची का नाम भी नहीं था, फिर भी उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले दस माह से वह जेल में है। ऐसे में मामले से कोई लेना-देना न होने की बात करते हुए जमानत की मांग की। पंजाब सरकार ने कहा कि उनके पास पर्याप्त सुबूत हैं कि याची तस्करी में लिप्त था और याची पर 31 जुलाई, 2020 को पहले ही एक मामला दर्ज है, जो जहरीली शराब की तस्करी का है। उस मामले में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी और कुछ की आंखें भी चली गई थीं।

हाई कोर्ट ने इसपर कहा कि याचिकाकर्ता पर समाज के खिलाफ जघन्य अपराध का आरोप है। जहरीली शराब को समाज के वंचित वर्ग को बेचने के लिए तैयार किया जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों में इसके चलते हुई त्रासदियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि इस तरह के व्यक्तियों को जमानत पर रिहा किया गया तो वे समाज की व्यवस्था को और खराब कर देंगे।

राष्ट्रीय खेल घोटाले में ईडी ने तेज की जांच, लिए जा रहे बयान

राज्य ब्यूरो, रांची

झारखंड में 2011 के बहुचर्चित 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने जांच तेज कर दी है। ईडी की टीम एक-एक कर सभी आरोपितों का पक्ष ले रही है, ताकि घोटाले से संबंधित सभी तथ्य सामने आ सकें। दो दिन पहले ही झारखंड उच्च न्यायालय ने एक आरोपित आरके आनंद की याचिका खारिज कर दी थी। आरके आनंद ने एसीबी में अपने उपर दर्ज प्राथमिकी को नियम विरुद्ध व गलत बताते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जहां उनकी याचिका खारिज हो गई थी।

28 करोड़ 38 लाख रुपये के इस घोटाले में एसीबी ने सभी आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया था। आरोपितों में एसीबी ने इस मामले में आयोजन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष आरके आनंद, सचिव एसएम हाशमी, कोषाध्यक्ष मधुकांत पाठक, तत्कालीन खेल निदेशक पीसी मिश्रा शामिल हैं, जिनके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया गया था। इसके अलावा दो स्क्वैश ग्राउंड बनाने में अनियमितता को लेकर पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को भी आरोपित बनाया गया था। एसीबी के चार्जशीट के आधार पर ही ईडी ने मनी लांड्रिंग अधिनियम के तहत पिछले वर्ष केस दर्ज किया था। इसके बाद से ही पूरे मामले की जांच जारी है। इस घोटाले से संबंधित जो-जो आरोपित हैं उन्हें ईडी नोटिस जारी कर उनका पक्ष रखने को कहा है। ईडी की टीम एक-एक कर सभी आरोपितों का बयान लेगी और उसकी समीक्षा करेगी। एसीबी से मिले घोटाले से संबंधित दस्तावेजों से ईडी की टीम आरोपितों के बयान का मिलान करेगी। मनी लांड्रिंग एक्ट में घोटाले की स्थिति स्पष्ट होने के बाद जो भी पदाधिकारी दोषी मिलेंगे, उनकी संपत्ति जब्त करने की भी कार्रवाई होगी।

कोयला तस्करी : ईडी ने सात आइपीएस को किया तलब

कोलकाता : कोयला तस्करी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ज्ञानवंत सिंह सहित सात आइपीएस अधिकारियों को पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि आइपीएस अधिकारी चाहें तो वर्चुअल माध्यम से उपस्थित होकर सवालों के जवाब दे सकते हैं। गौरतलब है कि इस मामले में इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी और उनके रिश्तेदारों से पूछताछ हो चुकी है। इनमें आइपीएस कोटेश्वर राव और आइपीएस सिल्वा मुरुगन को 26 जुलाई, आइपीएस श्याम सिंह को 30 जुलाई, आइपीएस राजीव मिश्रा को दो अगस्त, आइपीएस सुकेश जैन को चार अगस्त, आइपीएस ज्ञानवंत सिंह को पांच अगस्त तथा आइपीएस तथागत बसु को आठ अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

बीसीसीसी बनी गैर समाचार चैनलों के लिए स्वनियामक इकाई

- टीवी चैनलों की सामग्री के खिलाफ आई शिकायतों का करवाएगी समयबद्ध निस्तारण

नई दिल्ली, प्रेट्र : ब्राडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल (बीसीसीसी) को केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियमावली के तहत गैर समाचार चैनलों के खिलाफ शिकायतों के निस्तारण के लिए स्वनियामक के तौर पर पंजीकृत किया गया है। हाल में जारी अधिसूचना के अनुसार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बीसीसीसी को उसके सदस्य चैनलों के लिए द्वितीय श्रेणी के स्वनियामक के तौर पर पंजीकृत किया है। यह टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री के खिलाफ आई शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के लिए तीन स्तरीय वैधानिक तंत्र प्रदान करेगी। बुधवार को इंडियन ब्राडकास्टिंग फाउंडेशन (आइबीएफ) को औपचारिक तौर पर दी गई सूचना के अनुसार, 'बीसीसीसी केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियमावली-2021 के नियम-18 में स्वनियामक के लिए उल्लेखित कार्य करेगी।' बीसीसीसी महासचिव आशीष सिन्हा ने कहा, 'विद्वान अध्यक्षों के नेतृत्व में बीसीसीसी द्वारा 10 साल तक किए गए कठिन कार्यों को मिली मान्यता से मैं खुश हूं।' केंद्र सरकार द्वारा मई में अधिसूचित संशोधित नियमावली के मुताबिक टीवी चैनलों के स्वनियामक निकाय का केंद्र सरकार के पास पंजीयन अनिवार्य है।

ज्ञात हो, कि बीसीसीसी का गठन जून 2011 में आइबीएफ ने देश में मौजूद करीब 300 गैर समाचार चैनलों की सामग्री से संबंधित शिकायतों का परीक्षण करने वाले स्वनियामक निकाय के तौर पर की थी। जस्टिस (अवकाश प्राप्त) एपी शाह बीसीसीसी के संस्थापक अध्यक्ष थे। अब गीता मित्तल निकाय की प्रमुख हैं।

सामान लेने आई बच्ची को पांच घंटे तक बंधक बना दुकानदार ने किया दुष्कर्म

जासं, कन्नौज : दुकान पर सामान लेने गई आठ वर्षीय बच्ची को दुकानदार ने बंधक बना लिया और दुष्कर्म किया। पांच घंटे तक बच्ची आरोपित के कब्जे में रही। पुलिस ने आरोपित दुकानदार को हिरासत में लेने के साथ ही बच्ची को अस्पताल भेजा। बच्ची की मां ने सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है।

शहर के मोहल्ला दीदारगंज निवासी एक महिला ने बताया कि उनकी बेटी मोहल्ले की ही एक दुकान पर सामान लेने के लिए गई थी। वहां कोई दूसरा ग्राहक नहीं था। दुकानदार ने उसे मकान के अंदर बुला लिया और कमरे में बंधक बना लिया। दुकान बाहर से बंद कर ली। इसके बाद दुष्कर्म किया। जब काफी देर तक बेटी घर नहीं आई तो दुकान पर जाकर पता किया। वहां बेटी बदहवास हालत में मिली। प्रभारी निरीक्षक विकास राय ने बताया आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है।

250 एक्सट्रीम वेदर से जुड़ी घटनाएं हुई थीं 1970 से 2005 के बीच दुनिया में स्काईमेट के मुताबिक, लेकिन 2005 से 2020 के मध्य ऐसी घटनाओं की संख्या 150 रही।

आजकल



अभिषेक कुमार सिंह
संस्था एफआइएस ग्लोबल से संबद्ध

बार-बार प्रचंड रूप दिखाता मौसम

मानसून के सीजन में बारिश की बौछारों से सराबोर रहने वाले हमारे देश का उत्तरी इलाका इस साल मध्य जून से लेकर जुलाई के शुरुआती हफ्ते में बुरी तरह तपता रहा है। कुछ उसी तरह कनाडा, अमेरिका से लेकर फिनलैंड के कई इलाके ऐतिहासिक रूप से उच्च तापमान की चपेट में आए हैं। इन मौसमी घटनाओं ने पर्यावरणविदों के माथे पर पसीना ला दिया है। जलवायु परिवर्तन की इन कठिन चुनौतियों को हम फिर अपने समक्ष देख रहे हैं और खुद से पूछ रहे हैं कि आखिर पारा कहां जाकर रुकेगा



हमारी हरकतों से बढ़ रहा धरती का तापमान। फाइल

मौसम का बदलना नया नहीं है। हमारी पृथ्वी इस मामले में अनूठी है कि इसके ज्यादातर हिस्सों में ऋतुओं का आना-जाना लगा रहता है। हालांकि कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां मौसम बमुश्किल बदलता है। कुछ इलाकों में सदा बर्फ जमी रहती है तो कुछ इलाके हमेशा सूरज की गर्मी से तपते रहते हैं। भारत जैसे ऊष्ण-कटिबंधीय देशों में गर्मी की अधिकता रहती है तो भी जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में मौसम ज्यादातर वक्त ठंडा और खुशगवार रहता है। हमारे देश के इन हिस्सों की तरह ही दुनिया के कुछ देश अपनी ठंड के लिए ज्यादा मशहूर रहे हैं, लेकिन ये खुशगवारी अब गुम हो रही है। जो इलाके बर्फ से ढके-छिपे रहते थे, अब वहां भी प्रचंड गर्मी अपना असर दिखा रही है। मानसून के जिस सीजन में बारिश की बौछारों से सराबोर रहने वाले हमारे देश का उत्तरी इलाका इस साल मध्य जून से लेकर जुलाई के शुरुआती हफ्ते में बुरी तरह तपता रहा है, वैसे ही कनाडा से लेकर फिनलैंड के उत्तरी आर्कटिक इलाके ऐतिहासिक उच्च तापमान की चपेट में आए हैं। इन मौसमी घटनाओं ने एक बार फिर आम लोगों, विज्ञानियों और पर्यावरणविदों के माथे पर पसीना ला दिया है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की कठिन चुनौतियों को हम फिर अपने सामने उपस्थित देख रहे हैं और खुद से पूछ रहे हैं कि आखिर पारा कहां जाकर रुकेगा।

खबर ये गर्म है: गर्मी को लेकर हाल की सूचनाओं पर गौर करें तो पता चलता है कि भारत की राजधानी दिल्ली में पहली जुलाई को बीते एक दशक का कीर्तिमान तापमान के मामले में बन गया। उस दिन पारा 43.1 डिग्री तक पहुंचा था। करीब एक दशक में इसे गर्मी का नया रिकॉर्ड मानकर दर्ज किया गया। यही हाल मानसून को तरसते देश के मध्य और उत्तरी राज्यों जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहा। इन इलाकों में सामान्य से चार से छह डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान मध्य जून से जुलाई के आरंभ में दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान की परिभाषाओं में देखें तो इतना ऊंचा तापमान लू (हीटवेव) और भीषण लू (सीवियर हीटवेव) पैदा करता है। इन उत्तरी राज्यों में पाकिस्तान से आती गर्म हवाएं भीषण लू का कारण बनी हैं, पर सवाल है कि अमेरिका, कनाडा और फिनलैंड जैसे ठंडे मुल्कों में क्या हुआ है। अमेरिका में वाशिंगटन और ऑरेगन तो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में तापमान ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचा है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के लिटन गांव में हाल में तापमान करीब 50 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे वहां अचानक करीब 150 लोगों की मौत हो गई। कनाडा के इन इलाकों के निवासियों को इतनी गर्मी का कभी सामना नहीं करना पड़ा था। कनाडा का मौसमी इतिहास बताता है कि वहां किसी भी इलाके में तापमान 45 के पार पहुंचा ही नहीं था। ऐसे में प्रचंड तापमान से पहली बार सामना होने पर लोगों का शरीर जवाब दे गया और वे या तो बीमार पड़ गए या उनकी मौत की आशंका पैदा हो गई। यही हाल अमेरिका के पश्चिमी इलाकों का हुआ है। वाशिंगटन और ऑरेगन जैसे इलाकों में आर्कटिक तथा कैलिफोर्निया से आई गर्म हवाओं ने हीटवेव यानी लू पैदा कर दी। सुनने में आश्चर्यजनक लग सकता है, पर यूरोप खासकर पूर्वी और मध्य यूरोप के कई देशों के अलावा रूस, जर्मनी, इटली, फिनलैंड और यहां तक कि सबसे ठंडे इलाकों में से एक माने जाने वाले साइबेरिया में भी हीटवेव चल रही है।

क्या हैं चुनौतियां : मौसम परिवर्तन से बारिश होती है, बर्फ पड़ती है, नदियों-झीलों और महासागरों में पानी आता है। भारतीय मानसून को इसका क्रेडिट दिया जाता है कि चार महीने की इस मौसमी परिघटना में दुनिया का तापमान काबू में रखने की अद्भुत क्षमता है। इसी तरह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पड़ने वाली ठंड और गर्मी से जलवायु संतुलित रहती है। यही संतुलन धरती पर जीवनयोग्य माहौल तथा फसल-चक्र को कायम रखने में मदद करता है, पर बीते कुछ समय से मौसम अपना विकराल रूप दिखा रहे हैं। बारिश होती है तो जरूरत से ज्यादा होती है, गर्मी पड़ती है तो कीर्तिमान बना देती है। मौसम विज्ञान की परिभाषा में इसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन (किसी मौसमी अवस्था का चरम) कहा जाता है। जरूरत से ज्यादा गर्मी हो, औसत से कम बारिश हो, ज्यादा भूस्खलन हो, भारी वर्षा हो, ओले पड़ने और बादल फटने की घटनाएं बढ़ जाएं तो इन सारी घटनाओं को मौसम के बदलते व्यवहार के आधार पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की श्रेणी में रखा जाता है। इसी तरह यदि तीन या दस दिन की अवधि में होने वाली बारिश कुछ ही घंटों में हो जाए तो इस अवस्था को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। पिछले कुछ वर्षों से चेन्नई, मुंबई, दिल्ली-गुरुग्राम से लेकर जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के कई इलाके एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का सामना करने लगे हैं।

पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान : मौसम के बदलावों पर नजर रखने वाली गैर-सरकारी संस्था स्काईमेट के मुताबिक 1970 से 2005 के बीच के 35 सालों में एक्सट्रीम वेदर से जुड़ी 250 घटनाएं हुई थीं, लेकिन 2005 से 2020 के मध्य ऐसी घटनाओं की संख्या 150 रही। इससे साबित होता है कि भारत समेत पूरी दुनिया में एक्सट्रीम वेदर की घटनाओं में कई गुना बढ़ोतरी हो गई है। इन घटनाओं का नुकसान मोटे तौर पर बादल फटने, बाढ़ आने, बेइंतहा गर्मी या सूखे के रूप में नजर आते हैं, पर दीर्घकालिक नजरिये से ये और भी ज्यादा नुकसान हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचा रहे हैं। मिसाल के तौर पर शहरों में बाढ़ की घटनाओं में इजाफे के बावजूद तेजी से घटता जलस्तर यह साबित करता है कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का कितना खामियाजा धरती उठा रही है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि यदि तीन दिनों की बारिश एक झटके में तीन घंटे में हो जाए तो सारा पानी धरती की ऊपरी सतह से नालों में और फिर नदियों-समुद्रों में पहुंच जाता है। वह धरती के अंदर नहीं पहुंचता, जिससे जल स्तर में कोई इजाफा नहीं होता। विडंबना यह भी है कि ऐसा दिल्ली, मुंबई या चेन्नई जैसे महानगरों में ही नहीं हो रहा है, बल्कि असामान्य वर्षा का यह पैटर्न अब ज्यादातर राज्यों में नियमित तौर पर दिख रहा है।

बहरहाल भारी बारिश और भीषण गर्मी यानी तापमान की ऊंचाई के टूटते रिकार्ड यह सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसे रोका कैसे जाए? इन सवालों के जवाब बहुत सीधे हैं। अरसे से बताया जा रहा है कि 2025 तक ही दुनिया पूर्व-औद्योगिक काल से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक तक गर्म हो सकती है। हाल में विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर दुनिया ने अब भी पेरिस समझौते के तहत वैश्विक औसत तापमान में दो डिग्री सेल्सियस से अधिक वृद्धि न होने देने के प्रयासों पर अमल नहीं किया तो इससे भी ज्यादा खराब हालत देखने के लिए तैयार रहना होगा। समझना होगा कि जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल-डीजल) से चलने वाली कारों के अंधाधुंध इस्तेमाल, घरों को ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशनरों की फौज की तैनाती और ग्लोबल वॉर्मिंग को बढ़ावा देने वाली नीतियों पर अंकुश नहीं रखने की नीति मौसमों को खतर रूप दे रही हैं। ऐसे में राहत तभी मिलेगी, जब जलवायु परिवर्तन थामने वाली कोशिशों को लंबे समय तक कायम रखा जाएगा।

अटकता-भटकता मानसून

भारतीय मौसम विभाग ने इस वर्ष सामान्य से बेहतर मानसून की भविष्यवाणी की थी। इस भविष्यवाणी के मुताबिक देश में 101-104 प्रतिशत मानसूनी बारिश का अनुमान लगाया गया था। इस दौरान औसतन 880 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना थी। आरंभ में जब एक जून को मानसून ने केरल को छुआ तो लगा कि यह भविष्यवाणी सटीक साबित होगी। जून में देश के अलग-अलग हिस्सों में 188.5 मिलीमीटर बारिश हुई। इस हिसाब से जुलाई से सितंबर के बीच देश में 88 फीसद बारिश बची हुई है। यह सही है कि जून के आरंभ में मानसून कुछ राज्यों को छोड़कर देश के ज्यादातर हिस्सों में अपनी पहुंच बना ली, लेकिन इसके बाद मानसूनी बादलों ने दगा देना शुरू कर दिया। जून के मध्य तक आते-आते कई ऐसी स्थितियां बनीं कि देश के 72 फीसद हिस्से में सामान्य वर्षा नहीं हो पाई। कहीं ज्यादा तो कहीं न्यूनतम बारिश हुई। मानसून की दशा और दिशा बदलने में 15 जून के बाद अरब सागर से उठे चार पश्चिमी विक्षोभों ने बड़ी भूमिका निभाई। इस दौरान हालांकि बिहार जैसे राज्यों में खूब बारिश हुई, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र के ज्यादातर जिलों में बादलों के दर्शन ही दुर्लभ हो गए। हाल में मौसम विभाग ने भी कहा कि दक्षिण-पश्चिम मानसून यूं तो अपने तय वक्त से दो हफ्ते पहले ही पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर पहुंच गया, लेकिन वहां यह ऐसे अटक गया कि न तो बारिश हो रही है और न ही बादल आगे बढ़ रहे हैं।

असल में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्सों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान तक मानसून को पहुंचाने में बंगाल की खाड़ी में होने वाले मौसमी बदलावों की अहम भूमिका रहती है। अगर बंगाल की खाड़ी में कोई मौसमी सक्रियता या मौसम के सिस्टम में कोई हलचल नहीं होती है तो बादलों को आगे ठेलने वाली पूर्वी हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं और मानसून जहां का तहां अटक जाता है। इसके साथ ही इस साल देश के उत्तर-पश्चिम और पश्चिमी भागों में गर्म-शुष्क पछुआ हवाएं चलती रहीं, जिन्होंने मानसून की चाल को अटका दिया। देश के उत्तरी इलाकों में मानसूनी बारिश कराने में एक भूमिका हिमालय की तलहटी में बनने वाली ट्रफ लाइन की भी होती है। बादलों के बीच गर्म और ठंडी हवा के परस्पर मेल से पैदा होने वाले कम दबाव के क्षेत्र में एक सक्रिय पट्टी बनती है, जिसमें बादल बनते और तेजी से आगे खिसकते हैं। यह सक्रिय पट्टी ही ट्रफ लाइन कहलाती है। चूंकि इस वर्ष यह ट्रफ लाइन हिमालय की तरफ ज्यादा खिसक गई, इसलिए नए बादलों का बनना और आगे बढ़ना रुक गया। इससे भी मानसून अटक गया।

खरी-खरी

व्यंग्य संग्रह और खूंखार खंजर

डॉ. पिलकेंद्र अरोरा

एक वाट्सएप मित्र का फोन था-'बधाई पांचवें संग्रह के ऑनलाइन विमोचन की। सच यार, बहुत सशक्त लिखते हो। तुम हो, तो व्यंग्य है, उसका भविष्य है। मैं तो धर्मयुग के युग से तुम्हारा प्रशंसक हूं। क्या भाषा! क्या शैली! क्या विट! क्या ये...क्या वो...! गज्जब।' सुबह-सवेरे प्रशंसा सुनकर मार्निंग वाकई गुड हो गई। तभी वह पिघला-'पुस्तक की एक प्रति तो भेजो यार! तुम्हें पढ़ने की बहुत इच्छा है।' मैंने कहा-'कल ही ग्रुप में लिंक डाली है भाई! अमेजन, फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। 30 प्रतिशत डिस्काउंट और डिलीवरी फ्री।' 'मगर यार, तुम्हारे होते हुए पुस्तक खरीदना शोभा नहीं देता, आत्मा गवाराइच नहीं करती।'- उसने कहा। दिल चाहता है कि तुम अपने सुंदर अक्षरों में 'सप्रेम भेंट' लिखकर अपने आटोग्राफ के साथ पुस्तक मुझे भेंट करो। यार, मैं तुम्हारा लंगोटिया हूं। उसकी टुच्चई देख अपन को अब मजा आने लगा, इसलिए अपन भी दो पायदान नीचे उतरे और बोले-'तुम कहो तो पीडीएफ फारवर्ड कर दूं!' यार, कागज पर पढ़ने का आनंद ही अलग है। तुम मुझे अपना गरीब मित्र सुदामा ही समझ कर पुस्तक दे दो।

मेरा कृष्ण बनने का कतई मूड नहीं था। सो मैंने कहा-'यार मजबूरी है। प्रकाशक ने कुल दस प्रतियां दी हैं। मैं इतनी कम प्रतियों में लंगर कैसे कराऊं? अच्छा, बताओ हमारे सहपाठी संता की किराने की दुकान है। क्या कभी तुमने उससे किराना फ्री मांगा?' भला कोई किराना कैसे मांग सकता है? किराना खरीदना इज्जत की बात है भाई! और किताब खरीदना इज्जत की बात नहीं? मैं तल्खाया। 'तुमसे यह उम्मीद नहीं थी मिस्टर!'

वह यार से मिस्टर तक आ गया। तुम बदल गए हो। घमंड सिर चढ़ गया है। पांच संग्रह क्या छप गए, खुद को शरद जोशी समझने लगे हो! मैं तो तुम्हें प्रोत्साहित करने के लिए पुस्तक मांग रहा था। खरीदना होगा तो 'खून भरी मांग' जैसा कोई ढंग का उपन्यास नहीं खरीद लूंगा। उसने मुझे यह अहसास करवाते हुए फोन काट दिया कि खामखां पांच संग्रह पर मेहनत की पिलकेंदर, अच्छा होता कि एकाध 'खूंखार खंजर' टाइप का उपन्यास ही लिख देता। कम से कम वह बिकता तो सही!

ट्वीट-ट्वीट

अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया भाई और नारायण राणे जी को केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और उससे पहले हिमंता भाई को असम का मुख्यमंत्री, तो इससे यही राजनीतिक संदेश निकलेगा कि कांग्रेस से आने वालों का स्वागत है और उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा।
तहसीन पूनवाला@tehseenp

सिंधिया ने जहां उड़ान भर ली है, वहीं सचिन पायलट अभी भी अटके पड़े हैं।
समीर@BesuraTaansane



मंत्रिमंडल फेरबदल के मूल में सक्षमता और सुशासन ही है, पर इसमें विभागों को सुसंगत बनाना, चुनावी गणित, युवाओं का समावेशन और बेहतर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व भी झलकता है। यह एक शुभ संकेत है।
हर्ष गोयनका@hvgoenka

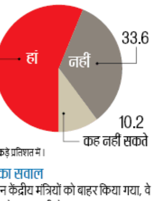
प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार में शानदार फेरबदल किए हैं। खराब प्रदर्शन करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाया, जबकि परखी हुई प्रतिभाओं, उद्यमिता कौशल, महिला सशक्तीकरण और विविधता को प्रोत्साहन दिया।
मालिनी पार्थसारथी@MaliniP

एक छोटे शहर के सरकारी स्कूल में पढ़ने के कारण मैंने अंग्रेजी बहुत देर से सीखी। अभी तक अपने निजी और पेशेवर जीवन में मैंने बढ़िया प्रदर्शन ही किया है। उन तमाम लोगों से तो कहीं बेहतर, जो अपनी अंग्रेजी भाषा कौशल के आधार पर लोगों को परखने में लगे हैं।
अरुण बोथरा@arunbothra

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या विस्तार के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद पहले से अधिक सक्षम दिख रही है?



सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या जिन केंद्रीय मंत्रियों को बाहर किया गया, वे हटाए जाने लायक ही थे?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

जबड़े में घड़ियाल के है अफगानिस्तान,
उसे निगलने जा रहा तालिबान शैतान।
तालिबान शैतान छोड़ भागा अमरीका,
उसने तो जंजाल छुड़ाया अपने जी का।
बैठा पाकिस्तान कर रहा सारे लफड़े,
तालिबान को पाल वही खुलवाए जबड़े।
– ओमप्रकाश तिवारी



प्रदीप शुक्ला
स्थानीय संपादक, झारखंड

झारखंड डायरी

अब तैयारी तीसरी लहर से लड़ने की

कोरोना की दूसरी लहर लगभग अंतिम पड़ाव पर है और राज्य सरकार अब संभावित तीसरी लहर से लड़ने की तैयारियों को पुख्ता करने में जुट गई है। जैसा कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार यह आशंका जता रहे हैं कि यदि तीसरी लहर आती है तो संभव है कि इस बार महामारी की चपेट में सबसे ज्यादा बच्चे आएं। इस बाबत अध्ययन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित एंपावर्ड कमेटी की रिपोर्ट भी ऐसे ही संकेत दे रही है। इसमें जो तथ्य हैं, वह थोड़े डराने वाले हैं। ऐसे में अभी से व्यवस्थाएं चाक-चौबंद करनी जरूरी हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में ढांचागत सुविधाएं बढ़ाने के साथ ही बड़ी संख्या में प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की जरूरत पड़ सकती है।

तीसरी लहर आएगी भी अथवा नहीं? क्या इसमें बच्चे सबसे अधिक प्रभावित होंगे? इसे लेकर भले ही विशेषज्ञों में अभी कोई आम राय नहीं बनी है, लेकिन एंपावर्ड कमेटी ने पिछली दो लहरों के आधार पर अनुमान लगाया है कि नवजात से 18 वर्ष के कुल 1.43 करोड़ बच्चों में यदि पांच प्रतिशत में भी संक्रमण हुआ तो 7.17 लाख बच्चे कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। कमेटी की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि संक्रमित होनेवाले बच्चों में 40 प्रतिशत यानी 2.87 लाख बच्चे कोरोना के लक्षण वाले हो सकते हैं। लक्षण वाले इन बच्चों में 2.35 लाख में सामान्य लक्षण हो सकते हैं, जो घर में भी ठीक हो सकते हैं। वहीं लगभग 43 हजार बच्चे मॉडरेट हो सकते हैं, जिन्हें पीडियाट्रिक वार्ड में भर्ती कराना पड़ सकता है, जबकि तीन प्रतिशत बच्चे गंभीर हो सकते हैं, जिनके लिए आइसीयू की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। मॉडरेट बच्चों में 90 प्रतिशत को आक्सीजन बेड तथा 10 प्रतिशत को हाई डिपेंडेंसी यूनिट की आवश्यकता हो सकती है। कमेटी ने यह भी कहा है कि यदि 10 प्रतिशत बच्चे प्रभावित होते हैं तो सभी आवश्यकताएं दोगुनी हो जाएंगी।



रांची के सदर अस्पताल में बनाए गए शिशु वार्ड का निरीक्षण करते अधिकारी। जागरण

राज्य सरकार ने इस कमेटी की अनुशंसा के आलोक में बच्चों के लिए प्रत्येक मेडिकल कॉलेजों में 100-100 आक्सीजन बेड, 25-25 एचडीयू तथा इतने ही पीडियाट्रिक आइसीयू तैयार करने का निर्णय लिया है। वहीं सभी सदर अस्पतालों में भी 100-100 आक्सीजन बेड, 20-20 एचडीयू तथा 16 पीडियाट्रिक आइसीयू तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह की व्यवस्था कुछ अनुमंडल अस्पतालों व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी होगी। सदर अस्पतालों में बच्चों के लिए चाइल्ड फ्रेंडली वार्ड बनाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी कमी यहां शिशु रोग विशेषज्ञों की है। हालांकि एमबीबीएस चिकित्सकों को ही पीडियाट्रिक आइसीयू के मैनेजमेंट का प्रशिक्षण देकर शिशु रोग विशेषज्ञों की कमी की भरपाई करने की कोशिश की जा रही है। प्रत्येक जिले से दो-दो शिशु रोग विशेषज्ञों, दो-दो चिकित्सा पदाधिकारियों तथा इतने ही स्टाफ नर्स को इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

झारखंड के बच्चों में कुपोषण की भी बड़ी समस्या रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के आंकड़ों के अनुसार यहां के 48 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं। स्वास्थ्य से संबंधित पत्रिका लैंसेट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, कोरोना की वजह से कुपोषित बच्चों की संख्या में लगभग 14 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। राज्य सरकार भी इसे लेकर चिंतित है। कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ी है या नहीं इसकी पुष्टि करने तथा तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए अति कुपोषित बच्चों की पहचान के लिए सघन अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान वैसे बच्चे जिन्हें कुपोषण उपचार केंद्रों पर भर्ती कराना जरूरी है उन्हें भर्ती कराया जाएगा तथा जिन्हें घर पर ही उपचार, पोषक तत्व व परामर्श देकर ठीक किया जा सकता है उन्हें घर पर ही ये सुविधाएं एएनएम के माध्यम से प्रदान की जाएंगी।

इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में अन्य सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। खासकर अस्पतालों में आक्सीजन की किल्लत न हो, इसपर विशेष जोर दिया जा रहा है। राज्य के 52 अस्पतालों में लगाए जा रहे पीएसए आक्सीजन प्लांट इसमें महत्वपूर्ण हैं। इनमें 27 अस्पतालों में ये प्लांट पीएम केयर फंड से स्थापित किए जा रहे हैं। कोरोना जांच की गति और बढ़ाने के लिए उन जिलों में आरटी-पीसीआर लैब स्थापित की जा रही है, जहां यह सुविधा अभी तक नहीं है। पीएम केयर फंड से भी बड़ी संख्या में आक्सीजन कांसेंट्रेटर, आक्सीजन सिलेंडर आदि राज्य के सरकारी अस्पतालों को मिले हैं। चिकित्सकों व पारा मेडिकल कर्मियों की कमी को देखते हुए जिला स्तर पर अनुबंध पर बहाली के निर्देश दिए गए हैं।

घटे दैनिक मामले : झारखंड में कोरोना का संक्रमण फिलहाल पूरी तरह काबू में है। अब यहां के विभिन्न जिलों में छिटपुट मामले ही मिल रहे हैं। पूरे राज्य में दैनिक मामले 50 के आसपास मिलते हैं। अच्छी बात यह है कि कोरोना का संक्रमण काफी कम होने के बाद भी राज्य में जांच की गति कम नहीं की गई है। राज्य में प्रत्येक दिन औसतन 50 हजार सैंपल की जांच अभी भी हो रही है।

स्मरण



शारदा शुक्ला
वरिष्ठ पत्रकार

मुकम्मल फिल्मकार थे गुरु दत्त

गुरु दत्त की फिल्मों को क्लासिक फिल्म का दर्जा प्राप्त है। टाइम मैगजीन ने 'प्यासा' और 'कागज के फूल' को 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में शामिल किया है

गुरु दत्त हिंदी सिनेमा का वह नाम हैं, जो 'चौदहवीं के चांद' की तरह फिल्माकाश पर दिखे तो कम समय के लिए, लेकिन उनकी चांदनी की ठंडक सिनेप्रेमियों को आज भी महसूस होती है। नौ जुलाई गुरु दत्त की जन्मतिथि होती है। जन्मतिथि पर किसी को याद करने की रवायत है तो चलिए याद करें उस चित्रों के चितेरे को, जिसने 'प्यासा' और 'कागज के फूल' जैसी कविताओं को सेल्यूलॉयड पर उतारा। गुरु दत्त हिंदी सिनेमा के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि उनकी फिल्मों को क्लासिक फिल्मों का दर्जा प्राप्त है। टाइम मैगजीन ने 'प्यासा' और 'कागज के फूल' को 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में शामिल किया है। 'प्यासा' गुरु दत्त का सपना था। कहते तो यह भी हैं कि यह उनकी अपनी कहानी है। 'प्यासा' पर उनके जीवन की छाप होना लाजिमी है, क्योंकि गुरु दत्त ने इसकी पटकथा को अपने संघर्ष के दिनों में आत्मकथ्यात्मक शैली में लिखा था। उन दिनों वह मुंबई के माटुंगा में अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहा करते थे। सफलता तो दूर, काम पाने के लिए भी दर-दर भटकना पड़ रहा था। गुरु दत्त ने संघर्ष का लंबा दौर देखा। जो सफलता उन्हें बाद में हासिल हुई उसके पीछे की कहानी काफी उतार-चढ़ाव से भरी हुई है। वह 'प्यासा' पर फिल्म बनाना चाहते थे। छोटी-मोटी सफलताएं मिलने लगी थीं, लेकिन यह उनकी बौद्धिक भूख को शांत करने के लिए नाकाफी थी। 'प्यासा' की स्क्रिप्ट लेकर वह निर्माताओं के पास जाया करते। हर जगह से इन्कार मिलता। कहते तो यहां तक हैं कि एक निर्माता ने 'प्यासा' की स्क्रिप्ट को गुरु दत्त के सामने ही उठाकर फेंक दिया था। इस बात की सच्चाई तो नहीं पता, पर शायद अवहेलना की यही तड़प इस फिल्म में दिखाई देती है। जो हर उस व्यक्ति के दिल को छू जाती है, जिसने कभी न कभी अवहेलना और सामाजिक उपेक्षा का प्याला पिया है।

गुरु दत्त निर्देशक, निर्माता, स्क्रिप्ट राइटर, सिनेमेटोग्राफर और एक्टर भी थे। 1950 से 1962 का समय गुरु दत्त का था। इसी बीच उनकी 'प्यासा' के अतिरिक्त 'कागज के फूल', 'चौदहवीं का चांद', 'साहब बीवी और गुलाम', 'बाजी' और 'मिस्टर मिसेज 55' आदि फिल्में आईं। अभिनेता के तौर पर वह बेहतरीन अदाकार तो थे ही, हैंडसम भी कुछ कम न थे। सूट-बूट में हैंडसम दिखने वाले अभिनेता तो बहुत हैं, पर धोती-कुर्ता जैसे पारंपरिक परिधान में भी वह गजब के सजीले दिखते थे। 'साहब बीवी और गुलाम' के उस गांव के गंवई भूतनाथ को भला कौन भूल सकता है। इन सबसे परे फिल्मी पर्दे पर गुरु दत्त की प्रतिभा उनके कला पक्ष में अद्भुत तरीके से दीप्त हो उठती है। दृश्य को सशक्त बनाने में उनकी लाइटिंग व्यवस्था का जवाब नहीं था। 'कागज के फूल' का एक-एक सीन इसका उदाहरण है। गानों के फिल्मांकन में गुरु दत्त सिद्धहस्त थे। स्टोरी की ही तरह वह गानों को फिल्माने में भी बहुत मेहनत करते थे। 'जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां हैं...' गाना इस बात का सुबूत है।

बहुमुखी प्रतिभा के धनी गुरु दत्त निजी जीवन में एकाकी और दुखी थे। कम लोग जानते हैं कि गीता दत्त से पहले भी गुरु दत्त ने दो शादियां की थीं। उनकी पहली पत्नी का नाम विजया और दूसरी का नाम सुवर्णा था। गीता उनकी सर्वविदित पत्नी थीं। हालांकि उनके साथ भी गुरु दत्त का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहा। वहीदा रहमान के प्रति उनका आकर्षक एक ओपन सीक्रेट है। सब जानते हैं कि गुरु दत्त वहीदा रहमान को चाहते थे, लेकिन वहीदा उनके साथ सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता रखना चाहती थीं। वहीदा रहमान से वह अपने रिश्ते को कोई परिणति नहीं दे पाए और गीता से उनकी निभी नहीं।

गुरु दत्त को करीब से जानने वाले बताते हैं कि उनके स्वभाव में एक अजीब-सी बेचैनी थी। वह कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे। उनका यह स्वभाव उन्हें काम में सफल और रिश्तों में असफल बनाता था। कैफी आजमी ने आकाशवाणी पर दिए एक इंटरव्यू में गुरु दत्त को बेहद निराशावादी बताया था। उनका मानना था कि उदासी और नैराश्य उन्हें आकर्षित करता था। उन्होंने 'कागज के फूल' के समय का एक वाकया भी सुनाया। फिल्म के क्लाइमेक्स के लिए एक गाना चाहिए था। कैफी आजमी ने एक के बाद एक कई गीत लिखकर गुरु दत्त को दिखाए। गुरु दत्त को कोई भी गीत पसंद नहीं आ रहा था। मामला झल्लाहट की हद पर पहुंचने वाला था। आखिरी कोशिश के तौर पर कैफी साहब ने निराशा से भरा गीत लिखा-'देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी... ।' गीत सुनकर गुरु दत्त खुशी से झूम उठे। कैफी साहब इस घटना को गुरु दत्त के निराशावादी स्वभाव से जोड़ते हैं। यही निराशावाद अवसाद का रूप लेकर गुरु दत्त को शराब में डुबो दिया करता था। 10 अक्टूबर, 1964 को गुरु दत्त अपने फ्लैट में मृत पाए गए। उनकी मौत अधिक शराब पीने से हुई थी। शराब उन्होंने जानबूझकर ज्यादा पी या अनजाने में यह कोई नहीं जानता। हां, यह जरूर है कि इस दिन हिंदी सिनेमा ने एक महान फिल्मकार को सिर्फ इसलिए खो दिया, क्योंकि वह अपनी सफलताओं और असफलताओं को संभाल नहीं सका।



निर्देशक, निर्माता, स्क्रिप्ट राइटर, सिनेमेटोग्राफर और एक्टर भी थे गुरु दत्त। फाइल

46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है अमेरिका में सिएटल और पोर्टलैंड जैसे शहरों में पारा। बुधवार को फ्लोरिडा, जार्जिया, कैरोलिना और मैसाचुसेट्स में तूफान आया।

गूगल पर 36 अमेरिकी राज्यों ने ठोका मुकदमा

एप स्टोर की फीस को लेकर एंडरायड एप कंपनियों की शिकायत

न्यूयॉर्क टाइम्स से

गूगल पर आरोप, मोबाइल एप स्टोर का दुरुपयोग कर बाजार शक्ति में किया इजाफा

वाशिंगटन : इंटरनेट सर्च इंजन गूगल के खिलाफ अमेरिका के 36 राज्यों और जिले कोलंबिया ने संघीय अदालत में मुकदमा दर्ज किया है। गूगल पर आरोप है कि उसने अपने मोबाइल एप स्टोर का दुरुपयोग करते हुए अपने बाजार की शक्ति को बढ़ाया है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कड़े नियम-शर्तों के तहत गूगल की मनमानियों के कारण कानूनी चुनौतियों का शिकार हो रहे हैं।

गूगल के खिलाफ अक्टूबर के बाद से अब तक संघीय अदालत में 'कंपनियों का सामान ऊंचे दामों में बेचने के अविश्वास कानून' के तहत यह चौथा मुकदमा है। हालांकि इससे पहले, कंपनी के बेहद



गूगल की बढ़ेगी मुश्किलें। फाइल फोटो

कमाऊ एप स्टोर को लेकर उटा, नार्थ कैरोलीना, न्यूयार्क और टेनेसी के नेतृत्व में कैलीफोर्निया के उत्तरी जिले में स्थित एक संघीय अदालत में केस दर्ज हुआ है।

गूगल के खिलाफ इस मामले को लाने वाले मोबाइल एप के डेवलपर्स का कहना है कि यह अमेरिकी कंपनी अपनी ही प्रणाली के जरिये उनके उत्पादों को लेकर कुछ रकम वसूलती है। गूगल की यह प्रणाली कई ट्रांजैक्शन होने पर उसका करीब तीस फीसद शुल्क लेती है। इसके चलते डेवलपर्स को भी अपने सेवाएं ऊंचे दामों में देनी पड़ती हैं। इस मुकदमे में इन सब चिंताओं का जिक्र करते हुए कहा गया कि गूगल ने अपने एंडरायड स्मार्ट आपरेटिंग सिस्टम में मोबाइल एप्स के वितरण पर उसके पूरा नियंत्रण होने की शिकायत की है। अमेरिकी कंपनी के इसी प्रतिस्पर्द्धा रोधी बर्ताव के कारण गूगल प्ले स्टोर मार्केट शेयर 90 फीसद से अधिक हो गया है। उसे किसी से कोई खतरा नहीं है और बाजार में उसकी अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धा है।

हालांकि गूगल ने इस मुकदमे को निराधार बताते हुए कहा कि अटर्नी जनरल ने प्रतिपक्षी एप्पल स्टोर पर नहीं बल्कि उसके प्ले स्टोर पर प्रहार किया है। गूगल की पब्लिक पालिसी के सीनियर डायरेक्टर विलियम व्हाइट ने कहा कि यह मुकदमा किसी छोटे लड़के को बचाने या उपभोक्ता के संरक्षण के लिए नहीं है। यह कुछ प्रमुख एप डेवलपर्स के बारे में है, जो गूगल प्ले का लाभ बिना कोई कीमत चुकाए उठाना चाहते हैं।

'उइगर नरसंहार के विरोध में ब्रिटेन बीजिंग खेलों का बहिष्कार करे'

लंदन, एपी : ब्रिटेन में संसद सदस्यों के एक प्रभावशाली ग्रुप ने सरकार से अपील की है कि वह उइगर मुस्लिमों के नरसंहार को रोकने के लिए चीन पर दबाव बनाए। ब्रिटेन को 2022 में बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक का भी बहिष्कार करना चाहिए।

संसद की विदेशी मामलों की समिति के प्रमुख व कंजरवेटिव पार्टी के संसद सदस्य टोम टगेनधट ने कहा है कि चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगरों का नरसंहार ऐसा शर्मनाक कृत्य है, जिस पर विश्व के सभी देशों को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए और चीन पर दबाव बनाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अप्रैल माह में संसद में सदस्यों ने उइगर नरसंहार पर जो निर्णय लिए थे, उन पर अमल किया जाना चाहिए। चीन की सरकार को इसके लिए जवाबदेह बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन का पांच हजार साल का सभ्य संस्कृति का इतिहास है। इस इतिहास पर उइगर व अन्य अल्पसंख्यकों का नरसंहार काला धब्बा है। यह अहसास चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को उसके सौ साल पूरा होने पर कराया जाना चाहिए। संसद सदस्यों की समिति ने कहा है कि ब्रिटेन को फरवरी 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों का राजनीतिक रूप से बहिष्कार करना चाहिए।

अफगान सुरक्षा बलों ने बादगीस की राजधानी से आतंकियों को खदेड़ा

काबुल, एएनआइ : अफगानिस्तान में सुरक्षा बलों ने बादगीस प्रांत की राजधानी काला-ए-नव को फिर कब्जे में ले लिया है। सुरक्षाकर्मियों ने कार्रवाई के दौरान 69 आतंकियों को मार गिराया, जबकि 23 घायल हो गए। प्रांतीय राजधानी को दोबारा नियंत्रण में लेने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरी ताकत लगा दी। इस सैन्य अभियान में हवाई हमले भी किए गए। बुधवार को काला-ए-नव पर तालिबानी आतंकियों ने कब्जा कर लिया था।

रायटर के मुताबिक, रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता फवाद अहमद ने कहा,अब काला-ए-नव पर हमारा पूरा नियंत्रण है। तालिबान से भारी मात्रा में गोला-बारूद भी मिला है। सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, तालिबान अब तक सौ जिलों पर कब्जा कर चुके हैं।

अमेरिका अफगानिस्तान की कमजोर महिलाओं को वीजा दे : एएनआइ के अनुसार अधिकार कार्यकर्ताओं ने अमेरिका से मांग की है कि वह सेना वापसी के बाद कमजोर पड़ रही महिलाओं और अमेरिकी सेना के साथ काम करने वाले लोगों को प्राथमिकता के आधार पर वीजा जारी करे। यहां तमाम महिला पत्रकार, अधिकार कार्यकर्ता और राजनेता हैं, जो तालिबान की हिट लिस्ट में हैं।

- संघर्ष में 69 तालिबानी आतंकी मारे गए
- पूरी ताकत झोंकने के बाद दोबारा हासिल किया शहर


जलालाबाद-काबुल हाईवे पर स्थित चेक प्वाइंट पर मुस्तैदी से तैनात अफगान नेशनल आर्मी का जवान। रायटर

अफगानिस्तान पर नीति की जानकारी देंगे बाइडन : प्रेट्र के अनुसार व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने पत्रकारों को बताया कि राष्ट्रपति जो बाइडन जल्द ही अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति और भावी नीति पर बात करेंगे। इससे पहले वह सुरक्षा अधिकारियों से ताजा हालात के बारे में जानकारी लेंगे।

तालिबान के हमले अफगान जनता के मानवाधिकारों का हनन : एएनआइ के अनुसार काबुल स्थित अमेरिकी दूतावास के उप राजदूत रास विल्सन ने कहा है कि तालिबान अफगान नागरिकों पर हमले करके उनके मानवाधिकारों का हनन कर रहा है।

ब्रिटेन के सभी सैनिक वापस लौटे : बोरिस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जानसन ने कहा है कि उनकी अधिकांश सेना ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है, लेकिन वहां के प्रति हमारी प्रतिबद्धता बनी रहेगी। ब्रिटेन के चीफ आफ द डिफेंस स्टाफ निक कार्टर ने आगाह किया है कि अफगानिस्तान में सेना वापसी के बाद गृहयुद्ध हो सकता है।

शिनजियांग पर चीन की चिंता बढ़ी : अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के साथ ही चीन की शिनजियांग को लेकर चिंता बढ़ गई है। अफगानिस्तान में उइगर मुस्लिमों का संगठन ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट भी सक्रिय है। चीन को आशंका है कि इस संगठन की शिनजियांग में गतिविधि बढ़ सकती है।

ताइवान ने चीनी युद्धक विमानों को खदेड़ा

ताइपे, एएनआइ : चीन के युद्धक जेट विमान ने एक बार फिर से ताइवान की वायु सीमा में घुसकर अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। चीन के ये लड़ाकू विमान ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन (एडीआइजेड) में बुधवार की सुबह घुसे थे। ताइवान में चीन के फाइटर जेट की घुसपैठ की इस माह चौथी घटना है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी (पीएलए) की वायुसेना के शांग्जी वाई-8 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्लेन दक्षिण पश्चिम से ताइवान के एडीआइजेड में घुसे थे।

इसके जवाब में ताइवान ने इसको लेकर रेडियो वार्निंग दी और अपने विमानों को चीन के लड़ाकू विमानों को खदेड़ने के लिए भेजा। चीन के लड़ाकू विमानों की ताइवान के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने ट्रैक किया था। इससे पहले चीन के विमानों ने इस तरह की हरकत दो, तीन और चार जुलाई को भी की थी। ताइवान के मुताबिक इन विमानों ने काफी कम गति में उड़ान भरी थी।

गौरतलब है कि पिछले वर्ष सितंबर के मध्य में अपनी ग्रे जोन नीति के तहत


चीन ने एक माह में चौथी बार भेजा ताइवान के एयर स्पेस में लड़ाकू विमान
चीनी विमानों की हरकत। फाइल

ताइवान के एडीआइजेड में लगातार विमानों को भेजने की कवायद शुरू की है। ये जोन ताइवान के दक्षिण-पश्चिम में है। ज्यादातर इसके लिए एक से तीन धीमी गति से उड़ने वाले टर्बोप्रॉप विमानों का इस्तेमाल किया गया है। ताइवान ने चीन के इस दुस्साहस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

ताइवान का कहना है कि चीन की ये कवायद गैरजरूरी है जिस पर उसको दोबारा विचार करने की जरूरत है। दरअसल, चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानकर उस पर अपना अधिकार जताता आया है। चीन की मुख्य भूमि से अलग ताइवान में करीब ढाई करोड़ लोग रहते हैं। बीते सात दशकों से ही ताइवान एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह अपना काम कर रहा है। वो चीन के अधिकार को गलत बताते हुए खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानता है।

भारत के खिलाफ दुष्प्रचार बंद करे पाक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कई दशकों से आतंकवाद को बतौर सरकारी नीति बढ़ावा दे रहा पाकिस्तान अब भारत पर अपने यहां आतंकी वारदातों को अंजाम देने का आरोप लगा रहा है। पाकिस्तान के आरोपों को भारत ने पूरी तरह से आधारहीन करार देते हुए उसे सलाह दी है वह दुष्प्रचार बंद करे और अपने घर के भीतर ध्यान दे। भारत ने यह भी कहा है कि अंतरराष्ट्रीय बिरादरी इस बात से पूरी तरह से वाकिफ है कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का का कैसा रवैया रहा है। दो दिन पहले ही पाकिस्तान सरकार की तरफ से प्रेस वार्ता करके लाहौर में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से नामित आतंकी हाफिज सईद के घर के पास किए गए धमाके को लेकर भारत पर टिप्पणी की गई है। वहां के पीएम इमरान खान और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी ये गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था कि भारत के खिलाफ आधारहीन टिप्पणी करना पाकिस्तान के लिए नया नहीं है। पाकिस्तान अच्छा करेगा अगर वह अपने घर के भीतर सुरक्षित तौर से रह रहे आतंकियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को

- हाफिज सईद के घर के पास किए गए धमाके को लेकर पाक ने की भारत पर टिप्पणी
- बागची ने कहा, अपने यहां रह रहे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करे पाक


अरिंदम बागची बोले, पाकिस्तान अपने घर के भीतर सुरक्षित तौर से रह रहे आतंकियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे। फाइल फोटो

भी आतंकवाद पर पाकिस्तान की साख के बारे में अच्छी तरह से पता है। पाकिस्तान के नेताओं ने स्वयं ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकी को शहीद बता कर उसका गुणगान किया है।

पाकिस्तान के रवैये को लेकर भारत ने इस्लामिक देशों के संगठन (ओआइसी) को भी आगाह किया है। विगत पांच जुलाई को सऊदी अरब में भारत के राजदूत ने ओआइसी के महासचिव से मुलाकात की थी। बैठक में कई मुद्दों पर बात हुई। भारत ने खास तौर पर आग्रह किया कि भारत को लेकर इस संगठन में अनावश्यक तौर पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए और संगठन को किसी खास देश के दुष्प्रचार को लेकर कदम नहीं उठाना चाहिए। सनद रहे कि पाकिस्तान लगातार ओआइसी में कश्मीर का मुद्दा उठाता रहता है। ओआइसी की तरफ से हाल ही में एक बयान जारी किया था, जिसमें भारत व पाकिस्तान से मिल-जुल कर कश्मीर मुद्दे का समाधान करने का आग्रह किया गया था। इसके साथ ही भारत से अनुरोध किया गया था कि वह ओआइसी की एक टीम को कश्मीर जाने की इजाजत दे।

बागची ने कहा है कि ओआइसी के महासचिव के साथ भारतीय राजदूत ने कई मुद्दों पर बात की है। हमने ओआइसी की कुछ गलतफहमियों को भी दूर करने की कोशिश की है। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर बागची ने कहा कि अधिकांश गलतफहमियां कुछ देशों की तरफ से पैदा की गई हैं। ओआइसी को इन देशों के निजी एजेंडे पर ध्यान रखना चाहिए, ताकि स्वार्थ आधारित दुष्प्रचार से इस संगठन को बचाया जा सके। ओआइसी को यह भी सलाह दी गई है कि भारत विरोधी दुष्प्रचार के आधार पर उसे देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए।

भारत-इटली में आपसी रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति

नई दिल्ली, प्रेट्र : सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने गुरुवार को रोम में इटली के अपने समकक्ष लेफ्टिनेंट जनरल पिएट्रो सेरिनो और रक्षा मंत्री लोरेंजो गुएरिनी से मुलाकात कर द्विपक्षीय रक्षा संबंधों पर महत्वपूर्ण चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी रक्षा संबंध मजबूत करने और दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने सहमति जताई। जनरल नरवणे बुधवार को दो दिन की यात्रा पर रोम पहुंचे हैं। इससे पहले वह ब्रिटेन में थे।

भारतीय सेना ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि लेफ्टिनेंट जनरल सेरिनो के साथ मुलाकात में दोनों सेना प्रमुख ने संयुक्त सैन्य अभ्यास समेत कई मसलों पर चर्चा की। सहमति बनी है कि दोनों देशों की सेनाएं कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगी। जनरल नरवणे ने इटली के कैसीनो शहर में भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए स्मारक का भी उद्घाटन किया। यह स्मारक द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया है। शहीद भारतीय सैनिक ब्रिटिश सेना की ओर से युद्ध में लड़े थे। बदले में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने भारत को आजाद करने का आश्वासन दिया था।

जनरल नरवणे की यह यात्रा नवंबर, 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने इतालवी समकक्ष गियूसेप कोंटे के साथ हुई वर्चुअल मीटिंग में रक्षा सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति के बाद हुई है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने रक्षा सहयोग और रक्षा तकनीक सहयोग के साथ ही हथियारों के साथ मिलकर विकास और उत्पादन तक पर बात की थी। भारतीय सेनाओं के लिए हथियार और अन्य उपकरणों की खरीद के लिए इटली विश्वसनीय ठिकाना रहा है। जनरल नरवणे की यात्रा से पहले भारतीय नौसेना के युद्धपोत आइएनएस तबर और इटली के युद्धपोत आईटीएस एंटोनियो मार्सेग्लिया ने टिरहेनियन सागर में संयुक्त अभ्यास किया था। चार और पांच जुलाई को हुए इस नौसैनिक अभ्यास में दोनों नौसेनाओं ने रात और दिन में मिलकर तीसरे देश की नौसेना से मुकाबला करना वाला अभियान चलाया था।


मोदी और कोंटे के बीच बनी सहमति को जमीन पर उतारने को जनरल नरवणे पहुंचे रोम
एमएम नरवणे। फाइल

श्रीलंका में राजपक्षे परिवार के सातवें सदस्य भी सरकार में शामिल

कोलंबो, प्रेट्र : श्रीलंका की सरकार में राजपक्षे परिवार का पूरी तरह दबदबा हो गया है। राजपक्षे परिवार के सबसे छोटे भाई बेसिल राजपक्षे भी सरकार में शामिल हो गए हैं। उन्हें श्रीलंका का वित्तमंत्री बनाया गया है। अब तक इस परिवार में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित सात सदस्य सरकार में शामिल हो चुके हैं।

बेसिल राजपक्षे (70) परिवार में सबसे छोटे भाई हैं। तीन भाई राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे (72), प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे (75), कृषि मंत्री चमल राजपक्षे (78) पहले से ही पदों पर बने हुए हैं। महिंदा के बड़े बेटे नमल खेल मंत्री हैं। चमल के बेटे शशिंद्र राज्य मंत्री हैं। चारों राजपक्षे भाइयों के एक भतीजे निपुण रणवाका भी सरकार में ही कामकाज देख रहे हैं। अमेरिका और श्रीलंका के दोहरे नागरिक बेसल ने गोटाबाया राजपक्षे के अधीन आर्थिक कार्यों के साथ ही पर्यावरण संबंधी कामकाज भी देखा है। वित्त मंत्रालय अब तक प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के पास था। महिंदा अब आर्थिक नीति और योजना कार्यान्वयन का नया विभाग देखेंगे।

रूस के साथ भारत के रिश्ते सबसे दृढ़ लेकिन चीन को लेकर चिंता

मॉस्को, प्रेट्र : भारत रूस के साथ अपने रिश्तों की गर्माहट को भूला नहीं है लेकिन हाल के सीमा विवाद के चलते चीन के साथ उसके रिश्तों में खटास आ गई है। भारत-रूस के रिश्ते द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की सबसे स्थिर और दृढ़ साझेदारियों में से एक हैं। भारत वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए जल्द होने वाली राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा में व्यापक संभावनाएं देख रहा है। इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश संबंधों के लिए नई ऊंचाई तय कर सकते हैं। यह बात भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रिमाकोव इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के कार्यक्रम में कही है।

जयशंकर ने कहा, रूस के अमेरिका, यूरोप, चीन, जापान, तुर्की और इराक आदि के साथ संबंधों में उतार-चढ़ाव आए लेकिन भारत के साथ उसके रिश्ते कभी नहीं बदले। समय-समय पर ऐसे कई


जयशंकर ने कहा, चीन की हरकतों से हमारे संबंधों की नींव हिली
एस जयशंकर। फाइल

घटनाक्रम हुए जिनसे दोनों देशों के संबंधों का पोषण हुआ और वे पहले से ज्यादा मजबूत हुए। विदेश मंत्री ने कहा, दोनों देशों के संबंधों में कई तरह के बदलाव आए। कई तरह की अंदरूनी और बाहरी परिस्थितियां बदलीं लेकिन दोनों देशों के संबंध आज भी सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। दोनों देशों का सहयोग ऐसी सच्चाई है जिसमें अपवाद स्वरूप शायद ही कोई असहमति पैदा हुई हो। इसी के परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2014 से अभी तक 19 बार मिल चुके हैं। मोदी इतनी बार अन्य किसी विदेशी नेता से नहीं मिले।

चीन सीमा समझौता मानने को तैयार नहीं : जयशंकर ने कहा, पिछले एक वर्ष में सीमा समझौते को लेकर चीन ने जिस तरह का व्यवहार दिखाया है, उससे भारत-चीन के संबंधों में तमाम चिंताएं पैदा हो गई हैं। बीते 40 वर्षों में दोनों देशों के संबंध बहुत स्थिर रहे। इसी के चलते चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझीदार बना। लेकिन चीन अब भारत के साथ हुआ सीमा समझौता मानने के लिए तैयार नहीं है। इससे हमारे संबंधों की नींव हिली है। 45 साल के बाद सीमा पर हुई घटना में जानें गई हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता उससे जुड़े देशों के रिश्तों की असलियत बयां करती हैं। जबकि बीते एक साल में भारत और चीन के रिश्तों का बुनियादी ढांचा ही कमजोर पड़ गया है। जयशंकर ने चीन को लेकर ये बातें पूर्वी लद्दाख में एक साल से ज्यादा समय से चल रहे भू विवाद के मद्देनजर कही हैं।

संजय भंडारी के प्रत्यर्पण पर फरवरी में सुनवाई करेगी ब्रिटिश अदालत

लंदन, प्रेट्र : मनी लांड्रिंग और कर चोरी के आरोपों में भारत में वांछित आरोपित आर्म्स डीलर संजय भंडारी के प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई कर रही ब्रिटेन की एक अदालत ने गुरुवार को मामले में आगे की सुनवाई फरवरी, 2022 में करने का फैसला किया।

डिस्ट्रिक्ट जज माइकल स्नो ने भंडारी के प्रत्यर्पण के लिए भारतीय अधिकारियों से प्राप्त दो अनुरोधों से संबंधित मामले में सुनवाई की। एक मामला मनी लांड्रिंग और दूसरा कर चोरी से जुड़ा है। लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत में मौजूद 59 वर्षीय भंडारी ने केवल अपने नाम की पुष्टि की और कहा कि उसकी भारत प्रत्यर्पित किए जाने में सहमति नहीं है। वह अगले साल प्रत्यर्पण पर होने वाली सुनवाई तक सशर्त जमानत पर रहेगा। गुरुवार को अदालत ने जमानत शर्तों में कुछ ढील देने पर भी सहमति व्यक्त की। सुनवाई की तारीखें अगले साल 21 फरवरी से नौ मार्च के बीच तय करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है जिसमें बड़ी संख्या में दस्तावेजों को हासिल करने में समय लगेगा।

- कोर्ट ने आर्म्स डीलर को दी जमानत शर्तों में ढील
- भंडारी दुनियाभर में अपनी संपत्तियों की भारतीय कर अधिकारियों के समक्ष घोषणा नहीं करने का भी आरोपित है


मनी लांड्रिंग में फंसे हैं संजय भंडारी। फाइल

भारतीय अधिकारियों की ओर से अदालत में पेश क्राउन प्रासिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने आरोपित कारोबारी भंडारी के खिलाफ आरोपों का जिक्र किया। मनी लांड्रिंग के अलावा भंडारी दुनियाभर में अपनी संपत्तियों की भारतीय कर अधिकारियों के समक्ष घोषणा नहीं करने का भी आरोपित है। सीपीएस के वकील बेन लेलायड ने कहा कि उसने विदेश में अपनी उन संपत्तियों की स्वेच्छा से घोषणा नहीं की जो भारत में कर योग्य हैं।

जुमा ने सजा के लिए खुद को दक्षिण अफ्रीकी प्रशासन के हवाले किया

जोहानिसबर्ग, प्रेट्र : दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा ने खुद को 15 महीने की सजा भुगतने के लिए, अंततः प्रशासन के हवाले कर दिया है। इसी के साथ उनके सशस्त्र समर्थकों और पुलिस के बीच तनाव खत्म हो गया है।

गत बुधवार को मध्यरात्रि की समय सीमा खत्म होने से पहले जुमा ने खुद को दक्षिण अफ्रीका की पुलिस के हवाले कर दिया जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें भ्रष्टाचार की एक जांच में अदालत की अवमानना का दोषी पाए जाने पर 15 महीने की कैद की सजा सुनाई थी।

वर्ष 2009 से 2018 के बीच उनके शासनकाल में उनकी सरकार को भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त पाया गया था, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा का कहना था कि उनके साथ मनमाना बर्ताव किया गया है और वह सजा के हकदार नहीं हैं। इसीलिए, उन्होंने अपनी सजा के खिलाफ कोर्ट में भी अपील की थी जिसे वह बाद में हार गए हैं।

अमेरिका में भीषण गर्मी, ओरेगन में 116 की मौत

पोर्टलैंड, एपी : अमेरिका में गर्मी का भीषण प्रकोप और जबर्दस्त लू चल रही है। कुछ क्षेत्रों में तूफान ने तबाही मचाई हुई है। ओरेगन में गर्मी के कारण पिछले एक सप्ताह में 116 लोगों की मौत हो गई। फ्लोरिडा में तूफान एल्सा से नुकसान हुआ, जगह-जगह पेड़ गिर गए। वाहनों के भी तूफान की चपेट में आने की जानकारी मिली है।

अमेरिका के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पिछले कई दिनों से झुलसाने वाली गर्मी का दौर चल रहा है। यहां पर लू चल रही है और स्थानीय निवासी परेशान हैं। ओरेगन में मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले एक सप्ताह में यहां 116 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 37 से 97 वर्ष की उम्र के लोग हैं।

ओरेगन की गवर्नर केट ब्राउन ने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि

- फ्लोरिडा और आसपास के क्षेत्रों में तूफान का कहर

गर्मी से कम से कम नुकसान हो और लोगों की जान बचाई जा सके। उल्लेखनीय है कि कनाडा और अमेरिका के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में गर्मी के कारण हालत खराब हैं।

कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में तो गर्मी से मरने वालों की संख्या सैकड़ों में पहुंच चुकी है। अमेरिका में सिएटल और पोर्टलैंड जैसे शहरों में पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बुधवार को फ्लोरिडा, जार्जिया, कैरोलिना और मैसाचुसेट्स में तूफान आया। इस तूफान में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दर्जनों लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। तूफान एल्सा के कारण जगह-जगह पेड़ों के गिरने की जानकारी है। रास्ते में जो वाहन गिरने वाले पेड़ों की चपेट में आए, उनमें भी नुकसान हुआ है।

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का गिलगिट-बाल्टिस्तान पर बुरा असर

इस्लामाबाद, एएनआइ : चीन के 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' की महत्वाकांक्षी व्यापारिक सड़क योजना को अगर पूरा कर लिया तो उसके भूराजनीतिक स्थिति और आर्थिक हितों का असर दक्षिण-पूर्वी एशियाई तटीय देशों के ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग और यूरेशिया की मुख्य भूमि समेत हिंद महासागर के अधिकांश हिस्से में पड़ेगा। टाइम्स आफ इजरायल में सेंटर फार पालिटिकल एंड फॉरेन अफेयर (सीपीएफए) के अध्यक्ष फेबियन बुसार्ट ने कहा कि चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) और खासतौर पर ग्वादर बंदरगाह चीन की भूमिका को अत्यधिक बढ़ा देगा। खासकर जब उसने अफगानिस्तान, मध्य एशियाई देशों से कारोबार करना शुरू कर दिया है।

सीपीईसी की इस परियोजना को वर्ष 2015 से शुरू किया जा रहा है। इसका संबंध चीन के पश्चिमी प्रांत शिनजियांग

- इजरायली मीडिया में चीनी महत्वाकांक्षा का जिक्र


चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा चीन की भूमिका को अत्यधिक बढ़ा देगा। फाइल

(काशगर) और पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान के ग्वादर क्षेत्र में है। बीआरआइ के तहत चीन को 150 से अधिक देशों से सड़कों के संजाल, रेलवे और समुद्र मार्ग से जोड़ने की कोशिश है। इस परियोजना की लागत 1.3 अरब डालर आएगी। विश्लेषकों का कहना है कि सीपीईसी के कुछ मौजूदा मुद्दों पर कुछ गंभीर चुनौतियां हैं।

बुसार्ट का कहना है कि सीपेक के जरिये चीन सीधे तौर पर भारतीय उप महाद्वीप में दखल देगा। सीपेक पूरा होने पर चीन को अरब सागर में सीधा रास्ता मिलेगा और दूसरी ओर अफगानिस्तान तक उसकी सीधी पहुंच होगी। इससे वह अहम ऊर्जा आयात के लिए खनिजों के मार्ग में वैकल्पिक रास्ता बना लेगा और राजनीतिक रूप से अहम अफगानिस्तान में भी संध लगा लेगा। उन्होंने लेख में लिखा है कि पाकिस्तानी साझेदारों में वह असंतुलित तरीके से आर्थिक विकास करेगा। चीन की सत्ता और संसाधनों की भूख ने उसे गिलगिट-बाल्टिस्तान क्षेत्र में भी प्रभाव बनाने में कामयाबी दी है। इसमें सबसे दुखद बात यह है कि वहां अपने फायदे के लिए उसने पर्यावरण और स्थानीय लोगों के जीवनयापन के साधनों को भी तबाह कर दिया है।

हैती में राष्ट्रपति की हत्या में शामिल चार संदिग्ध ढेर

पोर्ट-ओ-प्रिंस, रायटर : हैती में राष्ट्रपति जोवेनल मौसे की उनके आवास में घुसकर हत्या और प्रथम महिला को गंभीर रूप से घायल करने की घटना में शामिल चार संदिग्ध को पुलिस ने गोली से उड़ा दिया। घटना में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है।

हैती के पुलिस महानिदेशक लियोन चार्ल्स ने स्थानीय टीवी में बताया कि राष्ट्रपति की हत्या के बाद हमने इन भाड़े के हत्यारों का रास्ता रोक लिया था और चार हमलावर मुठभेड़ में मारे गए। उन्होंने कहा कि हत्या में शामिल सभी लोग पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे।

हमले में राष्ट्रपति की पत्नी मार्टिन मौसे भी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। इनका फ्लोरिडा के अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। अमेरिका में हैती के राजदूत बोचिट एडमंड ने बताया कि बंदूकधारी नकाब में थे और वे अमेरिका के ड्रग प्रवर्तन


हमले में शामिल दो लोगों को हिरासत में लेकर की जा रही पूछताछ
जोवेनल मौसे। फाइल

अधिकारी बनकर आवास में दाखिल हुए थे। सरकार ने दो सप्ताह के लिए इमरजेंसी घोषित कर दी है। हत्या के बाद राजधानी में दुकानें और बाजार बंद रहे। अंतरिम प्रधानमंत्री क्लाउड जोसेफ ने बताया कि ये भाड़े के हत्यारे थे और अच्छी तरह प्रशिक्षित थे। हत्यारे अंग्रेजी और स्पेनिश भाषा बोल रहे थे, जबकि हैती में फ्रेंच और क्रियोल भाषा बोली जाती है।

इस घटना की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कड़ी आलोचना की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जानसन पहले ही हत्या की बर्बर बताते हुए कड़ी निंदा कर चुके हैं।

इंग्लैंड के लिए 55 साल बाद खुला फाइनल का दरवाजा

केन के पेनाल्टी पर गोल की मदद से इंग्लैंड ने डेनमार्क को हराया, खिताबी भिड़ंत में इटली से होगा सामना

लंदन, एपी : पिछले 55 साल में पहली बार किसी बड़े खिताब का इंतजार कर रहे इंग्लैंड ने बुधवार देर रात को डेनमार्क को हराकर यूरो कप फुटबाल के फाइनल में प्रवेश कर लिया, जहां उसका सामना रविवार को इटली से होगा। एक गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए इंग्लैंड ने 2-1 से जीत दर्ज की। इस जीत के नायक उसके कप्तान हैरी केन रहे, जिन्होंने 104वें मिनट में पेनाल्टी बचा लिए जाने के बाद रिबाउंड शाट पर विजयी गोल दागा। इंग्लैंड को यह स्पाट किक रहीम स्टर्लिंग को पेनाल्टी एरिया में गिराए जाने के बाद मिली थी।

इंग्लैंड की मिटेगी कसक : विश्व कप 1966 के बाद इंग्लैंड का यह पहला फाइनल है। इंग्लैंड की झोली में एकमात्र खिताब 1966 विश्व कप ही है। पिछले 55 साल में इंग्लैंड विश्व कप या यूरो चैंपियनशिप में चार बार सेमीफाइनल हार चुका है। यह जीत उसके सारे मलाल और कसक मिटाने वाली साबित हो सकती है। उनमें से तीन 1990, 1996, 2018 उसने पेनाल्टी शूट आउट में गंवाए थे।

नहीं दे पाए खिताबी तोहफा : टूर्नामेंट के पहले ही मैच में क्रिस्टियन एरिक्सन के मैदान पर गिरने के बाद से डेनमार्क के खिलाड़ियों ने उनके लिए खिताब जीतने का लक्ष्य रखा था। मैच दर मैच उनके प्रदर्शन में निखार आता गया, लेकिन यह सेमीफाइनल में थम गया।

पहला हाफ 1-1 से बराबर : मेहमान टीम को फ्री किक मिली जिस पर मिकेल डैंसगार्ड ने 30वें मिनट में गोल करके टीम को 1-0 से आगे कर दिया। फिर आठ मिनट बाद ही इंग्लैंड के स्टर्लिंग को बाक्स के अंदर से एक अच्छा पास मिला और उन्होंने पहली बार गोल पोस्ट पर गेंद को भेजा, लेकिन डेनमार्क के गोलकीपर ने गोल होने नहीं दिया। फिर अगले मिनट में डेनमार्क के कप्तान सिमोन कजेर की एक गलती के कारण इंग्लैंड ने मैच में वापसी कर ली। इंग्लिश मिडफील्डर ने गेंद स्टर्लिंग की तरफ गेंद भेजी, लेकिन, डेनमार्क के कप्तान तेजी से गेंद पर आ गए और गेंद उनके शरीर से लगकर पोस्ट में चली गई और स्कोर 1-1 से बराबर रहा।

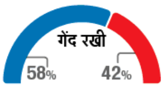
अतिरिक्त समय में गया मैच : दूसरे हाफ में इंग्लैंड और भी आक्रामक होकर खेला। 55वें मिनट में हैरी मैगुएर के पास इंग्लैंड को बढ़त दिलाने का मौका था, जब फ्री किक पर पेनाल्टी एरिया की तरफ से उन्होंने हेडर से गेंद गोल पोस्ट की तरफ भेजी, लेकिन डेनमार्क के डिफेंडर कास्पेर ने उनके प्रयास को नाकाम कर दिया। फिर 74वें मिनट में केन बाक्स के अंदर डेनमार्क के डेनियल वास के साथ टकराकर गिर गए और फिर रेफरी ने वास को यलो कार्ड दिखाया। लेकिन, इंग्लैंड ने पेनाल्टी की मांग की और वार की मदद से चेक करने के बाद उन्हें पेनाल्टी नहीं मिली। इस हाफ में भी दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर पाईं और मैच अतिरिक्त समय में गया। अतिरिक्त समय में स्टर्लिंग के डेनमार्क के खिलाड़ियों के साथ गिरने के कारण इंग्लैंड ने पेनाल्टी की मांग की और रेफरी ने वार की मदद से मेजबान टीम को पेनाल्टी दी। 104वें मिनट में पेनाल्टी पर गोल करने केन आए और उन्होंने दायें पैर से गेंद पोस्ट की ओर भेजी और गोलकीपर कास्पेर ने बायीं ओर कूदकर गेंद को पकड़ लिया, लेकिन केन ने तेजी से जाकर रिबाउंड किक लगाई और टीम का दूसरा गोल दाग दिया। अतिरिक्त समय के दूसरे हाफ में डेनमार्क को 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा जब यानसेन चोट के कारण बाहर हो गए। उस समय तक डेनमार्क सभी स्थानापन्न खिलाड़ियों का इस्तेमाल कर चुका था। इसके बाद डेनमार्क ने मैच को बराबर करके पेनाल्टी शूट आउट में ले जाने की कोशिश की, लेकिन वह गोल नहीं दाग पाए।

लाइट मामले में इंग्लैंड के खिलाफ होगी जांच

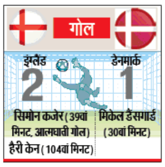


डेनमार्क के गोलकीपर कास्पेर के चहरे पर चमकती लेजर लाइट • ट्विटर

यूरो कप की संचालन यूएफा ने इंग्लैंड के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच का आदेश दिया गया गया। डेनमार्क के खिलाफ मैच के दौरान हैरी केन पेनाल्टी पर किक लेने आए थे और उस दौरान डेनमार्क के गोलकीपर कास्पेर श्माइकल को इंग्लिश प्रशंसक ने उनके चेहरे पर पेन वाली हरे रंग की लेजर लाइट दिखाई थी जिसके बाद यूएफा ने जांच का आदेश दिया। इसके अलावा मैच से पहले डेनमार्क के राष्ट्रीय गान के बजने के दौरान भी वेंबले स्टेडियम में हूटिंग कर रहे थे। इससे पहले इंग्लैंड और जर्मनी के अंतिम-16 के मैच में इंग्लिश प्रशंसकों ने जर्मनी के राष्ट्रीय गान बजने पर हूटिंग की थी।



इंग्लैंड		डेनमार्क
33	फ्री किक	14
06	कार्नर किर	05
02	गोलकीपर बचाव	08
01	यलो कार्ड	01
759	कुल पास	543





1992 में यूरो कप का खिताब जीतने वाली डेनमार्क की टीम इसके बाद से पहली बार किसी भी बड़े टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची थी

> मुझे अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। यह शानदार पल है। प्रशंसकों ने हमारा हमेशा साथ दिया है। अब हम फाइनल में है। इटली मजबूत टीम है। वह पिछले कुछ समय से शानदार प्रदर्शन करती आ रही है। मुझे फिर से रोचक मुकाबले की उम्मीद है।
> **गेरेथ साउथगेट**, कोच, इंग्लैंड

मैच जीतने के बाद खुशी से उत्साहित हैरी केन • एएफपी

पेनाल्टी पर नाखुश डेनमार्क की टीम

इंग्लैंड को पेनाल्टी रहीम स्टर्लिंग को डेनिश खिलाड़ियों द्वारा पेनाल्टी एरिया में गिराए जाने के बाद मिली थी। डेनमार्क के मैथियास जेंसेन की कोहनी लगने के बाद स्टर्लिंग मैदान पर गिर पड़े थे। रेफरी ने पेनाल्टी स्पाट की तरफ इशारा किया और वीडियो एसिस्टेंट रेफरी (वार) की मदद से इंग्लैंड को पेनाल्टी दी गई और केन ने इस पर रिबाउंड पर गोल कर दिया। डेनमार्क के कोच कास्पर हजुलमंद ने कहा कि वह नहीं समझ पा रहे हैं कि इतने महत्वपूर्ण मौके पर इतना बड़ा फैसला कैसे लिया गया। उन्होंने कहा, 'आप ऐसे निर्णय को नहीं दे सकते जिसका खेल पर इतना प्रभाव पड़ता है। मैं इसे पेनाल्टी के रूप में नहीं देखता। एक चीज यह है कि हम मैच हार गए और यह निराशाजनक है। खिलाड़ी भी पेनाल्टी दिए जाने पर खुश नहीं है।' वहीं, इंग्लैंड के कोच गेरेथ साउथगेट ने कहा, 'यह वार के जरिये फैसला दिया गया है। उन्होंने इसे चेक किया है और रेफरी के फैसले पर कायम रहना चाहिए।' पेनाल्टी पर भले डेनमार्क खुश नहीं हो, लेकिन रेफरी के फैसलों की इस टूर्नामेंट में प्रशंसा की गई है।

बार्टी और प्लिस्कोवा के बीच होगा खिताबी मुकाबला

टेनिस डायरी

लंदन, एपी : एश्ले बार्टी के लिए अपने पहले विंबलडन के फाइनल तक पहुंचना आसान नहीं रहा है क्योंकि उन्होंने पिछले महीने अपने कूल्हे के चोटिल होने के बाद खेलना बंद कर दिया था। लेकिन वह खुद को ज्यादा परेशान नहीं होने देती और वह नंबर एक खिलाड़ी क्यों है, उन्होंने फाइनल में पहुंचकर भी बता दिया। बार्टी ने गुरुवार को यहां पूर्व चैंपियन एंजेलिक कर्बर को सीधे सेटों में हराकर पहली बार विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश किया। आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बार्टी ने एंजेलिक कर्बर को 6-3, 7-6 (7-3) से हराया।

फाइनल में उनका मुकाबला कैरोलिना प्लिस्कोवा से होगा जिन्होंने अन्य सेमीफाइनल में आर्यना सबालेंका को 5-7, 6-4, 6-4 से हरा दिया। पूर्व विश्व नंबर एक प्लिस्कोवा ने शुरुआती सेट में पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए पहली बार विंबलडन के फाइनल में जगह पक्की की और इस बार विंबलडन को नई महिला चैंपियन मिलेगी। फाइनल मुकाबला शनिवार को खेला जाएगा।

इससे पहले बार्टी 2011 में विंबलडन में जूनियर चैंपियन भी रही थीं। उन्होंने कहा, 'मेरे करियर में कई उतार-चढ़ाव आए और उस बीच में हर चीजें हुईं लेकिन, हमें अपने रास्ते और सफर पर चलना चाहिए। विंबलडन में खेलना सबसे अच्छा अनुभव रहा है। मैंने अभी तक जितने मैच खेले हैं, उसमें यह सर्वश्रेष्ठ टेनिस मैच रहा है।' 25 वर्षीय बार्टी ने 2019 फ्रेंच ओपन के रूप में अपने करियर का पहला ग्रैंडस्लैम खिताब जीता था। बार्टी के खिलाफ पहला सेट गंवाने के बाद उनके पास दूसरे सेट में वापसी का मौका था। कर्बर 5-3 पर सेट के लिए सर्विस कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी सर्विस गंवा दी। इसके बाद यह सेट टाई ब्रेकर तक खिंच गया। फ्रेंच ओपन 2019 की विजेता बार्टी ने टाईब्रेकर में 6-0 की बढ़त हासिल कर ली और फिर अपने चौथे मैच प्वाइंट पर जीत दर्ज की। कर्बर का बैकहैंड तब नेट पर उलझ गया था।

फेडरर को अगला विंबलडन खेलने का भरोसा नहीं : ग्रासकोर्ट के बादशाह रोजर फेडरर का आल इंग्लैंड क्लब पर अमूमन दर्शकों ने खड़े होकर अभिवादन किया है लेकिन, इस बार क्वार्टर फाइनल में उनकी अप्रत्याशित हार के बाद यह अभिवादन विदाई जैसा लग रहा था और आठ बार के चैंपियन इस महान खिलाड़ी ने स्वीकार किया कि उन्हें पता नहीं है कि वह अगला विंबलडन खेल सकेंगे या नहीं। यह वह फेडरर नहीं थे जिसे देखने की दुनिया भर के टेनिसप्रेमियों को आदत रही है। पिछले साल घुटने के आपरेशन के बाद से वह सिर्फ आठ मैच खेले हैं। मैच के दौरान फेडरर के रैकेट से वैसे स्ट्रोक्स नहीं निकले जिन्होंने उन्हें 20 बार ग्रैंडस्लैम चैंपियन बनाया। मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में यह पूछने पर कि क्या यहां उनका यह आखिरी मैच था इस पर फेडरर ने कहा, 'पता नहीं। मुझे सच में नहीं पता। मुझे आत्ममंथन करना होगा।' टेनिस से संन्यास की संभावना पर उन्होंने कहा, 'अभी नहीं। उम्मीद है कि अभी नहीं। अभी खेलने का लक्ष्य है।' फेडरर ने कहा, 'पिछले कुछ मैच अपेक्षा के अनुरूप नहीं थे। मुझे ऐसे हालात की आदत नहीं है। यहां तो कतई नहीं।'

सिटी ओपन से प्रतिस्पर्धी टेनिस में वापसी करेंगे नडाल

वाशिंगटन, एपी : राफेल नडाल यूएस ओपन की तैयारियों के सिलसिले में वाशिंगटन में सिटी ओपन हार्ड कोर्ट टूर्नामेंट के जरिये प्रतिस्पर्धी टेनिस में वापसी करेंगे। सिटी ओपन ने गुरुवार को घोषणा की कि 20 बार के ग्रैंडस्लैम चैंपियन नडाल यूएस ओपन से पहले 31 जुलाई से आठ अगस्त के बीच होने वाले इस टूर्नामेंट के मुख्य आकर्षण होंगे। नडाल ने पिछले महीने फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविक से हारने के बाद कोई मैच नहीं खेला है। इस 35 वर्षीय खिलाड़ी ने विंबलडन और 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक में नहीं खेलने का फैसला किया है। सिटी ओपन में जो अन्य खिलाड़ी भाग लेंगे, उनमें विंबलडन के सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाले डेनिस शापोवालोव और हुबर्ट हरकाज शामिल हैं।

आज खेले जाने वाले पुरूष सिंगल्स के सेमीफाइनल

नोवाक जोकोविक *vs* शापोवालोव
मेटेयो बेरेटिनी *vs* हुबर्ट हरकाज



मैच जीतने के बाद एश्ले बार्टी • एएफपी

श्रीलंका के बल्लेबाजी कोच फ्लावर भारत के खिलाफ सीरीज से पहले पाजिटिव

क्रिकेट डायरी

कोलंबो, प्रेट्र : श्रीलंका के बल्लेबाजी कोच ग्रांट फ्लावर को टीम के इंग्लैंड से यहां पहुंचने के 48 घंटे बाद और भारत के खिलाफ सीमित ओवर की सीरीज से एक सप्ताह पहले गुरुवार को कोविड-19 के लिए पाजिटिव पाया गया। श्रीलंका की टीम अभी कड़े क्वारंटाइन में है और फ्लावर को उससे अलग-थलग कर दिया गया है।

श्रीलंका क्रिकेट ने कहा, 'टीम के बल्लेबाजी कोच फ्लावर का कोविड-19 परीक्षण पाजिटिव आया है। फ्लावर में इस बीमारी के हल्के लक्षण नजर आने के बाद उनका गुरुवार को पीसीआर परीक्षण किया गया, जो पाजिटिव आया है। इसका पता चलने के तुरंत बाद फ्लावर को टीम के अन्य सदस्यों से अलग-थलग कर दिया गया, जो कि इंग्लैंड से लौटने के बाद क्वारंटाइन में हैं।'

श्रीलंका क्रिकेट ने साथ ही कहा कि जो खिलाड़ी क्वारंटाइन हैं उन सभी का भी परीक्षण किया जा चुका है।

सलामी बल्लेबाजों के विवाद पर सौरव गांगुली ने तोड़ी चुप्पी

कोलकाता, प्रेट्र : बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली ने चोटिल सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल की जगह किसी अन्य खिलाड़ी को इंग्लैंड नहीं भेजने के फैसले पर उठे विवाद पर गुरुवार को कहा कि यह चयनसमिति से जुड़ा विषय है। भारतीय टीम प्रबंधन ने अपने प्रशासनिक मैनेजर गिरीश डोंगरे के जरिये 28 जून को गिल की जगह दो सलामी बल्लेबाजों को भेजने के लिए कहा था। उन्होंने पृथ्वी शा और देवदत्त पडीक्कल के नाम भी सुझाए थे लेकिन, चयनसमिति के अध्यक्ष चेतन शर्मा ने दो दिन पहले तक कोई औपचारिक उत्तर नहीं भेजा था। गुरुवार को 49 साल के हुए गांगुली अपने जन्मदिन के अवसर पर पत्रकारों से बात कर रहे थे तो उनसे इस विवादास्पद मामले के बारे में भी पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'यह चयनकर्ताओं का फैसला है।'

सीरीज में अधिक आत्मविश्वास से भरा युजी दिखेगा : चहल

कोलंबो, प्रेट्र : भारतीय वनडे टीम में वापसी करने वाले लेग स्पिनर युजवेंद्रा सिंह चहल ने गुरुवार को कहा कि वह अपनी गेंदबाजी की विविधताओं पर काम कर रहे हैं और श्रीलंका के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज में लोगों को अधिक आत्मविश्वास से भरा युजी (युजवेंद्रा) दिखेगा। चहल ने कहा, 'मेरे पास कुछ वैरिएशन (विविधतापूर्ण गेंदबाजी) हैं और मैं सिर्फ उन्हीं पर ध्यान लगा रहा हूं, अन्य गेंदों पर नहीं। इस सीरीज में आपको अधिक आत्मविश्वास से भरा युजी दिखेगा। मैं सिर्फ अपने कोणों पर काम कर रहा हूं और अधिक गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहा हूं।' विश्व कप 2019 से पहले भारत की वनडे टीम का अहम हिस्सा रहे चहल को बीसीसीआइ ने वार्षिक अनुबंधों की सूची में ग्रेड-बी से ग्रेड-सी में खिसका दिया है।

17 को टोक्यो जाएगा भारत का पहला दल

अभिषेक त्रिपाठी • नई दिल्ली

भारत का 90 सदस्यों का पहला ओलंपिक दल अब 17 जुलाई को टोक्यो के लिए रवाना होगा। भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए) के एक पदाधिकारी ने बताया कि खिलाड़ियों सहित स्टाफ सदस्य मिलाकर पहला दल एयर इंडिया की चार्टेड फ्लाइट से रवाना होगा। हालांकि पहले यह दल 14 जुलाई को जाना था लेकिन ओलंपिक आयोजकों ने भारत के आग्रह स्वीकार नहीं किया, जिस पर आइओए ने निराशा भी व्यक्त की।

भारतीय खिलाड़ियों और अधिकारियों को टोक्यो पहुंचने पर तीन दिन के लिए अनिवार्य क्वारंटाइन पर रहना होगा। सूत्रों के अनुसार टोक्यो आयोजन समिति के क्षेत्रीय प्रबंधक काते योनेयामा को भेजे गए ईमेल में आइओए अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने लिखा है कि आवश्यक मंजूरी लंबित होने के कारण आइओए के पास खिलाड़ियों का पहला दल 17 जुलाई को भेजने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। आइओए प्रमुख ने ईमेल में लिखा, 'टोक्यो आयोजन समिति से हमें आवश्यक मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए हम भारतीय दल को 17 जुलाई को भेजने की तैयारी कर रहे हैं, जो 18 जुलाई को टोक्यो पहुंचेगा। हम बेहद निराश हैं कि हमारे आग्रह को मंजूर नहीं किया गया। भारत पर लगाए गए सात दिन पहले प्रस्थान करने के चिकित्सा प्रोटोकाल को देखते हुए हमारे पास 17 जुलाई को रवाना होने और 18 जुलाई को वहां पहुंचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।'



टोक्यो में गुरुवार को सेंटर प्रोमेंड पार्क के बाहर घूमती दो महिलाएं • रायटर

> पहले 14 जुलाई को रवाना होना था दल, आयोजकों ने भारत के आग्रह को नहीं किया स्वीकार

बिना दर्शकों के होगा टोक्यो ओलंपिक का आयोजन

ओलंपिक डायरी

टोक्यो, रायटर : जापान में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए कहर को देखते हुए वहां के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने टोक्यो में आपातकाल लगाने का फैसला किया है। इसके बाद ओलंपिक मंत्री तमायो मौरकावा ने भी इस बात का एलान किया कि अब ओलंपिक में दर्शकों को आने की अनुमति नहीं मिलेगी।

तमायो मौरकावा ने कहा, 'आपातकाल की स्थिति लागू होने के कारण ओलंपिक दर्शकों के बिना आयोजित किए जाएंगे।' जापान के पीएम सुगा ने कहा कि टोक्यो शहर में 12 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक आपातकाल लागू रहेगा। टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आयोजन 23 जुलाई से आठ अगस्त के बीच होना है। पहले ही मैदान पर विदेशी दर्शकों के जाने पर रोक लगाने का फैसला ले लिया गया था, लेकिन अब आपातकाल लागू होने के बाद टोक्यो के लोगों के भी मैदान पर जाकर ओलंपिक खेलों को देखने की संभावना खत्म हो गई है। बीते दो दिनों से टोक्यो में कोरोना वायरस के रिकार्ड मामले सामने आ रहे हैं। गुरुवार को टोक्यो में कोरोना के 896 मामले सामने आए हैं। इससे पहले बुधवार को टोक्यो में कोविड-19 के 920 मामले सामने आए थे।

दुती बोलीं, मेरा लक्ष्य 11.10 सेकेंड : विश्व रैंकिंग कोटा के जरिये टोक्यो ओलंपिक में जगह बनाने वाली फर्राटा धाविका दुती चंद का लक्ष्य 100 मीटर की दौड़ को 11.10 सेकेंड के अंदर पूरा करना है, जो उनके अनुसार सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए जरूरी होगा। ओडिशा की दुती ने कहा, 'मैंने एशियाई स्तर पर पदक जीता है, लेकिन ओलंपिक में दुनिया भर के शीर्ष खिलाड़ी आते हैं। अमेरिका या जर्मनी के धावकों की टाइमिंग तो 10 सेकेंड के आसपास तक चली जाती है। मैंने 11.10 सेकेंड का लक्ष्य रखा है, जिससे सेमीफाइनल तक आ सकती हूं।'

सिंधू को ओलंपिक में मिला आसान ड्रा

कुआलालंपुर: भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधू और पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत को टोक्यो ओलंपिक के लिए आसान ड्रा में रखा गया है, जबकि दुनिया की 10वें नंबर की भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी को ग्रुप-ए में रखा गया है। सिंधू को जहां ओलंपिक में छठी वरीयता मिली है और वह महिला सिंगल्स के ग्रुप-जे में शामिल हैं। वहीं प्रणीत को पुरुष सिंगल्स के ग्रुप-डी में 13वीं वरीयता मिली है। ओलंपिक में सिंधु अपने पहले मुकाबले में हांगकांग की चेयुंग निगान यि (34वीं रैंकिंग) और इजरायल की केसनिना पोलीकारपोवा (58वीं रैंकिंग) के सामने होंगी, जबकि प्रणीत नीदरलैंड्स के मार्क कालजोऊ (29वीं रैंकिंग) और इजरायल के मिशा जिल्बरमैन (47वीं रैंकिंग) से भिड़ेंगे। सिंगल्स स्पर्धा में प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष खिलाड़ी नाकआउट चरण के लिए क्वालीफाई करेंगे।चिराग और सात्विकसाईराज को मुश्किल ड्रा मिला है।

भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच पहला टी-20 आज

नार्थैंप्टन, प्रेट्र : भारतीय कप्तान हरमनप्रीत मेजबान इंग्लैंड की मजबूत टीम के खिलाफ शुक्रवार को यहां होने वाले पहले टी-20 मुकाबले में फार्म में वापसी के साथ बल्लेबाजी क्रम को मजबूती देने की कोशिश करेंगी, जो अब तक जूझता नजर आया है।

मौजूदा दौरे पर एकमात्र टेस्ट ड्रा रहा, जबकि इंग्लैंड ने वनडे सीरीज 2-1 से जीती। हरमनप्रीत ने नवंबर 2018 से खेल के सबसे छोटे प्रारूप में अर्धशतक नहीं जड़ा है और वह बड़ी पारी खेलकर उदाहरण पेश करना चाहेंगी। दोनों सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना अच्छी लय में हैं, लेकिन टीम को इन दोनों ही बल्लेबाजों के प्रदर्शन में अधिक निरंतरता की जरूरत है।

कभी जल गया था हाथ, अब ओलंपिक में लगाएंगी पंच



पूजा रानी • फाइल फोटो, ट्विटर

उपलब्धियां

एशियाई चैंपियनशिप

- 2021 में स्वर्ण पदक
- 2019 में स्वर्ण पदक
- 2012 में रजत पदक
- 2015 में कांस्य पदक
- 2014 में कांस्य पदक

शुभम पांडेय • नई दिल्ली

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब भी बात मुक्केबाजी की आती है तो विश्व में सबसे पहले क्यूबा का नाम आता है, जबकि भारत की बात करें तो हरियाणा के भिवानी को मिनी क्यूबा कहा जाता है। जहां से कविता चहल, जितेंद्र कुमार, विकास कृष्णन और ओलंपिक पदक विजेता विजेंद्र सिंह जैसे दिग्गज मुक्केबाज निकलकर आए हैं। इसी कड़ी को अब पूजा रानी आगे बढ़ा रही हैं, जो टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पदक का पंच लगाने के लिए तैयार है।

जब करियर खत्म होने के कगार पर था : 12 साल पहले मुक्केबाजी का पहला पंच लगाने वाली पूजा ने दैनिक जागरण को बताया कि कैसे 2016 ओलंपिक के समय उनका करियर खत्म होने की कगार पर था। मगर हार ना मानते हुए उन्होंने अपने पंचों पर फिर से जोर डालते हुए टोक्यो तक का सफर तय कर किया। 30 वर्षीय अनुभवी पूजा 2016 रियो ओलंपिक में जगह नहीं बना पाई थीं। उस समय को याद करते हुए उन्होंने कहा, 'उस समय ऐसा लगा था कि मेरा करियर खत्म हो गया जाएगा और मैं दोबारा रिंग में नहीं उतर पाऊंगी, क्योंकि उसी साल दीवाली के दौरान पटाखे जलाते हुए मेरा दायां हाथ जल गया था, जिससे उबरने में छह महीने लगे और अगले ही साल 2017 में मेरे कंधे में चोट आ गई थी। इसलिए एक तरफ ओलंपिक में भाग ना ले पाना बहुत कचोट रहा था। ऐसा लग रहा था कि कभी ओलंपिक नहीं खेल पाऊंगी। हालांकि, मेरे कोच, परिवार और लक्ष्य फाउंडेशन ने मेरा साथ दिया, जिससे मैं रिंग में दोबारा वापसी कर पाई।

हाल का प्रदर्शन : पूजा की हालिया लय की बात करें तो इन्होंने हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। इस बारे में पूजा ने कहा, 'ओलंपिक से पहले खेला जाने वाला यह अंतिम टूर्नामेंट था और इसमें स्वर्ण पदक जीतने से काफी आत्मविश्वास बढ़ा है। इसके साथ ही यह भी पता चलता है कि हमारी लय और तैयारी सही दिशा में जा रही है।'

तकनीक पर फोकस : 75 किग्रा के भार वर्ग में रिंग में उतरने वाली पूजा ने टोक्यो ओलंपिक की तैयारी और पदक जीतने की राह में आने वाली चुनौती को लेकर कहा, 'मैं इस समय इटली में अभ्यास कर रही हूं और तैयारी काफी अच्छी चल रही है। मैं ज्यादातर तकनीकी पर ध्यान केंद्रित कर रही हूं। वहीं पदक के लिए मेरे भार वर्ग में कुल 16 मुक्केबाज हैं, लेकिन नीदरलैंड्स, ग्रेट ब्रिटेन और रूस के मुक्केबाजों पर नजरें होंगी। मैं उन सबके खिलाफ वीडियो देखकर अनुसरण कर रही हूं और अपना गेम प्लान तैयार कर रही हूं।'

पदक के दावेदार
TOKYO 2020
14 दिन शेष

भारत को टीम के रूप में खेलों में आगे ले जाएंगे : ठाकुर

नई दिल्ली, जेएनएन : टोक्यो ओलंपिक से दो सप्ताह पहले गुरुवार को यहां नए खेल मंत्री का पदभार संभालने वाले अनुराग ठाकुर ने कहा कि सभी खेल महासंघों, राज्यों और संबंधित पक्षों को साथ लेकर वह एक टीम के रूप में भारत को खेलों में और आगे ले जाने का प्रयास करेंगे।

ठाकुर ने कहा, 'हम सारी टीम के साथ मिलकर देशभर में खेलों को बढ़ाने का काम करेंगे। राज्यों, खेल संस्थाओं, खेल संघों और महासंघों को साथ में लेकर हरसंभव प्रयास करेंगे।' मणिशंकर अय्यर (2006-2008) के बाद ठाकुर पहले कैबिनेट मंत्री हैं, जिन्हें खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नीतीश प्रमाणिक को खेल मंत्रालय में राज्यमंत्री बनाया गया है। ठाकुर के पास सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का भी जिम्मा है।

ठाकुर ने कहा, 'मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री का, जिन्होंने मेरे ऊपर युवाओं और खेलों को लेकर एक नई जिम्मेदारी दी है। खेलों के प्रति उनका प्यार और भारत को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने लगातार मुहिम चलाई है, मैं प्रयास करूंगा कि किरण (पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू) उसे जहां तक लेकर गए, मैं उसे आगे बढ़ा सकूं।'

ठाकुर का खेलों से पुराना रिश्ता है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की तरफ से एक रणजी ट्राफी मैच खेला था तथा वह मई 2016 से फरवरी 2017 तक बीसीसीआइ के अध्यक्ष भी रहे थे। इससे पहले वह बीसीसीआइ के सचिव तथा हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के अध्यक्ष थे।



कार्यभार ग्रहण करने जाते अनुराग ठाकुर • प्रेट्र

दैनिक जागरण
सप्तरंग
मनोरंजन की दुनिया का
शुक्रवार, 9 जुलाई, 2021

देश के कई हिस्सों में बारिश का मौसम दस्तक दे चुका है। स्व. राज कपूर व यश चोपड़ा की फिल्मों से लेकर सूरज बड़जात्या और करण जौहर की फिल्मों तक इस मौसम में कई गाने, एक्शन, इमोशनल सीन फिल्माए गए हैं। फिल्म 'श्री 420' में राज कपूर और नरगिस पर फिल्माया गया गाना प्यार हुआ इकरार हुआ... बारिश में रोमांस का खूबसूरत खयाल पैदा करता है। बरसो रे मेघा..., रिमझिम गिरे सावन..., जैसे गाने इस मौसम को और खूबसूरत बना देते हैं। हालांकि आजकल की फिल्मों में सावन के झूले कम ही नजर आते हैं। अब बरसात पर गाने भी उतनी तादाद में नहीं बनते हैं, लेकिन इस मौसम के प्रति आकर्षण बरकरार है। बारिश पर गानों और उन्हें फिल्माने की चुनौतियों की पड़ताल कर रहे हैं प्रियंका सिंह व दीपेश पांडेय...

सिनेमा में रोमांस घोलती ये बारिश की बूंदें...

बालीवुड ट्रेंड

बरसात की सिचुएशन के आसपास कहानियां और गाने गढ़ना बालीवुड फिल्मों का पसंदीदा ट्रेंड रहा है। बारिश के इस मौसम में उन फिल्मों और गानों की बात भला कैसे न हो। साल 1979 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म 'मंजिल' का गाना 'रिमझिम गिरे सावन' को मुंबई की सड़कों पर शूट किया गया था। बताया जाता है कि इस गाने को शूट करने के लिए फिल्म निर्माताओं ने बारिश होने का कई दिनों तक इंतजार किया था। 'टिप टिप बरसा पानी' गाने में भले ही रवीना टंडन को देखकर लोग मदहोश हो जाते हों, लेकिन इस गाने की शूटिंग को लेकर रवीना कहती हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पर बिना चप्पल पहने मैंने डांस किया था। कभी वहां पड़े स्क्रू तो कभी कंकड़ पैरों में चुभ जाते थे। टैंक का पानी बहुत ठंडा था, सेट पर तीसरे दिन मुझे बुखार आ गया था। गर्म पानी में अदरक और शहद डालकर पी रही थी।

ऐसे आती है गानों में रवानगी: बरसात पर कई गाने बना चुके संगीतकार ललित पंडित कहते हैं कि इन गानों की मेकिंग दूसरे रोमांटिक गानों से मुश्किल होती है। स्टेप बाय स्टेप गाने पर काम होता है, तब बरसात के गाने की रवानगी बनती है। पहले की फिल्मों में बाकायदा बरसात के गानों की सिचुएशन बनाई जाती थी। 'खिलाड़ी' फिल्म का गाना 'देखा तेरी मस्त निगाहों में', 'फना' फिल्म का गाना 'ये साजिश है बूंदों की', 'गुलाम' फिल्म का 'आंखों से तूने ये क्या कह दिया...' हमारे बरसात आधारित गाने थे। सिचुएशन के मुताबिक गाने बनाए जाते हैं, उससे फिल्म में जो बात आती है और कंपोजिशन जब उड़ान भरती है तो गाने हिट हो जाते हैं। कई बार बरसात के गाने हम गर्मी या ठंड के मौसम में बैठकर बनाते हैं। ऐसे में बरसात के मौसम की कल्पना करनी होती है। अमिताभ बच्चन साहब का गाना 'आज रपट जाएं...' देख लीजिए, क्या मस्ती और रोमांस है। किशोर दा ने उस गाने को पूरी मस्ती में गाया है। बरसात की सिचुएशन में ही एक तीव्रता होती है। ये गाने फिल्मों के लिए स्कोरिंग प्वाइंट्स रहे हैं। 'प्यार हुआ इकरार हुआ...', 'हाय हाय ये मजबूरी ये मौसम और ये दूरी...', 'पानी रे पानी तेरा रंग कैसा...' इन्हें


फिल्म श्री 420 में 'प्यार हुआ इकरार हुआ' गाने का दृश्य


फिल्म बागी में 'छम छम छम' गाने का दृश्य

फिल्माया भी तरीके से गया है। पैरों से जमे हुए पानी को मारना, कीचड़ उड़ाना, वह मूड इन गानों में क्रिएट किया गया है।

सावन के मौसम को जीना पड़ता है: गीतकार समीर कहते हैं कि बरसात के पांच हजार गाने भी लिखने हों तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने सावन के मौसम को जीया है। गांव के चौपाल में जब कुंवारी लड़कियां सावन के गाने गाया करती थीं, वह दृश्य आंखों में बसा है। पहले की फिल्मों में रोमांस को दिखाने के लिए इस मौसम का इस्तेमाल किया जाता था। 'हाय हाय ये मजबूरी ये मौसम और ये दूरी... ', इस गाने में जो हीरो-हीरोइन एक-दूसरे से कह रहे हैं, वह खुलेआम उस जमाने में नहीं कह सकते थे। अब तो सब खुलेआम होता है। इसलिए मौसमों, त्योहारों, रिश्तों की बातें कम हो रही हैं। डार्क सिनेमा का दौर है, लेकिन एक बात तय है कि इंसान कितना भी बदल जाए, कुदरत नहीं बदलती है। सावन अब भी आता है, एहसास दिल में होते हैं। राज कपूर, यश चोपड़ा सभी शीर्ष फिल्ममेकर्स की फिल्मों में


फिल्म दिल तो पागल है में 'कोई लड़की है जब वो हंसती है' गाने का दृश्य

बरसात को खूबसूरती से फिल्माया जाता था। शिफान की साड़ी, हवा, बरसात के साथ एक सामाजिक जिम्मेदारी के तहत वे इन गानों को शूट करते थे। साहिर लुधियानवी साहब का गाना 'जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात...' का चित्रण बहुत ही खूबसूरत था। 'बरसात के दिन आए...', 'भरी बरसात में इकरार हुआ' जैसे कई गाने मैंने भी लिखे हैं। आज की फिल्मों में प्यार तो है, लेकिन उसका एहसास बदल गया है। बरसात ने भी शहरों को इतना डराया है कि रोमांस कहां से आएगा।

बरसात के सीन बढ़ा देते हैं बजट: कुणाल कोहली निर्देशित फिल्मों 'फना' और 'हम तुम' में बरसात की सिचुएशन बनाई गई थी। इस बाबत कुणाल कहते हैं कि मैं जब निर्देशक नहीं बना था, तभी सोच लिया था कि जब निर्देशक बनूंगा तो बरसात के दृश्य मेरी फिल्मों में जरूर होंगे। हालांकि इन दृश्यों को फिल्माया जाना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। जब कलाकार पानी में भीग रहे होते हैं तो कभी कीचड़ हो जाता है तो कभी कोई छींक रहा होता है। स्क्रीन पर भले ही वह माहौल बहुत रोमांटिक लगता हो, लेकिन ज्यादातर कलाकार बरसात के सीन करने के दौरान असहज महसूस करते हैं। कलाकारों को ऐसी असहज अवस्था में भी स्क्रीन पर रोमांटिक दिखाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसके अलावा लाइटिंग से लेकर इलेक्ट्रानिक सामानों तक काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ताकि किसी को इलेक्ट्रिक शाक न लगे, कैमरा पानी में सुरक्षित रहे। सेट पर सैकड़ों डांसर्स को संभालना उतना मुश्किल नहीं होता है, जितना बारिश का एक गाना शूट करना होता है। बारिश के सीन फिल्माते हुए निर्माता को भी सामान्य दृश्यों की तुलना में ज्यादा खर्च करना पड़ता है। पानी, रेन मशीन, वाटरप्रूफ उपकरण समेत कई अतिरिक्त चीजों का इस्तेमाल होता है।

बनते रहेंगे इस मौसम पर गाने: बारिश पर बने कई गाने गा चुके गायक जुबिन नौटियाल कहते हैं कि बरसात में बैठकर गाना रिकार्ड करना हमेशा गायक के लिए स्पेशल होता है। जश्न के गाने हों या दुख भरे गाने, बरसात हर परिस्थिति में पानी की तरह घुल जाती है। बरसात में एक अलग किस्म की शांति होती है। ऐसे कई गाने हैं, जिनमें बारिश की ध्वनि का प्रयोग म्यूजिक के तौर पर किया गया है। बारिश में हर कोई बच्चा बन जाता है, मैं भी। बारिश के मौसम में भाई-बहनों के साथ खेलना मेरी सबसे अच्छी यादें हैं। बरसात के गानों को सुनने वाले पहले भी मौजूद थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। परिस्थितियां सामान्य होने के बाद मुझे लगता है कि फिर से फिल्मों में बरसात का प्रयोग बढ़ेगा। मैं कुछ दिनों में ही बारिश पर आधारित अपना अगला गाना लाने वाला हूं।

पहले की तरह प्रमोट नहीं होते गाने: 'हाफ गर्लफ्रेंड' का गाना 'ये बारिश की बूंदें...' का संगीत देने वाले संगीतकार तनिष्क बागची कहते हैं कि बारिश और संगीत का संबंध पुराना है। संगीतकार तानसेन के राग से होने वाली बरसात की कहानियां हमने सुनी हैं। हर दौर के गानों में बारिश और रोमांस को जोड़ा गया है। सावन के महीने में जो कपल एक-दूसरे के साथ रहते हैं उनके लिए तो रोमांटिक मौसम होता है, लेकिन जो अपने प्रेमी से दूर हैं, उन्हें भी अपने प्रेमी की याद आने लगती है। इन परिस्थितियों को लेकर भी कई गाने बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि मौजूदा दौर में फिल्मों में बारिश पर कम गाने बनते हैं। मैंने खुद कई फिल्मों के लिए बरसात पर गाने बनाए हैं, पर वे गाने प्रमोट नहीं होते। उनकी जगह डांस नंबर्स ज्यादा प्रमोट हो जाते हैं। मुझे लगता है कि आगे फिल्मों में जो गाने आएंगे उनमें भारतीय संगीत और रोमांस को प्राथमिकता दी जाएगी।

तुंबाड में बारिश के लिए किया इंतजार



फिल्म 'तुबांड' के दृश्य असल बारिश के मौसम में शूट हुए थे। फिल्म के अभिनेता और सह निर्माता सोहम शाह कहते हैं कि फिल्म में लैंडस्केप और बादलों के दृश्य वास्तविक दिखाने के लिए हमने इस मानसून में शूट किया था। शूटिंग के दौरान लाइट पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल था। अगर कभी बादलों वाले सीन की शूटिंग के दौरान अचानक धूप आ जाती या फिर बादल कम हो जाते तो सही लाइटिंग के लिए दोबारा बादलों के आने का इंतजार करना पड़ता था। कभी-कभी तो पूरे क्रू को दो-तीन दिन तक इंतजार करना पड़ा था।

इंडिपेंडेंट गानों में भी बारिश है हिट



गायिका पायल देव कहती हैं कि 'बारिश बन जाना...' गाना मेरे दिल के बहुत करीब है। फिल्में सिर्फ एक गाने से नहीं बनती, बल्कि उनमें अलग-अलग परिस्थितियां होती हैं। फिल्म किसी भी मौसम में रिलीज हो सकती है, जिसमें बारिश का एक सीन हो सकता है, लेकिन इंडिपेंडेंट गाने बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि गाना किस मौसम में रिलीज किया जाएगा। अगर बारिश के मौसम में इंडिपेंडेंट बारिश का गाना रिलीज होता है तो उसको दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है, क्योंकि लोग खुद को उससे जोड़ पाते हैं।

मुलाकात

दिल को जो सही लगे वही करती हूं

खेल पर आधारित फिल्मों में अगर अभिनेता मुख्य किरदार में होता है तो अक्सर अभिनेत्री के हिस्से ज्यादा काम नहीं आता है, लेकिन फिल्म 'तूफान' में मृणाल ठाकुर के किरदार के साथ ऐसा नहीं है। वह कहती हैं कि हर खिलाड़ी के पीछे एक ऐसा इंसान जरूर होता है, जो उसे प्रेरणा देने के लिए मौजूद होता है। वह किरदार फिल्म में वह निभा रही हैं। 'तूफान' फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर 16 जुलाई को रिलीज होगी। मृणाल से बातचीत के अंश:



आप फिल्म में काफी सशक्त भूमिका में नजर आ रही हैं...
हां, मेरा किरदार फिल्म में बहुत अहम है। फिल्म के निर्देशक राकेश ओमप्रकाश मेहरा सर के साथ काम करके अच्छा लग रहा है। उनके साथ काम करना है, यह सोचने की हिम्मत आठ-नौ फिल्में करने के बाद आती है, लेकिन मुझे यह मौका अपने करियर के शुरुआती दौर में ही मिल गया है। ट्रेलर में मेरे किरदार का आत्मविश्वास दिख रहा है। फिल्म में मेरा किरदार एक ऐसी लड़की का है, जो अपने पार्टनर के पीछे हर कदम पर खड़ी है। कहीं न कहीं फिल्म के किरदार और मुझमें बहुत सी समानताएं हैं।

आपने कालेज के दिनों में राकेश ओमप्रकाश मेहरा को फेसबुक पर एक मैसेज किया था। याद है कि इस मैसेज में आपने क्या लिखा था?
(हंसते हुए) हां, मैंने उन्हें मैसेज किया था। यह तब की बात है, 'जब भाग मिल्खा भाग' फिल्म रिलीज हुई थी। मुझे फिल्में अकेले देखने का शौक है। 'जब भाग मिल्खा भाग' रिलीज हुई थी, तब मैं कालेज में थी और तब तक मुझे यह पता नहीं था कि मैं अभिनेत्री बनना चाहती हूं या नहीं। फिल्म को देखने के बाद जेहन में यही चल रहा था कि फरहान अख्तर और राकेश सर ने फिल्म में कमाल कर दिया है। इस जोड़ी ने उस वक्त मुझे बहुत प्रभावित और प्रेरित किया था। कह सकते हैं कि उनकी वजह से मैंने तय किया कि मुझे भी एक्टिंग में आना चाहिए। मैंने सोचा कि भले ही राकेश सर मेरा मैसेज देखें या न देखें, लेकिन बहुत जरूरी है मुझे यह बताना कि उन्होंने मुझे किस हद तक प्रेरित किया है। मैंने एक थैंक्यू नोट लिखा था। जिसमें आगे लिखा था कि एक बार मैं आपसे मिलना चाहती हूं। मैं फिल्म देखकर बहुत प्रेरित हुई हूं। ईश्वर की कृपा से अब मैंने पूरी फिल्म ही उनके साथ कर ली है।

आपका किरदार फरहान अख्तर के सामने दो विकल्प रखता है, जिनमें से एक उन्हें चुनना होता है। वास्तविक जीवन में आप किसी बात पर निर्णय कैसे लेती हैं?
हमारी जिंदगी में हमेशा एक ऐसा इंसान होता है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मैं जब अपने करियर को लेकर अहम निर्णय ले रही थी, उस वक्त मेरी दोस्त ने मदद की थी। कई बार जब हम भटक जाते हैं तो हमें एक इंसान चाहिए होता है, जो हमें सही दिशा दिखा पाए। जब आसपास कोई समझाने वाला नहीं होता है या मैं कनफ्यूज हो जाती हूं तो उस वक्त जो दिल को सही लगता है, वही करती हूं। आपका मन आपको कभी गलत दिशा नहीं दिखाएगा। मैं बस भीतर की आवाज सुनती हूं और अपने निर्णय लेती हूं।

पहले से बाक्सिंग के बारे में कितना जानती थी?
बाक्सिंग के बारे में बहुत ज्यादा जानती नहीं थी। फिल्म का हिस्सा बनने के बाद महसूस हुआ कि देश के हर बच्चे को बाक्सिंग रिंग में उतरकर बाक्सिंग सीखनी चाहिए। यह खेल न सिर्फ फिट रखता है, बल्कि जीवन में आई समस्याओं से लड़ने के लिए मजबूत बनाता है।

जीवन में कुछ तूफानी करने का सपना रहा है?
(हंसते हुए) हां, बचपन से पता था कि कुछ तो तूफानी करना है। मुझे लगता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए खुद के भीतर एक तूफान होना चाहिए। डरकर बैठने से जीवन में कुछ नहीं होता है। मुसीबतों का सामना करना चाहिए। खुद पर यकीन करें। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में रखकर आगे बढ़ें, जो प्रेरित करें और सही दिशा दिखाएं। निगेटिव लोगों को दूर रखें। इस फिल्म से मैंने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बल्कि ऐसी चीजें सीखी हैं, जो जीवन के निर्णय लेने में मेरी मदद करेंगी।

प्रियंका सिंह

निर्देशक कोना

मैं चौरासी उपन्यास के इश्क में था

फिल्म 'बमफाड़' के बाद रंजन चंदेल ने वेब सीरीज 'ग्रहण' का निर्देशन किया है। वर्ष 1984 की पृष्ठभूमि में बनी यह सीरीज दैनिक जागरण हिंदी बेस्ट सेलर रहे सत्य व्यास के उपन्यास 'चौरासी' से प्रेरित है। यह शो एक पिता-पुत्री की कहानी है। शो में पिता की भूमिका में पवन मल्होत्रा, जबकि उनकी बेटी और पुलिस अधिकारी की भूमिका में जोया हुसैन हैं। कानपुर से ताल्लुक रखने वाले रंजन ने शो, अपने सफर और आगामी प्रोजेक्ट्स को लेकर बात की स्मिता श्रीवास्तव से...



निर्देशक बनने का सफर कैसे शुरू हुआ?
मैंने पुणे से एमबीए किया था। उसके बाद दो साल बेंगलुरू में एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी की, पर उसमें दिल नहीं लगा। मेरा काफी समय कहानियां सुनने-सुनाने में जाता था। यह फितरत बचपन से थी, पर फिल्म इंडस्ट्री से कोई कनेक्शन नहीं था। जब नौकरी करने लगा तो लगा कि आत्मनिर्भर हो गए हैं, तब मैंने फिल्मों को एक्सप्लोर करना शुरू किया। बहुत सारी फिल्में देखीं। फिल्ममेकिंग की तरफ मेरा ध्यान गया। फिर एक प्वाइंट पर तय किया कि मुझे नौकरी छोड़कर मुंबई आना चाहिए। मैं साल 2011 में मुंबई आया था। मुंबई में मेरा कालेज का दोस्त रहता था। उसके साथ रहा। वहां से जाना कि फिल्में कहां बनती हैं। कहानी लिखना शुरू किया। उसे लेकर लोगों से मिलना शुरू किया। इस तरह अनुराग कश्यप के संपर्क में आया। मेरे पास कोई विषय था जो उन्हें पसंद आया था। उन्होंने कहा कि तुम इस पर लिखो मैं बनाऊंगा। हालांकि वह फिल्म बनी नहीं। फिर 'मुक्काबाज' के डायलाग मैंने लिखे थे। नीरज घेवन निर्देशित शार्ट फिल्म 'जूस' का सहलेखन किया था। 'जान जिगर' नामक शार्ट फिल्म बनाई। जिसे मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डेब्यू का अवार्ड मिला। फिर अपनी पहली फिल्म 'बमफाड़' बनाई।

'ग्रहण' की शुरुआत कैसे हुई?
'बमफाड़' का पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था। उस समय मैंने 'चौरासी' उपन्यास पढ़ा था। उसने मुझे कहानी को बनाने के लिए प्रेरित किया था। हालांकि बाद में मैं दूसरे कामों में व्यस्त हो गया। एक दिन मेरी फिल्म 'बमफाड़' के निर्माता ने मुझसे कहा कि एक किताब के राइट्स हैं। उन्होंने किताब का नाम नहीं लिया, बस यही कहा है कि किताब की कहानी बोकारो में सेट है। यह सुनते ही मैंने कहा कि आप चौरासी उपन्यास की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा हां। मैंने कहा कि मैं यह शो डायरेक्ट कर रहा हूं। इसे लिखना बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हम इतने वृहद सब्जेक्ट से डील कर रहे थे।

'चौरासी' उपन्यास से प्रेरित वेब सीरीज बनाते समय यह नहीं लगा कि लोग दोनों की तुलना करेंगे?
मुझे चिंता से ज्यादा उपन्यास से प्यार था। उस किताब की खूबसूरती को जस्टीफाई करना था। उपन्यास की जो कहानी है वह शो का आधा हिस्सा है। हमारे शो में दो टाइमलाइन चल रही हैं। साल 1984 में मनु ऋषि की प्रेम कहानी चल रही है और वर्तमान में अमृता और गुरसेवक की बेटी और पिता की कहानी है। उपन्यास से मनु और ऋषि की लव स्टोरी ली है। उसमें मनु के साथ ट्रेजडी होती है। उसके साथ हिंसा और दुष्कर्म होता है और उससे उसे बेटी होती है जो बड़ी होकर अमृता बनती है। यह दुष्कर्म वाला हिस्सा उपन्यास में नहीं है। हमने उसे काल्पनिक तौर पर सीरीज के लिए विकसित किया है।

पवन मल्होत्रा और जोया हुसैन की कास्टिंग आपकी पसंद थी?
अमृता का किरदार जब लिखा जा रहा था तो उसमें मैं जोया को ही देख पा रहा था। फिल्म 'मुक्काबाज' एक तरह से हम दोनों के करियर की शुरुआत थी। वह भावों को बहुत खूबसूरती से बिना लाउड हुए व्यक्त कर जाती हैं। अमृता की एक तरफ ड्यूटी है, दूसरी तरफ आरोपित पिता। दोनों के बीच में पतली सी धार है उस पर उसे चलना है। पिता के किरदार में पवन ही जेहन में आए।

अगले प्रोजेक्ट की क्या तैयारी है
मैं एक लव स्टोरी लिख रहा हूं। उस पर फिल्म बनाने की तैयारी है। उसके अलावा एक वेब सीरीज पाइप लाइन में है। ओशो की पहली सेक्रेटरी थीं लक्ष्मी, उनपर एक किताब लिखी गई है 'ओनली लाइफ'। उसके अधिकार लिए हैं। उसके सेटअप की तैयारी है। यह गुरु और शिष्य की कहानी है। आचार्य रजनीश से ओशो बनाने में लक्ष्मी ने अहम भूमिका अदा की थी। ओशो का मेरे जीवन पर बड़ा प्रभाव है तो उस पर वेब सीरीज बनाना चाहता हूं। यह बड़ा प्रोजेक्ट है। इसकी तैयारी कर रहा हूं।





विंबलडन के पहले टूर्नामेंट में सिर्फ 22 खिलाड़ियों ने लिया था हिस्सा

वर्ष 1877 में आज ही के दिन दुनिया की सबसे बड़ी टेनिस चैंपियनशिप विंबलडन की शुरुआत हुई थी। पहली बार 22 पुरुष खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। पहला खिताब 27 साल के स्पेंसर गोरे ने जीता था। दो बार विश्व युद्ध के चलते और पिछले वर्ष कोरोना की वजह से टूर्नामेंट नहीं हुआ था।



चार गुजराती और एक पारसी ने की थी बीएसई की स्थापना

वर्ष 1875 में आज ही के दिन बांबे स्टाक एक्सचेंज (बीएसई) की स्थापना हुई थी। चार गुजराती और एक पारसी ने इसकी शुरुआत की थी। ये सभी टाउन हाल के सामने पेड़ के नीचे व्यवसाय करते थे। बाद में दलाल स्ट्रीट पर आफिस खरीद लिया। छह हजार कंपनियां यहां पंजीकृत हैं।

बतौर कोरियोग्राफर गुरुदत्त ने शुरू किया था करियर

वर्ष 1925 में आज ही के दिन गुरुदत्त का जन्म कर्नाटक के दक्षिण कनारा जिले में हुआ था। उनका पूरा नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। 1946 में प्रभात स्टूडियो की फिल्म 'हम एक हैं' से कोरियोग्राफर के तौर पर उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। बतौर निर्देशक उन्होंने पहली फिल्म वर्ष 1951 में बाजी बनाई। उसके बाद प्यासा, कागज के फूल, साहब बीबी और गुलाम और चौदहवीं का चांद जैसी कई लोकप्रिय फिल्मों का निर्माण किया। 10 अक्टूबर, 1964 को उनका निधन हो गया। उनकी आखिरी फिल्म सांझ और सवेरा रही।



कीटों की दृष्टि प्रभावित कर रहा है प्रकाश प्रदूषण

नई दिल्ली, आइएसडब्ल्यू : रोशनी से चकाचौंध रहने वाले शहरों में प्रकाश प्रदूषण एक नई चुनौती बनकर उभरा है। इससे पारिस्थितिक तंत्र के साथ-साथ उसमें रहने वाले जीव-जंतुओं का जीवन प्रभावित हो रहा है। एक नए अध्ययन में पता चला है कि प्रकाश प्रदूषण के रंगों और इसकी तीव्रता में परिवर्तन के कारण पिछले कुछ दशकों के दौरान जीव-जंतुओं की दृष्टि पर जटिल और अप्रत्याशित प्रभाव पड़ रहे हैं। ब्रिटेन के एक्सेटर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया यह अध्ययन दुनियाभर में प्रकाश प्रदूषण के कारण बढ़ते पर्यावरणीय खतरों के प्रति सचेत करता है।

प्रकाश के प्रति कीटों में आकर्षण होना एक सुपरिचित घटना है, लेकिन कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था के उन प्रजातियों पर कहीं गहरे परिणाम हो सकते हैं, जिनका व्यवहार रात्रि के समय उनकी दृष्टि पर निर्भर करता है। इन प्रभावों का पता लगाने के लिए शोधकर्ताओं ने कीटों और उन्हें अपना शिकार बनाने वाले पक्षियों की दृष्टि पर 20 से अधिक प्रकार की रोशनी के प्रभाव की जांच की है।

नई चुनौती : प्रकाश के रंगों और तीव्रता में बदलाव के कारण जीव-जंतुओं की दृष्टि पर पड़ रहे हैं जटिल और अप्रत्याशित प्रभाव



एलिफेंट हाक मोथ। इमेजेज़ ब्रियोलेट

बचाव के लिए संवेदनशील होने की जरूरत

शोधकर्ताओं ने प्रकाश की मात्रा एवं तीव्रता को सीमित करने के सामान्य प्रयासों से आगे बढ़कर प्रकाश व्यवस्था के लिए संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाए जाने पर जोर दिया है। ब्रिटेन की नेचुरल एन्वायरमेंट रिसर्च काउंसिल की सहायता से किया गया यह अध्ययन शोध पत्रिका नेचर कम्युनिकेशन्स में प्रकाशित किया गया है।

अध्ययन में पाया गया कि एलिफेंट हाक मोथ नामक कीट की दृष्टि कुछ विशिष्ट प्रकार की रोशनी में बढ़ जाती है, जबकि प्रकाश के कुछ अन्य रूपों से इनकी दृष्टि बाधित होती है। वहीं, लगभग हर प्रकार की प्रकाश व्यवस्था में एलिफेंट हाक मोथ का शिकार करने वाले पक्षियों की दृष्टि में सुधार देखा गया है।

पूरी दुनिया में रात के समय में प्रकाश व्यवस्था का स्वरूप पिछले करीब 20 वर्षों के दौरान नाटकीय रूप से बदला है। एलईडी जैसे विविध प्रकार के आधुनिक रोशनी उपकरणों का चलन बढ़ा है। एक्सेटर विश्वविद्यालय के कार्नवाल कैंपस में स्थित पारिस्थितिकी एवं संरक्षण केंद्र से जुड़े शोधकर्ता डाक्टर जाल्यान ट्रासिअर्कों का कहना है कि आधुनिक ब्राड-स्पेक्ट्रम प्रकाश व्यवस्था इंसानों को रात में अधिक आसानी से रंगों को देखने में सक्षम बनाती है। हालांकि, यह जानना मुश्किल है कि ये आधुनिक प्रकाश स्रोत अन्य जीव-जंतुओं की दृष्टि को कैसे प्रभावित करते हैं।

अध्ययन में फूलों के रंगों को देखने की कीटों की क्षमता का आकलन करने के लिए कृत्रिम एवं प्राकृतिक प्रकाश के विभिन्न स्तरों में जीव-जंतुओं की दृष्टि से संबंधित माडलिंग का उपयोग किया गया है। इसी तरह, छद्म आवरण के माध्यम से अपनी उपस्थिति को छिपाकर रखने वाले कीटों को देखने की पक्षियों की दृष्टि क्षमता का भी आकलन किया गया है।

ऐसा होता है प्रभाव : मानव दृष्टि के लिए डिजाइन की गई कृत्रिम रोशनी में नीली और पराबैंगनी श्रेणियों का अभाव होता है, जो इन कीटों की रंगों को देखने की दृष्टि क्षमता के निर्धारण में अहम है। यह स्थिति कई परिस्थितियों में किसी भी रंग को देखने की कीटों की क्षमता को अवरुद्ध कर देती है। ऐसी स्थिति कीटों को शिकारियों से बचकर छिपे रहने के लिए अनुकूल नहीं होती है। फूलों को खोजना एवं परागण करना भी उनके लिए कठिन हो जाता है।



रेस्तरां में तब्दील हो रहा विमान

फलस्तीन के जुडवा भाई अताल्लाह और खामिस अल-सैराफी वेस्ट बैंक में बोइंग 707 विमान को रेस्तरां में परिवर्तित कर रहे हैं। इन्होंने इसका नाम फलस्तीन-जार्डन एयरलाइन रेस्तरां रखा है। इसे उत्तरी इजरायल के स्क्रैप कारोबारी से खरीदा गया है। लोगों के लिए इसे एक माह में खोल दिया जाएगा। यहां हुक्का पीने वालों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। इसके काकपिट में नवविवाहित जोड़ों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। एएफपी

इधर-उधर की

जब घोड़े को रेस्क्यू करने को हेलिकॉप्टर बुलाना पड़ा

कैलिफोर्निया, एजेंसी : इंसानी जिंदगी को बचाने के लिए तो हरसंभव प्रयास होते हैं, लेकिन ऐसा कम ही होता है जब किसी जानवर को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ा हो। दरअसल, अमेरिका के कैलिफोर्निया में कुछ दिनों पहले फार्म हाउस से एक घोड़ा भागकर खाई में गिरकर फंस गया। उसके मालिक की सूचना पर अग्निशमन विभाग ने घोड़े को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर बुलाया और उसे सुरक्षित निकाला। 'द आरेंज काउंटी फायर अथॉरिटी' ने अभियान का वीडियो ट्वीट किया है। एयरलिफ्ट करने से पहले घोड़े को बेहोश किया था। घोड़े का पशु चिकित्सालय में इलाज चल रहा है।



एयरलिफ्ट करने से पहले घोड़े को बेहोश किया गया। इंटरनेट मीडिया

नई दवा से दो माह में खत्म होगी टीबी

उपलब्धि ▸ नई दवा के मौजूदा दवाओं से चार गुना ज्यादा प्रभावी होने का दावा

नहीं करना होगा लंबा इंतजार, कम दवाई खाकर जल्द ठीक होगी टीबी

विवेक राव, मेरठ

तपेदिक या टीबी के उन्मूलन में इसके इलाज में लगने वाला लंबा समय एक बड़ा बाधक रहा है। कई लोग इस बीमारी से इसलिए मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि वे लंबे समय तक दवा की डोज लेने में जरूरी निरंतरता का पालन करने में चूक जाते हैं। इससे जहां उनकी बीमारी ठीक नहीं हो पाती है, वहीं रोगाणु दवाओं के प्रति ज्यादा प्रतिरोधी भी हो जाते हैं।

ऐसे हालात में 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने की दिशा में एक नई संभावना नजर आ रही है। मेरठ इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी (एमआइईटी) के फार्मेसी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डा. अनुराग ने टीबी की एक नई दवा तैयार की है, जो महज दो महीने में टीबी की बीमारी खत्म कर देगी। दावा है कि यह दवा वर्तमान डोज से चार गुना कारगर होगी। दुष्प्रभाव भी कम होगा। इस दवा का चूहे पर सफल ट्रायल किया गया है। अब क्लीनिकल ट्रायल के लिए फार्मा कंपनी से बात चल रही है।

टीबी एक संक्रामक बीमारी है, जिसमें माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरक्यूलोसिस फेफड़ों को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, लेकिन यह बीमारी मस्तिष्क, जिगर, मुंह, गुर्दे, गर्भाशय और हड्डियों में भी होती है। हर तरह की टीबी का इलाज तो उपलब्ध है, पर छह माह से लेकर दो साल तक दवा खानी पड़ती है। प्रोफेसर अनुराग ने तीन साल के शोध के बाद टीबी की नई दवा तैयार की है। यह टीबी के इलाज में उपयोग में होने वाली दवाइयों राइफैम्पीसिन, आइसोनियाजिड और स्ट्रेप्टोमाइसिन से चार गुना अधिक प्रभावी है।



एमआइईटी के फार्मेसी लैब में दवा का परीक्षण करते डा. अनुराग। जागरण

ऐसे अलग है यह दवा

डा. अनुराग के मुताबिक अभी जो टीबी की दवाएं हैं, उनमें ज्यादातर बैक्टीरिया की सेल लेयर को बढ़ने से रोकती है। जिसमें समय लगता है। जबकि यह दवा बैक्टीरिया के सभी माइक्रो एंजाइम को निष्क्रिय कर देगी। जिसकी वजह से टीबी जल्द ठीक होने लगेगी।

चूहों पर सफल परीक्षण : कालेज की फार्मेसी लैब में दवा तैयार करने के बाद अनुराग ने इसका चूहों पर सफल परीक्षण किया। एक स्वस्थ चूहे में टीबी के बैक्टीरिया को डाला गया। स्टैंडर्ड प्रोटोकाल के तहत 1.05 मिलीग्राम की डोज एक सप्ताह तक चूहे को दी गई। सप्ताहभर में ही चूहे के भीतर के बैक्टीरिया खत्म हो गए। उस पर कोई दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ा।

क्लिनिकल ट्रायल की तैयारी : डा. अनुराग के शोध का पेटेंट हो चुका है। इस दवा के क्लिनिकल ट्रायल के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल आफ इंडिया से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए संस्थान की एक फार्मा कंपनी से बात हुई है। बाजार में उपलब्ध टीबी की दवा से यह 50 फीसद सस्ती होगी। मरीज को अधिक समय और अधिक गोलियां भी नहीं खानी पड़ेंगी। दो से तीन गोली रोज ही पर्याप्त होंगी।

डांस करने से पार्किंसन जैसी बीमारियों में हो सकता है लाभ

अनुसंधान



डांस से रोगों का निदान। फाइल फोटो

डांस के कई तरीके आजकल प्रचलन में हैं, जो किसी व्यायाम से कम नहीं हैं। डांस करते समय व्यक्ति प्रसन्न मुद्रा में होता है और शारीरिक रूप से सक्रिय भी रहता है। अब एक नया अध्ययन सामने आया है कि डांस से पार्किंसन जैसे गंभीर रोगों में भी फायदा मिलता है।

'ब्रेन साइंस' जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में सामने आया है कि पार्किंसन के हल्के से लेकर मध्यम लक्षण वाले मरीज यदि सप्ताह में सवा घंटे भी डांस करते हैं, तो इस बीमारी के बढ़ने की गति को काफी हद तक धीमा किया जा सकता है। पार्किंसन तंत्रिका संबंधी रोग है। इसमें धीरे-धीरे शरीर में अकड़न, सक्रियता कम होना या कंपकंपाने जैसी दिक्कतें आने लगती हैं।

शोधकर्ता यार्क यूनिवर्सिटी के साइकोलाजी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर जोसेफ डिसूजा और करोलिना बियर्स ने बताया कि सप्ताह में बताई गई अवधि में डांस करने वालों में तंत्रिका संबंधी दिक्कतों में सुधार दिखाई दिया। साथ ही कंपकंपी की दिक्कत भी कम हुई। वहीं नहीं उनके भ्रमित होने, अवसाद और उदासी में भी कमी आई।

यह अध्ययन तीन साल तक नृत्य में भाग लेने और न लेने वाले मरीजों पर किया गया। जो नृत्य कर रहे थे, उनमें पार्किंसन के लक्षणों में सुधार दिखाई दिया। बीमारी बढ़ने की गति कम हो गई। करोलिना ने बताया कि नृत्य से सुनने, देखने और स्पर्श के साथ ही सामाजिक सामंजस्य की स्थिति बनती है। यह केवल व्यायाम से पूरी नहीं की जा सकती। -एएनआइ

स्क्रीन शॉट

लग रहा कि जैसे इंडस्ट्री में शुरुआत कर रही हूं : शिल्पा



14 वर्ष बाद फिल्म रिलीज होने को लेकर नर्वस हैं शिल्पा। इंस्टाग्राम

फिल्मों के सेट से लंबे वक्त तक दूर रहने के बाद कलाकारों के लिए दोबारा सेट पर आकर सहजता से काम करना आसान नहीं होता। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का अनुभव भी कुछ ऐसा ही रहा है, जो 23 जुलाई को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो रही अपनी फिल्म हंगामा 2 को लेकर काफी नर्वस हैं। दरअसल, साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म अपने के बाद उन्होंने अभिनय से दूरी बना ली थी। इतने वर्षों बाद अपनी फिल्म रिलीज होने को लेकर नर्वस शिल्पा ने एक लाइव चैट के दौरान कहा, 'मेरी इस फिल्म के प्रोड्यूसर रतन जैन वीनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स के मालिक हैं। खास बात है कि वीनस ने ही मुझे फिल्म इंडस्ट्री में लांच किया था। बाजीगर, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी और धड़कन जैसी कई फिल्में मैंने वीनस के अंतर्गत की है और सभी फिल्में हिट रही हैं। अब मुझे उम्मीद है कि हंगामा 2 भी मेरी और वीनस की सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट में जुड़ जाएगी। इतने वर्षों बाद अपनी फिल्म रिलीज को लेकर मैं थोड़ा नर्वस भी हूं। मैंने फिल्म इंडस्ट्री में इतना काम किया हुआ है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत कर रही हूं। फिल्म को लेकर मेरे दिल में बहुत हलचल हो रही है।' साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म हंगामा की सीक्वल हंगामा 2 में शिल्पा के अलावा मीजान जाफरी, परेश रावल, प्रनिता सुभाष और राजपाल यादव अहम भूमिकाओं में हैं।

इस बार टीवी से पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आएगा बिग बॉस

बदलते वक्त और डिजिटल प्लेटफॉर्म की बढ़ती लोकप्रियता का असर अब सिनेमा के बाद टेलीविजन पर भी दिखाई देने लगा है। सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्में थिएटर बंद होने की वजह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही हैं। उसी तरह अब टीवी से पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विवादास्पद रियलिटी शो बिग बॉस को लाने की तैयारी है। इसे बिग बॉस ओटीटी के नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म वूट पर प्रसारित किया जाएगा। इस शो को वूट प्लेटफॉर्म पर टीवी पर आने से छह हफ्ते पहले ही शुरू कर दिया जाएगा। छह महीने तक चलने वाले बिग बॉस ओटीटी शो को छह हफ्तों बाद टीवी पर प्रसारित या जाएगा। बताया जा रहा है कि बिग बॉस में शामिल होने वाले सितारों में कई सनसनीखेज नाम और जाने-माने चेहरे होंगे। बहुत सारा ड्रामा शो में नजर आने वाला है। आम जनता को इस बार कई पावर्स शो की तरफ से दिए गए हैं। आम जनता प्रतियोगियों को चुन सकती है, वह प्रतियोगियों को घर में बनाए रखने या बाहर करने में सक्षम होगी। जनता की नजर प्रतियोगियों द्वारा किए जाने वाले टास्क पर भी होगी। शो की स्ट्रीमिंग तारीख को लेकर कोई एलान फिलहाल नहीं किया गया है।

अगस्त से रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग शुरू करेंगे धर्मेंद्र

हाल ही में अभिनेता रणवीर सिंह की जन्मतिथि के मौके पर फिल्मकार करण जौहर ने रोमांटिक ड्रामा फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का एलान किया था। इस फिल्म में गली ब्वॉय के बाद जहां रणवीर और आलिया की जोड़ी एक बार फिर साथ दिखेगी, वहीं धर्मेंद्र, जया बच्चन और शबाना आजमी भी अहम भूमिकाओं में होंगे। एक इंटरव्यू के दौरान धर्मेंद्र ने बताया कि इस फिल्म में उनका किरदार रोमांटिक होगा। उन्होंने कहा, 'इस फिल्म से जुड़कर मैं खुश हूं। आपको पता है कि मैं कैमरे को प्यार करता हूं और कैमरा मुझे प्यार करता है। हम लोग एक-दूसरे को देखते रहते हैं। जब भी मौका मिल जाता है गले लग जाते हैं। इस फिल्म में मैं इस उम्र में भी रोमांटिक किरदार निभा रहा हूं। जैसा कि सब जानते हैं कि एक बार रोमांटिक तो हमेशा रोमांटिक।' धर्मेंद्र को एक्शन और दमदार डायलॉग्स के अलावा उनके अलहदा रोमांस के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने बताया कि वह अगस्त से इस फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। इस फिल्म के अलावा वह अपने पोते करण देओल के साथ फिल्म अपने 2 की भी शूटिंग शुरू करेंगे।



फिल्म में रोमांटिक किरदार निभा रहे हैं धर्मेंद्र। इंटरनेट मीडिया

लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता : श्वेता तिवारी

रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी का सीजन 11 कलर्स चैनल पर 17 जुलाई से शुरू होने वाला है। इस बार शो के प्रतियोगियों में टीवी अभिनेत्री श्वेता तिवारी भी शामिल हैं। इस शो से जुड़ने की वजहों, उनकी बेटी पलक के फिल्म 'रोजी- द सैफरन चैप्टर' से डेब्यू को लेकर हुई बातचीत :

सात सवाल



खतरों के खिलाड़ी के 11वें सीजन में दिखेंगी श्वेता तिवारी ● इंस्टाग्राम

● खतरों के खिलाड़ी 11 की शूटिंग केपटाउन में हुई है। वहां का माहौल यहां के मुकाबले कितना अलग था?

-माहौल एक ही जैसा था। वहां भी हर कोई कोरोना वायरस से डरा हुआ है। वहां पर भी बिना मास्क पहने नहीं घूम सकते हैं, हर जगह तापमान चेक किया जाता था। जिस दिन वापसी की फ्लाइट थी, उस दिन आधा दिन शॉपिंग के लिए मिला था, लेकिन बहुत ज्यादा जगहें वहां भी नहीं खुली नहीं थीं। हालांकि मन में एक शांति थी कि इस मुश्किल दौर में भी काम है।

● इतने वर्षों के अनुभव के बाद क्या काम न मिलने की इनसिक्योरिटी मन में होती है?

-मुझे लगता है कि यह इनसिक्योरिटी एक मुकाम तक पहुंचने के बाद ही होती है। पहले आप नाम बनाने के लिए हर तरह का काम कम पैसे में भी कर लेते हैं। जब नाम बन जाता है, तो उस मुकाम पर बने रहना सबसे मुश्किल हो जाता है। हमें अपनी लाइफस्टाइल, स्टेटस को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना होता है। कुछ बन जाने के बाद आप कोई भी या कम पैसों में काम करेंगे, तो लोग बातें बनाने लग जाते हैं।

● क्या आपको लोगों की बातों से फर्क पड़ता है?

-सच कहूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए, मैं हर तरह का काम कर रही हूं। आसपास मैंने कई कलाकार देखे हैं, जो पब्लिक में अपनी छवि को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं। खुलकर कुछ कहना नहीं चाहते हैं। अपनी छवि से बाहर निकलने से डरते हैं। मुझे जो भी काम रचनात्मक तौर पर संतुष्टि देता है मैं वह कर लेती हूं, लेकिन हां, एक लाइफस्टाइल है, जो मुझे अपने बच्चों को देनी है। उसके लिए काम करते रहना जरूरी है।

● कौन सी चीज है, जो डराती है?

-मैं भले ही बहादुर दिखती हूं, लेकिन मैं हूं नहीं। किचन में अगर कॉकरोच दिख जाए, तो मैं बेड पर चढ़कर चीखती हूं। मुझे बचपन से क्लॉस्ट्रोफोबिया (एक मनोरोग, जिसमें बंद या छोटी जगह में घुटन होती है) है। मुझे अंधेरे से भी डर लगता है। मेरे बच्चों को भी मेरी वजह से डरती हूं, आखिरकार वह कर ही लेती हूं। से अंधेरे में सोने की आदत नहीं रही है, लेकिन जीवन में जुझने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। शो में भी मैं डरते-डरते टास्क करती रही। ऐसा हमेशा से हुआ है कि जीवन में जिस चीज से डरती हूं, आखिरकार वह कर ही लेती हूं।

● आप खुद इतनी फिट हैं। आपकी बेटी पलक भी फिल्मों में कदम रख चुकी हैं। क्या वह आपको देखकर प्रेरित होती हैं?

-दरअसल, मुझे अपनी बेटी से प्रेरणा मिलती है। वह जब 18-19 साल की थीं, तब से उन्होंने अपनी फिटनेस पर काम करना शुरू कर दिया था। उन्हें पता था कि फिल्म इंडस्ट्री में जाने से पहले उन्हें फिट होना है।

● क्या अपनी बेटी के फिल्म में डेब्यू से आप नर्वस हैं?

-नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे उन पर बहुत गर्व है। कल को फिल्म चले या ना भी चले, फिर भी मुझे अपनी बेटी पर गर्व होगा। वह बहुत मेहनत कर रही हैं। बचपन से माता-पिता अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि मेहनत करते रहो। स्कूल में भी टीचर्स यही सिखाते हैं कि पहला नंबर आना जरूरी नहीं है, अपना बेस्ट करना जरूरी है। आगे क्या होता है देखेंगे।

● बेटी के फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने से बतौर मां आपकी चुनौतियां कितनी बढ़ गई हैं?

-वह फिल्मों में काम कर रही हैं। मैंने टेलीविजन इंडस्ट्री में काम किया है। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूं कि वहां किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं, कैसे शूटिंग होती है। मेरी बेटी सोचती है कि मैं सब संभाल लूंगी। जब मैं उन्हें कहती हूं कि मुझे फलां चीज का आइडिया नहीं, तो उन्हें लगता है कि मम्मी को आइडिया कैसे नहीं है। फिर उन्हें मैनेजर दे रखा है। मैं कहती हूं कि अपने मैनेजर से पूछो। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के काम करने के तरीकों में बहुत ज्यादा अंतर है। (प्रियंका सिंह)

फुर्सत के समय में घुड़सवारी सीख रहे हैं अली फजल

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद कई फिल्मकार अपने प्रोजेक्ट्स की शूटिंग शुरू कर चुके हैं, जबकि कई हालात के और ज्यादा सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कलाकार अपने इन फुर्सत के पलों का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करना चाहते हैं। फुकरे और प्रस्थानम फिल्म तथा मिर्जापुर वेब सीरीज के अभिनेता अली फजल इन दिनों अपने फुर्सत के पलों का उपयोग घुड़सवारी सीखने में कर रहे हैं। अली को स्कूल के दिनों से ही घुड़सवारी का शौक रहा है। उन्होंने लखनऊ में स्कूल में पढ़ते हुए भी थोड़ी बहुत घुड़सवारी सीखी थी। अभिनेता बनने के बाद अपने व्यस्त शेड्यूल के चलते वह इस शौक को आगे नहीं ले जा पाए। मौजूदा दौर में जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया। अपने इस शौक को लेकर दैनिक जागरण से बातचीत में अली ने कहा, 'मैंने अपने शौक और कौशल को बढ़ाने के लिए घुड़सवारी सीखना शुरू किया है। यह बहुत ही अनोखा अनुभव है। मैं बहुत पहले से ही घुड़सवारी सीखना चाहता था। घोड़े की पीठ से गिरकर दोबारा उठने का अनुभव सिर्फ एक घुड़सवार ही अच्छी तरह से बता सकता है। घुड़सवारी करते हुए, जब आप घोड़े की पीठ पर बैठते हैं तो आपके अंदर कई भावनाएं एक साथ उठती हैं। लिहाजा इसको सीखने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूं। (हंसते हुए) मैं उम्मीद करता हूं कि इस कौशल को मैं अच्छी तरह से सीख पाऊं और अपने कुछ घोड़ों को भी अपना दोस्त बनाऊं। इस दौरान हम कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी दिशानिर्देशों का पालन कर रहे हैं।' अली आगामी दिनों में फिल्म फुकरे 3 और हालीवुड फिल्म अ डेथ आन द नाइल में नजर आएंगे।



समय का सदुपयोग कर रहे हैं अली। सौ.- स्वयं की टीम

पेस और भूपति की जोड़ी पर वेब सीरीज बनाएंगे तिवारी दंपती

मेरी कॉम, भाग मिल्खा भाग, एम एस धौनी: द अनटोल्ड स्टोरी जैसी फिल्मों की सफलता के बाद इन दिनों फिल्मों के साथ-साथ खिलाड़ियों की जिंदगी पर वेब सीरीज बनाने का चलन भी जोरों पर है। अब दंगल फेम निर्देशक नितेश तिवारी और उनकी पत्नी अश्विनी अय्यर तिवारी भारत के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी रहे महेश भूपति और लिएंडर पेस की जोड़ी पर वेब सीरीज ब्रेक प्वाइंट बनाने की तैयारी में हैं। जी 5 के लिए बनाई जा रही इस वेब सीरीज में तिवारी दंपती दोनों खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, महत्वाकांक्षाओं और सफलता के साथ-साथ उनके बीच के मतभेद तथा उनके जीवन से जुड़े विवादों को भी दिखाएंगे। इस शो के बारे में नितेश और अश्विनी का कहना है, 'ब्रेक प्वाइंट देश के सबसे बड़े स्पोर्ट्स लीजेंड्स में शुमार लिएंडर पेस और महेश भूपति के आगे बढ़ने की इमोशनल कहानी है। यह उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के उतार-चढ़ाव की कहानी है। इस शो के जरिये हम दोनों खिलाड़ियों की कठिन मेहनत, विचार, महत्वाकांक्षाओं और चुनौतियों समेत उनके जीवन के तमाम यादगार पलों से एक बार फिर से रूबरू होंगे। इस कहानी को दर्शकों के बीच लाने के लिए हम दोनों बहुत उत्साहित हैं।' बता दें कि लिएंडर पेस और महेश भूपति की जोड़ी ने दो बार फ्रेंच ओपन और एक बार विंबलडन जैसी ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी अपने नाम की है। टेनिस की दुनिया में प्रति माने जाने वाले विंबलडन खिताब को जीतने वाली देश की पहली जोड़ी लिएंडर और महेश की ही थी। इसके अलावा इस जोड़ी ने कई अन्य प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में भी देश का नाम रोशन किया है। हालांकि अभी तक इस शो के कलाकारों के नाम सामने नहीं आए हैं।



नितेश और अश्विनी अय्यर तिवारी ने की घोषणा ● जी5 की पीआर टीम